



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 2011/ज्येष्ठ 16, 1933

No. 297]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 2011/JYAISTHA 16, 1933

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

( रक्षोपाय महानिदेशक का कार्यालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2011

**विषय :** भारत में एन 1, 3-डाइमिथाइल ब्यूटाइल-एन' फेनिलीन डायमाइन ( पीएक्स-13 जिसे 6 पीपीडी, वल्कॉनॉक्स 4020 आदि नामों से भी जाना जाता है ) के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच—अंतिम जांच परिणाम।

सा.का.नि. 433(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन ) नियम, 1997 को ध्यान में रखते हुए ।

**प्रक्रिया**

1. मै. एनओसीआईएल लि., सी-37, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, ठाणे-बेलापुर मार्ग, नवी मुम्बई-400705 द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन ) नियम, 1997 ( जिसे एतदपश्चात् " रक्षोपाय नियम " कहा गया है ) के नियम 5 के अंतर्गत यह आरोप लगाते हुए एन 1, 3-डाइमिथाइल ब्यूटाइल-एन' फेनिलीन डायमाइन ( पीएक्स-13 जिसे 6 पीपीडी, वल्कॉनॉक्स 4020 आदि नामों से भी जाना जाता है ) पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि एन 1, 3-डाइमिथाइल ब्यूटाइल-एन' फेनिलीन डायमाइन ( पीएक्स-13 जिसे 6 पीपीडी, वल्कॉनॉक्स 4020 आदि नामों से भी जाना जाता है ) के बढ़े हुए आयातों से भारत में एन 1, 3-डाइमिथाइल ब्यूटाइल-एन' फेनिलीन डायमाइन ( पीएक्स-13 जिसे 6 पीपीडी, वल्कॉनॉक्स 4020 आदि नामों से भी जाना जाता है ) के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही थी और/या उसका खतरा था। इस बात से संतुष्ट होने पर कि नियम 5 की अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं, दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 की जांच शुरुआत अधिसूचना जिसे उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के जरिए एन 1, 3-डाइमिथाइल ब्यूटाइल-एन' फेनिलीन डायमाइन ( पीएक्स-13 जिसे 6 पीपीडी, वल्कॉनॉक्स 4020 आदि नामों से भी जाना जाता है ) के आयातों के विरुद्ध जांच शुरू की गई थी।
2. नई दिल्ली में उनके दूतावासों के जरिए प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को अधिसूचना की प्रति भेजी गई थी। जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रति नीचे दिए गए सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी :—

## 3. घरेलू उत्पादक

क्र.सं.	इकाई का नाम	फैक्ट्री का पता
1.	एनओसीआईएल लि०	सी-37, टी.टी.सी. इन्डस्ट्री क्षेत्र, ऑफ थाने बेतापुर रोड़, नवी मुम्बई-400705 फोन नं. 022-2767/2735/2789 फैक्स: 022-2767/1865 ई-मेल: gadgilrm@nicilindia.com
2.	पीएमसी रबड़ कैमिकल्स इंडिया प्रा.लि.	103 जीटी रोड़ पश्चिम पीओ रीशरा 712248, जिला-हुगली पश्चिम बंगाल, भारत
3.	लेनसैक्स इंडिया प्रा.लि.	कॉलशैट रोड़, थाने-400607, महाराष्ट्र इंडिया
4.	मर्चेम लि०	ग्रोव सेंटर, 44 डेवलपमेंट प्लाट, कलामैस्सरी, कोचीन-683109, केरल, इंडिया

## 4. आयातक

- क. जे.के. इंडस्ट्रीज लि०, 7, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001  
 ख. सिएट लि०, 463, डॉ० एन्नी बैसेंट रोड़, वर्ली, मुम्बई-400030  
 ग. अर्पोलो टायर्स लि०, छठा तल, चेरुपुष्पम बिल्डिंग, शन्मुघम रोड़, कोच्चि-682031, केरल  
 घ. बिरला टायर्स, द्वारा केसोशम इंडस्ट्रीज लि०, 8 वाँ तल, 9/1, आर.एन. मुखर्जी रोड़, कोलकाता-700001  
 ङ. एमआरएफ लि०, 126, ग्रीम्स रोड़, चेन्नई-600006  
 च. पेट्रो टायर्स लि०, बी-27, फोकल पाईट, लुधियाना-141010,  
 छ. योद्धा टायर्स लि०, योद्धा नगर, जीटी रोड़, जुगियाना, लुधियाना-141010  
 ज. रायसन इंडस्ट्रीज लि०, 14, 3 पलमोहन अपार्टमेंट, पंजाबी बाग पश्चिम, नई दिल्ली-110026  
 झ. रबड़ प्रोडक्ट्स लि०, वागी एस्टेट, नियर प्रेसीटेक्स, ठाणे-400601  
 ञ. पुनीत रेजिन्स लि०, 84 अटलांटा, नरीमन पाईट, मुम्बई-21  
 त. ऋषिरूप पॉलीमर्स प्रा.लि., 65 अटलांटा, नरीमन पाईट, मुम्बई-21  
 थ. ऑटोमोटिव टायर्स मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन, पीएचडी हाऊस (चौथा तल), एशियन गेम्स विलेज के सामने, सीरी फोर्ट इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016

द. अखिल भारतीय रबड़ उद्योग एसोसिएशन, 1009, पद्म टावर्स-1, 5, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

### निर्यातक

- क. सॉल्यूशिया इंक, सेंट लुइस, मिसौरी, यूएसए (विश्व हैडक्वार्टर्स) 575 मैरीविले सेंटर ड्राइव, सेंट लुइस, मिसौरी 63141, यूएसए
- ख. लैक्सेस एनवी, 51369, लिवरकुसेन, जर्मनी
- ग. दुसियो, ए.एस. एडमिनिस्ट्रेटिवा बुडोवा इवी, सी.1236, 927, क्यू 3 साफा, स्लोवाक रिपब्लिक
- घ. जिगासु साइनॉर्गकेम टेक्नोलॉजी कं. लि., शंघाई ऑपरेशन सेंटर, जिगासु साइनॉर्गकेम टेक्नोलॉजी कं.लि., 22एफ, योंगडा इंटरनेशनल टॉवर, सं. 2277, लांगयांग रोड, पुडोंग न्यू एरिया, शंघाई, चीन जन. गण.
- ण. कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं.लि., 21-24एफ कुम्हो एशियाना मेन टॉवर # 115, सिनमुनो 1-जीए, जॉंगनो-सीयू, सिओल 110-857, कोरिया
- त. फ्लेक्सिस एसए/एनवी (सोल्यूशिया इंक का हिस्सा), पार्क साईटिफिक-फ्लेमिंग, र्यू लेड ब्रुनायत 3, लॉवियन-ला-नॉव, 1348, बेल्जियम
- थ. नान्जिंग केमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नं 560, हेयेन रोड, नान्जिंग, जिगासु प्रोविन्स, चीन-210038
- द. शॉंग्यु लिक्सिंग केमिकल्स कं.लि., शॉंग्यु फाइन केमिकल जोन 5 आरडी, झेजियांग, चीन पी.सी.312369
- ध. नॉर्थ ईस्ट ऑक्जिलियरी केमिकल्स इंडस्ट्री कं.लि., वुकियांग इंडस्ट्री पार्क, हेबेई, चीन
- न. यूनाइटेड रबड़ केमिकल कॉर्प. कार्यालय पता: सुइट 1505 बिल्डिंग ए, नाक्सिंगकैंग इंटरनेशनल टावर, 22, डॉंगसिशिटियाओ, डॉंगचेंग जिला, बीजिंग, चीन 100007
- प. दि ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लि. ऑफ टॉंगलिंग केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप, पता: सं. 1269 जिनलिंगडाओ, टॉंगलिंग सिटी एन्हुई प्रोविंस, चीन, पोस्ट कोड-244003

### 5. निर्यातक देश

- (i) यूरोपीय संघ
- (ii) जर्मनी
- (iii) चेक गणराज्य
- (iv) बेल्जियम
- (v) चीन जन.गण.
- (vi) कोरिया गणराज्य
- (vii) मिस्र अरब गणराज्य
- (viii) यूएसए

6. सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों, आयातकों एवं निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी गई थी और उनसे 30 दिनों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का कहा गया था ।

7. निम्नलिखित पक्षकारों/निर्यातक देशों से उन्हें हितबद्ध पक्षकार माने जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए थे और सभी अनुरोधों को स्वीकार किया गया था:-
  - (i) मै0 पुनीत रेजिस लि0, मुम्बई
  - (ii) मै0 ऋषि पॉलिमर्स, मुम्बई
  - (iii) मै0 सॉल्यूशिया इंक, यूएसए
  - (iv) श्री अब्देलरहमान फौजी, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय, मिस्र
8. निम्नलिखित पक्षकारों द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय-विस्तार हेतु अनुरोध किया गया था:-
  - (i) मै0 जियांग्सु सिनॉर्गकैम टेक्नोलॉजी कं0. लि., चीन जन.गण.
  - (ii) मै0 कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स, कोरिया
  - (iii) ऑटोमोटिव टायर मेन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन, नई दिल्ली
9. निर्धारित समयावधि के भीतर जाँच पूरी करने के लिए समय-सीमा पर विचार करते हुए रक्षोपाय नियमों के नियम 6(4) के अनुसार किए गए अनुरोध के अनुरूप उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय विस्तार के लिए अनुरोध को स्वीकार किया गया था और संबंधित पक्षकारों को तदनुसार सूचित किया गया था ।
10. घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों के मौके पर दौरे तथा आवश्यक समझी गई सीमा तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रिकॉर्डों के जरिए आवेदक अर्थात् मै0 एनओसीआईएल द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया गया था । आवेदकों ने कार्यरत लागत लेखाकार द्वारा सत्यापित एवं विधिवत प्रमाणित लागत संबंधी आँकड़े प्रस्तुत किए थे । सत्यापित रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में रखा गया है ।
11. आवेदक तथा हितबद्ध पक्षकारों के सभी लिखित अभ्यावेदन रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं । प्राप्त अथवा हासिल की गई अगोपनीय सूचना सार्वजनिक फाइल में रखी गई है ।
12. दिनांक 21.02.2011 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी जिसकी सूचना 28 जनवरी, 2011 को भेजी गई थी । सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियम, 1997 के नियम 6 के उप नियम (6) के अनुसार मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारों का लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन की प्रति सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी । हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अभ्यावेदनों पर विरोध, यदि कोई हो, दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया था ।
13. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक से "घरेलू उत्पादकों के लिए प्रश्नावली" प्रपत्र में आँकड़ों हेतु अनुरोध किया था । उसे संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया गया था और सार्वजनिक



फाइल में भी रखा गया था। हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक के उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए वांछित अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया था।

14. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सभी अभ्यावेदन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए थे और सार्वजनिक फाइल में रखे गए थे। हितबद्ध पक्षकारों को इन अभ्यावेदनों पर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। जाँच की प्रक्रिया के दौरान आयात के अतिरिक्त आँकड़े सार्वजनिक फाइल में रखे गए थे। अतिरिक्त आँकड़ों को जोड़ने के बाद संवर्धित आयात तथा बाजार आकार, कुल घरेलू माँग में आयात का हिस्सा आदि जैसे अन्य आर्थिक मापदंडों पर आवेदक के अभ्यावेदन भी उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए थे और सार्वजनिक फाइल में रखे गए थे।
15. लिखित अभ्यावेदनों में या खण्डों में हितबद्ध पक्षकारों तथा अन्य घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सभी विचारों एवं घरेलू उद्योग के अभ्यावेदनों पर प्रतिक्रियाओं की जाँच की गई थी और उपयुक्त निर्धारण करने के लिए उन पर विचार किया गया है। चूँकि बड़ी संख्या में हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं, अतः संक्षिप्तता के लिए हितबद्ध पक्षकार का विशिष्ट रूप से नाम लिए बिना उनके विरोधों तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर उपयुक्त स्थलों पर विचार किया गया है।

### घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

#### आवेदक

16. वह उत्पाद जिस पर रक्षोपाय शुल्क के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, रबड़ रसायन पीएक्स-13 या 6 पीपीडी है जिसका व्यापक उपयोग प्राकृतिक रबड़, कृत्रिम रबड़ (एसबीआर, ब्यूटाडीन रबड़, नाइट्राइल रबड़ तथा कॉर्बोक्सिलेटेड रबड़) एवं अन्य कृत्रिम रबड़ आधारित यौगिकों के संसाधन में होता है, जिनका प्रयोग विभिन्न रबड़ उत्पादों के विनिर्माण में होता है।
17. वस्तु के तीन और उत्पादक हैं परंतु उत्पादन में मै0 एनओसीआईएल का हिस्सा 50% से अधिक है और इसलिए वे प्रमुख उत्पादक हैं।
18. लम्बी अवधि से भारतीय बाजार में उत्पाद का आयात हो रहा है और विभिन्न स्रोतों से इसके पाटन का पुराना इतिहास है। पाटन संबंधी मामलों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

विवरण	मामला 1	मामला 2
शामिल देश	ताईवान और ईयू	चीन तथा कोरिया
जांच शुरुआत	अगस्त, 2004	जुलाई, 2007
जांच अवधि	जनवरी, 03-दिसम्बर, 03	अप्रैल-2006, मार्च, 2007
अंतरिम शुल्क	8 अप्रैल, 2005	28 फरवरी, 2008
सीमाशुल्क	7 जुलाई, 2005	5 मई, 2008
निश्चयात्मक शुल्क	16 अगस्त, 2005	1 अक्टूबर, 2008

सीमाशुल्क	7 जुलाई, 2005	12 दिसम्बर, 2008
लगाया गया शुल्क	ईयू 816-840 अम.डॉ. प्रति मी. टन	कोरिया 10.35 रूपए प्रति किग्रा.
समीक्षा	मई, 2010 (एसएसआर)	अगस्त, 2010 (एमटीआर)
जाँच अवधि	अप्रैल, 09 से मार्च, 10	अप्रैल, 09 से मार्च, 10

19. आवेदक द्वारा इस तर्क के साथ 2000-01 से 2010-11 (दिसम्बर, 2010) तक के आयात एवं क्षति संबंधी आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि वर्ष 2003 से उत्पाद का पाटन किया जा रहा है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें अन्य सदस्य देशों के जाँचकर्ता प्राधिकरणों ने क्षति विश्लेषण के लिए लम्बी समयावधि ली है और विभिन्न मामले तथा इन जाँचों में विचार किए गए वर्षों को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त रक्षोपाय करार में जाँच अवधि के संबंध में कोई विशेष बाध्यता नहीं है और इसका निर्णय जाँचकर्ता प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ा गया है जो यूएस-लाइन पाइप मामले के संगत है।
20. आवेदक ने दावा किया कि हाल के वर्षों में आयात में 'वृद्धि' हुई है परंतु अनिवार्यतः उसी दर से जाँच की अवधि के अंत तक वृद्धि नहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि विरोधियों द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार हाल के वर्षों के आँकड़ों पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है। साथ ही वर्तमान मामले में आयात में वृद्धि का निर्धारण मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के आलोक में किया जाना है। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के आयात में अचानक, तीव्र और अत्यधिक वृद्धि हुई है।
21. चीन तथा कोरिया से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण वर्ष 2008-09 में आयातों में गिरावट आई थी। यह गिरावट अस्थायी प्रकृति की थी और बाद के वर्षों में आयात में उच्चतर गति से पुनः वृद्धि शुरू हो गई थी।
22. दो महत्वपूर्ण अपूर्वानुमेय घटनाक्रम हुए जिससे आयातों में वृद्धि हुई। वे हैं (क) केकेपीसी तथा साइनॉर्गकेम के बीच विशेष संबंध तथा (ख) वैश्विक बाजार में मंदी जिसके परिणामस्वरूप विकसित देशों और चीन में उत्पाद की माँग में अत्यधिक गिरावट आई।
23. कोरिया पेट्रोकेमिकल्स (केकेपीसी) कोरिया में 6 पीपीडी का एकमात्र उत्पादक है। 6 पीपीडी के उत्पादन के लिए 6 पीपीडी हेतु उपान्तिम चरण मध्यवर्ती के रूप में 4-एडीपीए अपेक्षित होता है। केकेपीसी के पास 4-एडीपीए के उत्पादन हेतु अपनी सुविधा नहीं है। साइनॉर्गकेम चीन में रबड़ रसायनों का एक उत्पादक है जो केवल 6 पीपीडी तथा 4-एडीपीए के उत्पादन में संलग्न है। यह कम्पनी एक अग्रणी वैश्विक उत्पादक (फ्लेक्सिस) द्वारा पेटेंटकृत उत्पादन प्रौद्योगिकी के उल्लंघन एवं प्रयोग हेतु अमेरिका में पेटेंट संबंधी मुद्दों पर एक बड़े कानूनी विवाद में शामिल है। वृहद अमेरिकी बाजार में बिक्री न कर पाने पर साइनॉर्गकेम ने वैकल्पिक बाजार नीतियाँ तैयार की हैं। इसी दिशा में साइनॉर्गकेम ने केकेपीसी के साथ कुछ व्यवस्था की है जिसमें साइनॉर्गकेम 4-एडीपीए का उत्पादन कर केकेपीसी को उसकी आपूर्ति करेगा तथा केकेपीसी 6 पीपीडी का उत्पादन कर उसकी आपूर्ति वैश्विक रूप से साइनॉर्गकेम तथा केकेपीसी के मौजूदा

एवं नए बाजारों को करेगा। इस विशेष संबंध का उल्लेख वर्ष 2008-09 के लिए केकेपीसी की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया गया है। साइनॉर्गकेम द्वारा सब्सिडीशुदा कीमतों पर केकेपीसी को 4-एडीपीए की बिक्री की जा रही है। वह कीमत जिस पर साइनॉर्गकेम ने भारतीय बाजार में 4-एडीपीए की बिक्री की है, केकेपीसी को बिक्री की कीमत से अधिक है। 6पीपीडी का कोरियाई बाजार लगभग 7000-8000 मी. टन था। कोरियाई बाजार की माँग का लगभग 50% आयात से पूरा किया जा रहा है। अतः केकेपीसी द्वारा लगभग 4000 मी. टन घरेलू माँग की पूर्ति की जाती है। मौजूदा क्षमता के इससे बहुत अधिक होने के बावजूद कम्पनी ने आगे और अधिक विस्तार केवल दोनों पक्षों के बीच संबंधों के कारण तथा अन्य वैश्विक उत्पादकों को बाजार से बाहर रखने के लिए किया।

24. यह विशेष संबंध कोरियाई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क के बावजूद अत्यधिक कीमत अंतर का कारण है।
25. वर्तमान वैश्विक मंदी का परिणाम प्रमुख बाजारों (जिसमें चीन, यूरोप और अमेरिका शामिल हैं) में उत्पाद की माँग में अत्यधिक गिरावट के रूप में हुआ। वैश्विक मंदी समाप्त होने के बाद भी टायरों के विश्व बाजार में मंदी है जबकि भारतीय बाजार बहुत मजबूत है। टायर उद्योग और उसकी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित सूचना माँग/खपत में वृद्धि का स्पष्ट संकेतक है। परिणामस्वरूप अधिकाधिक विदेशी उत्पादक भारतीय बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि यूरोप तथा ईयू बाजारों में टायरों के निर्यात में गिरावट आई है और परिणामस्वरूप यूरोप को निर्यात करने वाले तीसरे देशों में पीएक्स-13 की खपत में गिरावट आई है जिससे उत्पादकों की वस्तु सूची में वृद्धि हुई है। अतः उन्हें उपलब्ध एकमात्र विकल्प मंदी से कम प्रभावित बाजारों में अपने निर्यातों में वृद्धि करना था। ऐसा ही बाजार होने के कारण भारत को लक्ष्य किया गया और भारी मात्रा में आयात में वृद्धि की गई।
26. कोरिया से आयातों पर लागू शुल्क में मौजूद वृद्धि तथा वर्तमान समीक्षा के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मध्यावधि समीक्षा में निर्धारित किया जाने वाला संशोधित पाटनरोधी शुल्क भी जाँच की वर्तमान अवधि में क्षति मार्जिन से बहुत कम होगा। अतः घरेलू उद्योग ने केवल अपूरित क्षति की सीमा तक रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु अनुरोध करते हुए वर्तमान रक्षोपाय याचिका दायर की है। वस्तुतः घरेलू उद्योग इस स्थिति के प्रति सचेत था कि वह एक ही क्षति के लिए दोहरे उपचार हेतु पात्र नहीं है और उपर्युक्त स्थिति का समाधान करने के लिए घरेलू उद्योग ने स्वयं ही महानिदेशक (रक्षोपाय) को यह स्पष्ट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के परिणामस्वरूप अपूरित क्षति की सीमा तक ही रक्षोपाय शुल्क की माँग की जा रही है।
27. याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि इस उत्पाद पीएक्स-13 के लिए अपेक्षित उपांतिम मध्यवर्ती 4 एडीपीए है। कोरियाई विनिर्माता द्वारा अपेक्षित 4 एडीपीए चीन से प्राप्त किया जाता है जो पाटनरोधी प्राधिकरणों द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त चीन सरकार द्वारा अपने घरेलू उद्योग को निर्यात कर छूट, कमजोर मुद्रा (आरएमबी) आदि जैसे विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। यह नोट किया जाए कि

उसी उत्पाद पीएक्स 13 के लिए चीनी स्रोत पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क 42.70 रुपए प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है जबकि कोरिया के लिए यह 10.35 रुपए प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है। इस मामले में मुख्य अंतर कोरिया को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किए जाने के कारण है जबकि उसकी प्रमुख निविष्टि 4 एडीपीए चीन से प्राप्त की जा रही है और 4 एडीपीए से पीएक्स 13 तक मूल्यवर्धन बहुत अधिक है।

28. भारत में कॉस्टिक सोडा के हालिया मामले में महानिदेशक ने पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क के अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया और पाटनरोधी शुल्क के साथ रक्षोपाय शुल्क लगाया। अतः यह कहना गलत है कि दोनों शुल्क नहीं लगाए जा सकते हैं।
29. याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान याचिका दायर करने के लिए घरेलू उद्योग के पास कानूनी औचित्य है। डब्ल्यूटीओ कानूनों में भी इसकी अनुमति है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दोहरे उपचार के संबंध में चीन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यूरोपीय संघ के उत्तर (जी/एसजी/क्यू2/ईईसी/4) का संदर्भ दिया गया है और उस पर विश्वास किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

- ईयू को पाटनरोधी एवं सब्सिडीरोधी कार्यवाही के साथ-साथ रक्षोपाय जांच हेतु अनुरोध प्राप्त हुए थे। तीनों मामलों में मामलों की शुरुआत हेतु अपेक्षित शर्तें पूरी होती थीं। वस्तुतः जहां तक रक्षोपाय जांच का संबंध है, रक्षोपाय हेतु अपने अनुरोध में बेल्जियम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण से यह संकेत मिला था कि आयात में अचानक, हालिया और तीव्र वृद्धि हुई थी तथा इस वृद्धि से गंभीर क्षति हुई थी।

30. याचिकाकर्ता ने केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित वस्तुपरक सूचना यतः क्षमता, उत्पादन, बिक्री मात्रा (घरेलू एवं निर्यात), वस्तु सूची, लागत, कीमत, लाभ/हानि, बाजार हिस्सा आदि के संबंध में रक्षोपाय नियम 1997 के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने ऐसी किसी भी सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा नहीं किया है जो वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है या जिसे याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के संबंध में वास्तविक सूचना के प्रकटन से उत्पाद का भावी व्यवसाय प्रभावित होगा। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क के परिणामस्वरूप किसी सूचना को प्रकट किए जाने के निहितार्थ हैं - पहला, इस मामले में केवल एक याचिकाकर्ता है, जिसका तात्पर्य यह होगा कि सभी पक्षकारों को उस कम्पनी के बारे में वास्तविक सूचना प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, भारत में तीन और कम्पनियाँ हैं जो भारतीय बाजार में एक-दूसरे और घरेलू उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं तथा अपनी भावी व्यवसाय नीति तैयार करने के लिए दूसरी कम्पनी की गोपनीय व्यवसायिक जानकारी प्राप्त करने का पूरा प्रयास करती हैं। ऐसी सूचना के प्रकट होते ही ये सभी कम्पनियाँ दूसरी कम्पनी के बारे में मिनटों में सूचना प्राप्त कर सकती हैं - जिसे वे लम्बी अवधि से प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं और जिसके लिए उन्होंने काफी व्यय भी किया होगा परंतु अभी भी उससे

अनभिज्ञ हैं। तीसरा, जैसे ही सूचना प्रकट की जाएगी, प्रत्येक उपभोक्ता को यह जानकारी मिल जाएगी कि पूर्व में उनकी प्रापण कीमत क्या रही थी अर्थात् क्या वे उनके प्रतिस्पर्धियों जो उसी स्रोत से क्रय कर रहे थे, की तुलना में अधिक या कम अथवा उपयुक्त कीमत दे रहे थे (जिससे प्रतिस्पर्धा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा)। चौथा, उपभोक्ताओं को उनके आपूर्तिकर्ताओं की लागत संरचना की तुलना में अपनी कीमत का पता चल जाएगा जिससे इन पक्षकारों के बीच भावी कीमत वार्ताओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। पाँचवाँ, विदेशी उत्पादकों को अधिकांश भारतीय उत्पादकों के बारे में ऐसी जबरदस्त व्यावसायिक सूचना मिल जाएगी कि वे भारतीय उत्पादकों को हटाने के लिए स्पष्ट योजनाएं तैयार कर सकेंगे (जोकि मूल आशय है)। भारत में संयंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे संभावित भारतीय उत्पादक जिसे मौजूदा उत्पादकों के वास्तविक मौजूदा निष्पादन के बारे में कोई निश्चयात्मक जानकारी नहीं है, के लिए ऐसी सूचना एक स्वर्णिम अवसर होगी। छठा, उपभोक्ता अनुषंगी उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और दूसरे क्रोताओं के लिए कीमत निर्धारण उनके लिए सबसे बड़ी व्यावसायिक सूचना है। यदि ऐसा होता है तो उपभोक्ता को अपने प्रतिस्पर्धी जो अन्यथा उनमें से एक उत्पाद का उत्पादक है, के संबंध में तुरंत आश्चर्यजनक व्यापार सूचना प्राप्त होगी।

31. याचिकाकर्ता का दावा है कि रक्षोपाय महानिदेशालय में पुराने मामले ऐसी गोपनीयता रहित थे क्योंकि आवेदकों की संख्या अधिक थी और याचिका में दी गई सूचना पहले से ही सार्वजनिक रूप से अर्थात् आवेदक की कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में थी। वर्तमान मामला रबड़ रसायन उद्योग के रूप में गोपनीयता को उचित ठहराता है, उक्त व्यापार में किसी भी पक्ष ने कभी भी उत्पादवार स्थापित क्षमता-उत्पादन, बिक्री मात्रा इत्यादि का खुलासा नहीं किया है। इसके बावजूद यदि कोई भारतीय प्रतिस्पर्धियों के तुलन पत्र (वार्षिक रिपोर्ट) को देखता है तो वह व्यक्तिगत उत्पादवार क्षमताओं, बिक्री मात्रा, उत्पादन इत्यादि का कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं कर सकता है। चीन सन साइन अथवा लैनक्सेस या सोलुटिया इंक जैसी कंपनी भी उत्पादनवार क्षमता, बिक्री मात्रा इत्यादि को प्राप्त नहीं कर सकती है। लैनक्सेस, सोलुटिया इंक के मामले में रबड़ रसायन अन्य व्यापार के साथ मिला दिया गया है। के के पी सी रबड़ रसायन भी अन्य व्यापार के साथ मिला दिया गया है।

32. याचिकाकर्ता ने तीन पूरी हो चुकी जांचों और तीन जारी जांचों में भागीदारी की। याचिकाकर्ता ने अपने पाटनरोधी याचिकाओं में इन सूचनाओं में से किसी को प्रकट नहीं किया। याचिकाकर्ता का ऐसा दावा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकार/प्राप्त किया गया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत रक्षोपाय याचिका में अब इस सूचना का प्रकटन करने से पाटनरोधी निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिकूलतः प्रभावित करेगा।

33. प्रारम्भ में समायोजन योजना के संबंध में याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि कोरिया-डेयरी संबंधी पैनल ने उस विचार को अस्वीकार किया है जिसमें अनुच्छेद 5.1 के अंतर्गत समायोजन योजना को शामिल करने को लागू किया गया था।

34. भारतीय उत्पादकों ने समायोजन योजना बनाई है जिसका उद्देश्य क) लागत में कमी करना ख) मौजूदा उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग करना ग) बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता विस्तार करना है ।

35. याचिकाकर्ता उद्योग अर्थात् एन ओ सी आई एल दाहेज में दूसरी विनिर्माण सुविधा स्थापित कर रही है जिसमें कंपनी का 247 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय पर पी एक्स-13 के 14,000 मी.टन उत्पादन करने का विचार है । दिनांक 30 अप्रैल, 2011 के अनुसार 90.48 करोड़ रुपए की कुल वचनबद्धता है और दिनांक 30.4.2011 तक 45.96 करोड़ रुपए की राशि पहले ही खर्च हो चुकी है । परियोजना को मार्च, 2012 से और अप्रैल 2012 से उत्पादन शुरू किया जाना है । किए गए कार्य एवं किए जाने वाले कार्य का ब्यौरे के साथ चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाण पत्र में प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह प्रमाणित है कि अप्रैल 2012 से उत्पादन शुरू किया जाना संभव है । व्यय का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला लागत लेखाकार से भी एक प्रमाण पत्र पहले ही मिल गया है और उसे प्रस्तुत कर दिया गया है ।

36. निर्यातकों के मुकाबले पी एक्स - 13 के आयात और मांग में संभावित वृद्धि तथा अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ उत्पादन क्षमता को हिसाब में लेने के पश्चात देश में पी एक्स - 13 की वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए विस्तारित क्षमता पर्याप्त होगी ।

37. विस्तार से कंपनी को 30 रुपए प्रति किग्रा की न्यूनतम लागत बचत होगी । आवेदक ने इसके समर्थन में लागत लेखा पद्धति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है । इसके अलावा, याचिकाकर्ता को विश्वास है कि जब वह एक बार बाजार में अधिक सामान बेचने में समर्थ हो जाएगा तब अतिरिक्त लागत के खाते में लागत कमी आएगी ।

38. इसके आगे इस विस्तारण से कंपनी आयातों से उचित प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ होगी । याचिकाकर्ता ने तीन वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध किया है ताकि वह आयात प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की स्थिति में हो ।

39. समायोजन योजना की पूर्ण रूप से प्रचालन करने की आवश्यकता नहीं है जब रक्षोपाय शुल्क लगाए गए हों । घरेलू उद्योग को इस प्रकार की समायोजन योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिससे यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग को सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने में मदद मिलेगी ।

40. यह तर्क देना संगत होगा कि भारतीय उत्पादकों में एक मै0 लेक्सनेस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसके पास भारत और भारत से बाहर उत्पादन सुविधाएं हैं । याचिकाकर्ता ने बताया है कि मै0 लेक्सनेस ने अस्थायी तौर पर अपना उत्पादन स्थगित किया है और इसने अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से बाहर की उत्पादन सुविधाओं से सामग्री की आपूर्ति की है । यदि उत्पादन स्थगित नहीं किया गया तो कंपनी घरेलू रूप से संबद्ध वस्तु की समान मात्रा का उत्पादन कर रही होगी । उक्त प्रबंधन में स्थायित्व की अनुपस्थिति के मद्देनजर आयातों को छोड़ दिया गया है क्योंकि इन्हें जोड़ने से आंकड़ों में अन्यथा विकृति आएगी ।

41. उक्त विनिर्माण मै0 लेक्सनेस ने उत्पादन शुरू कर दिया है जो उनके द्वारा 4 ए डी पी ए के आयात से स्पष्ट होता है। जे एन पी टी, न्हावाशेवा में 4 ए डी पी ए के आयात आंकड़े उक्त दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए हैं।

42. याचिकाकर्ता ने सूचित किया है कि आई सी डी लुधियाना तथा कोचीन पत्तन के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के औसत आयात वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के आयात अंकों में जोड़ा गया है क्योंकि यह उपलब्ध नहीं थे। मौखिक सुनवाई के समय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इनके औचित्य पर कोई विवाद नहीं उठाया था। याचिकाकर्ता ने बताया है कि यह आयात संगत अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयात मालूम करने के उद्देश्य से जोड़ने की आवश्यकता है।

43. मौखिक सुनवाई के समय यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने मै0 लेनसेक्स द्वारा गए आयातों को छोड़ते हुए बढ़े हुए आयात प्रदर्शित किए हैं और इन आयातों को छोड़ने की कोई न्यायसंगतता नहीं है। आगे तर्क दिया गया है कि एक बार जब यह आयात छोड़े गए हैं आयातों में गिरावट प्रदर्शित हुई है। हितबद्ध पक्षकारों ने आयातों में गिरावट प्रदर्शित होने वाला ग्राफ भी प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि यह प्रस्तुतियां तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि आयात में वृद्धि हुई है चाहे कुल आयात से लेनसेक्स के आंकड़े जोड़े जाए या हटाए जाएं।

44. उत्पादन के संबंध में वर्ष 2000-01 से 2010-11 की पूरी अवधि में आयातों में वृद्धि हुई। आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा तेजी से घटा है जबकि आयात में अधिक व तेज वृद्धि दर्ज हुई है। घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोगिता में गिरावट आई। क्षमता उपयोग में यह गिरावट देश में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद आई है।

45. घरेलू उद्योग को व्यापक घरेलू मांग होने के बावजूद अपने उत्पादन का निर्यात करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। ऐसे निर्यात पसन्द का मामला नहीं होता है परन्तु घरेलू उद्योग के लिए बाध्यकार होते हैं जो देश में उत्पाद के लगातार बंद हुए आयात कर रहे हैं। विरोधी पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यह एक झूठा मामला है कि घरेलू उद्योग निरुद्ध कर रहा है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि घरेलू उत्पाद का निर्यात उससे कम कीमत पर कर रहे हैं जो वह सामान्य स्थिति में घरेलू बाजार में प्राप्त कर सकते हैं। इन बढ़े हुए आयातों का एकमात्र कारण कम कीमत होना है, याचिकाकर्ता घरेलू बाजार में अपने उत्पाद के लिए मांग प्राप्त करने में असमर्थ रहा है और इसलिए विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने को बाध्य हुआ है। याचिकाकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में उनकी घरेलू बिक्री और निर्यात कीमत तथा आयात की कोरियाई पहुंच कीमत पर आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

46. निवेश पर लाभप्रदतरा एवं आय अभी भी पूर्व में दर्ज स्तर से कम है। यह पिछले 4 - 5 वर्षों से अधिक की लागत स्थिति पर कम से कम 10 प्रतिशत तक के सुधार के बावजूद हुआ है।

47. घरेलू उद्योग का उत्पादन जो 2009-10 तक बढ़ रहा था, में उसके बाद गिरावट आ गई। घरेलू उद्योग ने बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अपनी क्षमता में वृद्धि की। इसके बावजूद जब देश में उत्पाद के लिए मांग महत्वपूर्ण रूप से उच्च है, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने में असमर्थ रहा था। इसके आगे हालांकि क्षति की अवधि में घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई थी लेकिन यह उत्पादन स्तर

एवं घरेलू मांग से काफी कम थी। इसके बावजूद घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अधिक मात्रा की बिक्री करने की अपनी असमर्थता को देखते हुए अपनी बिक्रियों के एक प्रमुख भाग का निर्यात करने हेतु बाध्य हुआ है। इस विषय में यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात किया जाना पसन्द एवं वरीयता के मुकाबले बाध्यता अधिक है।

48. यह तथ्य कि याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग करने में समर्थ नहीं है, को वर्ष 2007-08 से 2010-11 (दिसम्बर तक) तक उत्पादन घन्टे के हिसाब से क्षति पर प्रस्तुत उनके आंकड़ों से देखा जा सकता है।

49. आयातों की पहुँच कीमत (क) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और (ख) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है। आयातों से घरेलू बिक्री कीमतों में महत्वपूर्ण रूप से कटौती हुई है। कीमत कटौती से कीमत में वृद्धि अथवा ह्रास हो रहा है।

50. याचिकाकर्ता ने बताया है कि बढ़े हुए आयातों का प्रभाव भारत में स्थापित किए जा रहे (एन ओ सी आई एल एवं मर्चेंट द्वारा) अतिरिक्त क्षमता के वाणिज्यिकरण पर होगा। प्रथमतः आयातों में दी गई बढ़ोतरी, उत्पादक अतिरिक्त क्षमताओं जो कि स्थापित होने वाली है, के लिए बाजार भी नहीं खोज सके। दूसरा और यदि उत्पादक ने कुछ बाजार खोजे हैं तो वहां कीमतें संभवतः काफी विपरीत हैं। एन ओ सी आई एल अकेले लगभग 247 करोड़ रूपए का निवेश कर रहा है। मर्चेंट द्वारा काफी निवेश किया जा रहा है। एन ओ सी आई एल की अकेले 1000 व्यक्तियों से अधिक की रोजगार क्षमता है। इन निवेशों का महत्वपूर्ण भाग वित्तीय संस्थानों से आता है। इस प्रकार निवेश एवं रोजगार पर आयातों में वृद्धि के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

51. याचिकाकर्ता ने बताया है कि मांग एवं आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि निर्यात में उपयोग के लिए शुल्क मुक्त अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत आयात को घरेलू मांग के लिए गणना करने से छोड़ देने चाहिए। अन्य भारतीय उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमता (वर्तमान एवं भावी विस्तार) पर विचार करने के पश्चात डी आई के पास उपलब्ध सूची के अनुसार मांग एवं आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। इसके विपरीत डी आई के पास घरेलू उद्योग से अधिक क्षमता है।

52. घरेलू उद्योग बिक्री अवसर खो रहा है। इसी प्रकार कम कीमत पर बढ़े हुए आयातों का लगातार होने के कारण पाटनरोधी शुल्कों के लगाने के बाद भी उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ निवेश पर आय और नकदी प्रवाह में सुधार नहीं हो रहा है। विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित कम कीमतें और विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमताओं के कारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कम कीमतों के बावजूद आयात और अधिक बढ़ रहे हैं। आयात वृद्धि से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आने से उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को बढ़े हुए आयातों के कारण क्षति हो रही है।

53. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पहले ही घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के अलावा पी एक्स- 13 के बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को खतरे को निम्नलिखित कारकों के द्वारा स्थापित किया गया है:



(क) प्रचलित पाटनरोधी शुल्कों पर विचार करने के बावजूद भी घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच कीमत अंतर बहुत अधिक है।

(ख) विदेशी उत्पादक काफी अनप्रयुक्त क्षमता रखते हैं। जिसके कारण विदेशी उत्पादक अधिक से अधिक संभावित अतिरिक्त बाजार की तलाश कर रहे हैं।

(ग) चीनी तथा कोरियाई उत्पादक के बीच विशेष प्रबंधन कोरियाई उत्पादक को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर रहा है। इस प्रकार कोरियाई उत्पादक संभवतः भारतीय बाजार में अपने गतिविधियों में तेजी लाएगा।

(घ) वैश्विक मंदी के पश्चात टायरों के लिए वैश्विक बाजार लगातार मंदा रहा है, जबकि भारतीय व्यापार काफी मजबूत है। टायर एवं इसके सहयोगी द्वारा प्रकाशित सूचना स्पष्ट रूप से मांग/खपत में वृद्धि को इंगित करता है। परिणामस्वरूप भारतीय बाजार विदेशी उत्पादकों के लिए लगातार लाभप्रद होते जा रहे हैं।

54. रक्षोपाय शुल्कों को लागू करना सार्वजनिक हित में है। पी यू आई उपभोक्ताओं के लिए एक प्रमुख लागत तत्व नहीं बनाता है। 6 - पी पी डी की प्रमुख खपत टायर उद्योग द्वारा की जाती है। 6 - पी पी डी का लागत हिसाब टायर उद्योग की कीमत का 1 प्रतिशत से कम बनता है। किसी भी तरह इस परिकल्पना के लिए कोई आधार नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप और रक्षोपाय शुल्क तक एन ओ सी आई एल अपनी कीमतें बढ़ाएगा। एन ओ सी आई एल केवल उपभोक्ताओं से अतिरिक्त बाजार की तलाश कर रहा है। वर्तमान मामले में रक्षोपाय शुल्क लागू करना निम्न कारणों से सार्वजनिक हित में होगा।

55. इस उत्पाद के उत्पादकों के लिए 6 - पी पी डी एक मुख्य उत्पाद बनाता है। घरेलू उद्योग की उपस्थिति ने कीमतों को उचित स्तर पर रखा है। कोरियाई एवं चीनी उत्पादकों की सोच पहले भारत में उत्पाद के उत्पादन को समाप्त करना है और उसके बाद उच्च कीमतें वसूल करना है। क्या घरेलू उद्योग बच पाएगा, इसका लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा।

56. एन ओ सी आई एल द्वारा अकेले ही लगभग 247 करोड़ रुपए का नया निवेश किया जा रहा है। इसी तरह मर्चेम द्वारा भी महत्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है। इन निवेशों में मुख्यतः वित्तीय संस्थानों से हैं। आयातों में वृद्धि से स्पष्टतः इन सार्वजनिक निधियों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना है। एन ओ सी आई एल में अकेले ही 1000 व्यक्तियों से अधिक रोजगार हैं। यदि घरेलू उत्पादक नहीं बचते हैं तो इससे रोजगार प्रतिकूलतः प्रभावित होगा।

#### **मर्चेम लि० (घरेलू उत्पादक) का अनुरोध**

57. कंपनी रबड़ रसायन विनिर्माण करती है और 300 मी.टन क्षमता युक्त है। वे इसे 8000 मी.टन की क्षमता तक बढ़ाने जा रहे हैं और जुलाई 2011 से बढ़ी हुई क्षमता का उत्पादन आरंभ होने की संभावना है। विस्तारण से 165 व्यक्तियों का रोजगार सृजित होगा।

58. कंपनी पी यू आई पर रक्षोपाय शुल्क लागू करने का प्रबल समर्थन करता है ।
59. पी यू आई के आयात में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है । उत्पादन लागत से काफी कम कीमत पर हुई आयात वृद्धि के कारण गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति होने का खतरा है ।
60. 6-पी पी डी की उत्पादन लागत (संदर्भ: मानक निविष्टि उत्पादन क्रम.सं. 1412) लगभग 160.91/किग्रा. है । परन्तु आयात 3.30 अम.डा./किग्रा. 1.48 रूपए/किग्रा. की कीमत पर हो रहे हैं ।
61. कम कीमत पर आयात वृद्धि से कीमतों में ह्रास हुआ है और इसने घरेलू बाजार में पी यू आइ की कीमत वृद्धि को रोका है ।
62. आयात वृद्धि ने अनुचित कीमत के कारण उपभोक्ता को बनाए रखना असंभव कर दिया है । विकसित देशों में 6 पी पी डी के मुख्य उत्पादक भारत में बेशी मात्रा का पाटन कर रहे हैं ।
63. आयातों से हमारी लाभप्रदता एवं प्रचालन बुरी तरह प्रभावित हुई है । यह आगे हमारे नकदी प्रवाह, वृद्धि अवसर इत्यादि के प्रतिकूलतः प्रभावित करेगा । यदि रक्षोपाय उपाय नहीं किए जाते तो हमारे संयंत्र घाटे में जाएंगे और उन्हें बंद कर करने पर बाध्य होना पड़ेगा ।

### निर्यात करने वाले देशों के विचार

### यूरोपीय संघ के विचार

64. आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रथमदृष्ट्या पता चलता है कि कोई गंभीर क्षति नहीं है अथवा उस पर खतरा हो जैसे कि डब्ल्यू टी ओ रक्षोपाय करार (डब्ल्यूटीओएसए) की धारा 4.1 (ख) में अपेक्षित है ।
65. आवेदन में दिए गए आयात संबंधी हाल ही के आंकड़े, आवेदक के इस दावे के अनुसार कि उनके डाटाबेस के प्रवर्जन होने के कारण अधिकांश आई सी डी उनको उपलब्ध नहीं हो सके, अधूरे हैं, इसका सत्यापन करना अपेक्षित है ।
66. याचिकाकर्ता अनपेक्षित गतिविधियों की पहचान करने में असमर्थ है । गैट के अनुच्छेद XIX के अनुसार रक्षोपाय उपाय केवल अप्रत्याशित स्थिति ही उठाया जाने चाहिए ।
67. अनन्तिम उपायों को लागू करने हेतु न्यायोचित ठहराने के लिए डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 6 में यथाअपेक्षित मौजूद कोई निर्णय परिस्थिति नहीं है ।
68. वर्ष 2005 और 2008 में पाटनरोधी शुल्कों के अंतर्गत विभिन्न देशों से पहले से ही आयात हुए थे और यह कि उपाय वर्तमान में समीक्षाधीन (सनसेट और मध्यावधि समीक्षा) हैं तथा दोहरा उपचार नहीं होना चाहिए ।

69. आयातों में वृद्धि हाल ही में तीव्र तथा काफी अधिक नहीं है और कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हुई है। आवेदन के अनुसार हाल ही की अवधि में आयातों में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष 2009 में 8834 से 2010 में 9043) हुई है, जो आयात में तीव्र तथा महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है।

70. इस प्रकार कोई गंभीर क्षति का खतरा नहीं है। वर्ष 2007-08 और 2009-10 के बीच क्षमता तथा उत्पादन में विशेष वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान उत्पादन एवं बिक्री में विशेष वृद्धि हुई है।

71. उद्योग की स्थिति में आयात वृद्धि एवं हानि के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए नकारात्मक प्रभाव याचिकाकर्ता की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं जिसे आयातों पर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

### मिस्र के अरब गणराज्य के विचार

72. चूंकि संबद्ध वस्तु पी एक्स - 13 के मिस्र के कोई निर्यातक नहीं है इसलिए रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार पी एक्स-13 के आयात पर लगाए जाने वाले कोई रक्षोपाय उपाय से मिस्र को बाहर रखना चाहिए।

### कोरिया गणराज्य के विचार

73. दोहरे जोखिम पाटनरोधी एवं रक्षोपाय शुल्कों को समकालिक रूप में लागू करने के कारण है। कोरियाई कंपनियां जो पी एक्स-13 का निर्यात कर रहे हैं, पर अक्टूबर 2008 से भारत सरकार द्वारा पहले ही पाटनरोधी शुल्क लागू किए गए हैं। इसके अलावा जुलाई, 2010 में भारतीय पाटनरोधी प्राधिकारियों ने अपने घरेलू उद्योग के अनुरोध पर एक मध्यावधि समीक्षा आरंभ की।

74. डब्ल्यू टी ओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4 के अनुसार यह निर्धारण करने के लिए कि क्या गंभीर क्षति या खतरा मौजूद है, जांच प्राधिकारी उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे और अन्य कारकों द्वारा आयात पर हुई क्षति पर विचार नहीं करेंगे।

75. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। आधार वर्ष के रूप में वर्ष 2006-07 को लेते हुए आवेदक द्वारा दायर याचिका के आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में 100 से 161.15; क्षमता उपयोग में 100 से 112.20; की वृद्धि हुई है; घरेलू बिक्री दोगुनी हुई है और लाभ तीन गुने से अधिक अर्थात् लाभ में 100 से 325 तक की वृद्धि हुई है।

76. कोई अपरिहार्य घटना नहीं हुई है और आयात वृद्धि हाल ही में, अचानक, तीव्र तथा बहुत अधिक नहीं थी।

### निर्यातकों के विचार

जियांग्सु सिनोर्गचेम प्रौद्योगिकी कं० लि० चीन पी आर के विचार

77. रक्षोपाय जांच आरंभ करने के लिए आवेदन तथ्यहीन तथा वैधानिक आधार से परे हैं। जांच प्राधिकारी ने आवेदन की इसे प्रारंभ करने से पहले छानबीन नहीं की।

78. भारतीय पाटनरोधी प्राधिकारी ने लगभग सभी स्रोतों पर लागू मौजूदा रक्षोपाय जांच एवं पाटनरोधी शुल्क से पहले संबद्ध उत्पाद पर पहले ही पाटनरोधी जांच आरंभ कर दी है।

79. भारत में घरेलू उद्योग को विगत में भारत सरकार द्वारा किसी न किसी तरह संरक्षण दिया गया है। भारत में घरेलू उद्योग को भारत सरकार से व्यापार बाधाओं के जरिए संरक्षण प्राप्त करने की आदत है हालांकि यह विधिसम्मत नहीं है।

80. रक्षोपाय जांच (अप्रैल 2010 से सितम्बर 2010 वार्षिक) की प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि प्रदर्शित करने के लिए महानिदेशक (रक्षोपाय) को प्रस्तुत सूचना से यू एस ए से आयातों के ब्यौरे जानबूझ कर हटाए गए हैं। आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा डी जी ए डी को सूचित वास्तविक आयातों के मामले में प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

वर्ष	डी जी एस (मी.टन) के साथ आयात दावा	प्रतिशत वृद्धि	डी जी एस (मी.टन) के साथ आयात दावा	प्रतिशत वृद्धि
2009-10	8834	100 %	9828	100 %
जांच अवधि (वार्षिक)	9043	102 %	9043	92 %

81. वर्ष 2009-10 से जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति में गिरावट प्रदर्शित हुई है और इसमें आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार वृद्धि नहीं हुई है।

82. एस ओ एस के अनुच्छेद 2.1 तथा गैट 1994 के अनुच्छेद १, 1 (क) में अपेक्षित है कि गंभीर क्षति के मामले में आयातों में वृद्धि मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से हाल ही में अधिक, अचानक अधिक, अधिक तीव्र और वास्तविक रूप से अधिक होनी चाहिए। भारत में उपलब्ध आयात वृद्धि का निर्धारण करने हेतु एसिटाइलीन ब्लैक मामले के लिए आंकड़े हाल ही के तीन वर्षों के हैं। 10 वर्ष की जांच अवधि असामान्य रूप से लम्बी है और रक्षोपाय की पद्धति के विरुद्ध है।

83. घरेलू उद्योग से घरेलू उद्योग प्रश्नावली के अनुसार पूर्ण एवं विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा जाएगा और तत्पश्चात प्रश्नावली का उत्तर देने के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। घरेलू उद्योग ने उक्त प्रश्नावली में समायोजन योजना हेतु अपेक्षित जानकारी यथा- सनदी इंजीनियरी फर्म द्वारा परियोजना रिपोर्ट और लागत लेखाकार द्वारा परियोजना लागत प्रस्तुत नहीं की है।

84. अप्रत्याशित घटनाक्रम जिसके कारण आयातों में वृद्धि हुई, के संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः जाँच शुरू नहीं की जानी चाहिए थी।

85. केकेपीसी तथा सिनॉर्गकैम के बीच केवल सामान्य व्यापार संबंध हैं। सिनॉर्गकैम ने कभी भी केकेपीसी को कम कीमत पर 4एडीपीए की बिक्री नहीं की है। उनकी बिक्री सदैव लाभप्रद बाजार कीमत पर की गई है।

86. अनेक देशों में समय-समय पर उत्पादों हेतु वैट प्रति अदायगी दरों का समायोजन एक सामान्य कार्य पद्धति रही है। चीन की सरकार द्वारा अनेक उत्पादों पर 17% की वैट प्रतिअदायगी दर लागू की गई है और यह 6पीपीडी तक सीमित नहीं है। इसे अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं माना जा सकता है।

87. वर्ष 2009-10 के लिए घरेलू उद्योग के संबंध में निदेशक की रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ष 2009-10 में मंदी का कोई प्रभाव लक्षित नहीं हुआ है। भारतीय उद्योग और वैश्विक टायर उद्योग अपने सामान्य स्तर पर प्रचालन कर रहे हैं। अतः अप्रत्याशित घटनाक्रम का दावा सही नहीं है।

88. जैसाकि दिनांक 06.09.2007 की व्यापार सूचना सं. एसजी/टीएन/1/97 के अनुबंध के तहत अपेक्षित है, घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के एक भाग के रूप में कोई विस्तृत समायोजन योजना महानिदेशक (रक्षोपाय) के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि आयातों में कथित वृद्धि के कारण बढ़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है। कानून के अनुसार किसी व्यवहार्य समायोजन योजना की अनुपस्थिति में यह जाँच समुचित नहीं है।

89. घरेलू उद्योग सापेक्ष अथवा तुलनात्मक कथित आयातों, घरेलू उद्योग को कथित रूप से गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे और आयातों में वृद्धि तथा कथित रूप से गंभीर क्षति अथवा उसके खतरे के बीच कारणात्मक संबंध को वस्तुतः सिद्ध करने में असफल रहा है।

90. उत्पादन, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और घरेलू खपत में घरेलू उत्पादकों के हिस्से में कमी तथा घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट का प्रमुख कारण घरेलू उत्पादकों में से एक के द्वारा अपने संयंत्र को बंद किया जाना है।

91. यूएस-लैम्ब मामले में अपीलीय निकाय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप हमारा यह मत है कि अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं किया गया है और अनुच्छेद 4.2 (ख) का अनुपालन न होने के कारण जाँच शुरूआत अधिसूचना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है।

92. आवेदक आयातों में वृद्धि और गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मकता की मौजूदगी दर्शाने में असफल रहा है।

कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि., कोरिया के विचार

93. याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो अप्रत्याशित था और जिसके परिणामस्वरूप भारत में वस्तु के आयातों में वृद्धि हुई। अतः अनुच्छेद XIX :1 (क) के तहत विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति नहीं की गई है।

94. दूसरे, याचिका में यह उल्लेख नहीं है कि आयातों में वृद्धि गैट के अंतर्गत टैरिफ रियायतों से भारत द्वारा की गई वचनबद्धताओं के प्रभावस्वरूप हुई थी। भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य है और उसने गैट के तहत कुछ वचनबद्धताएँ की हैं, केवल इसी आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों में वृद्धि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत की गई उन जेनेरिक वचनबद्धताओं के प्रभावस्वरूप हुई थी।

95. आवेदन डीजीएडी को भेजा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने डीजीएडी के समक्ष यह दावा किया है कि पाटन के कारण उन्हें वास्तविक क्षति हुई थी। साथ ही घरेलू उद्योग ने डीजी(एसजीडी) के समक्ष यह दावा किया है कि बढ़े हुए आयातों के कारण उन्हें गंभीर क्षति हुई थी। इस मामले में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना अपेक्षित है कि कानून के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाएगा।

96. इस मामले में यह देखा जा सकता है कि आयातों का लगभग 97% हिस्सा केवल पाटित स्रोतों अथवा उन देशों से आया है जो डीजीएडी द्वारा भारत में वस्तु का पाटन करते पाए गए हैं। उपयुक्त रूप से लगभग उन सभी देशों के विरुद्ध पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू हैं जो भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करते हैं। चूँकि पाटनरोधी शुल्क पहले से अधिरोपित है और मौजूदा शुल्क समीक्षाधीन है अतः डीजी (एसजीडी) द्वारा इस बात का पता लगाने कि क्या रक्षोपाय शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है, के लिए एक और जाँच शुरू करना आवश्यक नहीं है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए नियम में यह प्रावधान है कि चूँकि वस्तु का पाटन हुआ है अतः डीजी (एसजीडी) आवेदन डीजी (एडी) को अग्रेषित करेंगे।

97. आयात संबंधी आंकड़ों का दुरुपयोग किया गया है हालांकि याचिकाकर्ता ने लेनेक्सिस द्वारा किए गए आयातों (डीजीएडी के समक्ष दायर याचिका में दूसरा घरेलू उत्पादक) को शामिल किया है तथापि उन्होंने अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड में सही आंकड़े न देने के लिए किसी कानूनी आधार के बिना ऐसे आंकड़ों को आयातों में शामिल नहीं किया है।

98. प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की शुरुआत नियम 5 के प्रावधानों का पूर्णतः उल्लंघन है। घरेलू उद्योग द्वारा आयात प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। रक्षोपाय शुल्क के असाधारण स्वरूप और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने की बाध्यता को समझते हुए महानिदेशक ने घरेलू उद्योग के लिए प्रश्नावली फॉर्मेट निर्धारित किया है जिसके भाग-IV में उनके द्वारा “समायोजन योजना संबंधी सूचना” दिया जाना अपेक्षित है। तथापि, याचिकाकर्ता ने अभी तक प्रश्नावली भरकर प्रस्तुत नहीं की है।

99. आयातों में वृद्धि नहीं हुई है जैसाकि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :-

क्र. सं.	वर्ष	संबद्ध वस्तु का आयात (मी. टन)	आयातों में वृद्धि (मी. टन)	आयातों में वृद्धि (%)
1	2009-10	8834		
2	2010-11 अप्रैल-सितम्बर	4,553	209	2.37
	2010-11 वार्षिक	9043		

100. जैसाकि स्वतः स्पष्ट है वर्ष 2010-11 के प्रथमार्द्ध के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि मात्र 289 टन अथवा वार्षिक आधार पर 2.37% है। अतः आयातों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

101. केवल मै. एनओसीआईएल लि. के संदर्भ में ही उत्पादन, क्षमता उपयोग आदि में गिरावट जैसे अन्य सभी क्षति मानदण्डों पर विचार किया गया है लेकिन सभी उत्पादकों के लिए समग्र रूप से केवल बाजार हिस्से में गिरावट पर विचार किया गया है।

102. रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग को आयातों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण पहुँची गंभीर क्षति का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए किया गया आपातकालीन उपाय है। एक लम्बी समयवधि में आयातों में क्रमिक अथवा यदा-कदा होने वाली वृद्धि से घरेलू उद्योग को ऐसी कोई क्षति होने की संभावना नहीं है जो रक्षोपाय शुल्क जैसे आपातकालीन उपाय को समुचित ठहरा सकें।

103. वर्ष 2004-05 में 5655 मी. टन की तुलना में वर्ष 2010-11 में 9066 मी. टन के आयात स्तर जिसमें 60% की वृद्धि प्रदर्शित होती है, को यदि अधिक माना भी जाता है तो भी यह वृद्धि 7 वर्षों की लम्बी अवधि में हुई है और इसलिए यह आकस्मिक नहीं है। वर्ष 2009-10 में 8834 मी. टन से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 9066 मी. टन के आयात मात्र 2.62% की वृद्धि दर्शाते हैं जो अधिक नहीं हैं। यह वृद्धि न तो अत्यधिक है, न ही आकस्मिक है और न ही विशेष रूप से प्रभावकारी है।

104. निम्नलिखित क्षति संबंधी आंकड़ों की जाँच से यह प्रकट होता है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है :-

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-09 की तुलना में वर्ष 2010-11 में परिवर्तन (वार्षिक)
1	संस्थापित क्षमता	258	258	274	274	6%
2	उत्पादन	235	238	273	253	8%
3	घरेलू बिक्री की मात्रा	122	117	174	177	45%
4	निर्यात बिक्री की मात्रा	441	474	418	282	-36%
5	बिक्री लागत	107	137	122	124	25%

6	बिक्री कीमत	96	132	121	120	25%
7	प्रति कि.ग्रा. लाभ/हानि	-5	89	106	88	1860%
8	बिक्री कीमत के % के रूप में लाभ	-1	56	63	52	5300%
9	नकद लाभ	24	110	1871	162	575%
10	आरओसीई	-1	83	95	76	7700%
11	मजदूरी	74	71	97	107	45%

105. वर्ष 2000-01 में 100 के स्तर से बढ़कर क्षमता वर्ष 2010-11 में 274 के स्तर पर पहुँच गई है। यदि हम पिछले 4 वर्षों के दौरान रहे निष्पादन पर विचार करें तो क्षमता वर्ष 2007-08 में 258 से बढ़कर वर्ष 2010-11 के दौरान 274 पर पहुँच गई थी जिसमें 6% की वृद्धि प्रदर्शित होती है पिछले दशक के दौरान उत्पादन में 2.53 गुना वृद्धि हुई है। विशेष रूप से उत्पादन वर्ष 2007-08 में 235 से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 253 के स्तर पर पहुँच गया था जिसमें 8% की वृद्धि लक्षित होती है। अत्यधिक क्षमता संवर्धन के बावजूद क्षमता उपयोग लगभग 91%-92% के स्तर पर बना हुआ है। वर्ष 2007-08 में 122 से बढ़कर घरेलू बिक्री 2010-11 में 177 हो गई है जिसमें 45% की वृद्धि दर्ज की गई है।

106. वर्ष 2007-08 की तुलना में केवल निर्यात मात्रा में ही वर्ष 2010-11 के दौरान 36% की गिरावट दर्ज की गई जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एकमात्र कारण हो सकता है।

107. वर्ष 2007-08 में बिक्री लागत 107 से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 124 हो गई थी जबकि इसी अवधि के दौरान बिक्री कीमत 96 से बढ़कर 120 के स्तर पर पहुँच गई थी। इस प्रकार जहाँ बिक्री लागत में 17 आधार बिन्दु की वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर बिक्री कीमत में 24 आधार बिन्दु की वृद्धि दर्ज की गई।

108. वर्ष 2007-08 में (5) की हानि के स्तर से घरेलू उद्योग वर्ष 2010-11 के दौरान 93 आधार बिन्दुओं की वृद्धि दर्ज करते हुए 88 के लाभ स्तर पर पहुँच गया है। उक्त अवधि के दौरान आरओसीई (-1) से बढ़कर 76 हो गया है।

109. उक्त आवेदन में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आंकड़े बढ़े हुए आयातों के कारण उन्हें पहुँची “ गंभीर क्षति ” का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसके विपरीत पिछले चार वर्षों में घरेलू उद्योग क्रमिक रूप से सुदृढ़ हुआ है।

110. रक्षोपाय जाँच के अधीन वस्तु का इस्तेमाल टायरों के विनिर्माण में किया जाता है जो ऑटोमोबाइल उद्योग की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। ऑटोमोबाइल उद्योग को टायरों के आयात के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। यदि 6 पीपीडी के आयात पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो घरेलू उद्योग में टायरों की कीमत बढ़ जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू रूप से उत्पादित टायरों की तुलना में आयातित टायर अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे जो टायर विनिर्माताओं के साथ-साथ ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं के हितों के विरुद्ध होगा और अंततः आम आदमी के लिए भी महंगा साबित होगा।



111. घरेलू उद्योग द्वारा कोई व्यवहार्य समायोजन योजना प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्राधिकारी रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं कर सकते हैं। सफेद/पीले फॉस्फोरस मामले में प्रस्तुत अंतिम जाँच परिणामों में महानिदेशक ने बढ़े हुए आयातों के कारण वास्तविक क्षति की मौजूदगी निर्धारित करने के बाद भी रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि समायोजन योजना में घरेलू उद्योग ने यह निर्धारित नहीं किया था कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम होगा। माननीय उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को बरकरार रखा गया था।

112. यद्यपि एओएस के अनुच्छेद 5.1 की यह व्याख्या स्वीकार्य है कि जाँचकर्ता प्राधिकारी समायोजन योजना पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं हैं तथापि रक्षोपाय नियमावली, 1997 के नियम 5 में विशेष रूप से समायोजन योजना का प्रावधान है। समायोजन योजना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्थान पर घरेलू कानून लागू होगा।

113. घरेलू उद्योग गुजरात स्थित दाहेज में विस्तार कार्य के इच्छुक नहीं हैं जैसा कि समायोजन योजना में उल्लिखित है। उन्होंने 3 वर्ष के बाद भी परियोजना राशि के केवल 10% का निवेश किया है, जैसाकि पणधारक बैठक में दिए गए अध्यक्ष के वक्तव्य जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, स्पष्ट होता है।

114. क्षति मार्जिन तथा पाटन मार्जिन शुल्क के बीच के अंतर के रूप में रक्षोपाय शुल्क संबंधी घरेलू उद्योग के दावे का कोई विधिक आधार नहीं है। एडीए के अनुच्छेद 11.1 में पाटन की भरपाई हेतु अपेक्षित सीमा तक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है। एओएस के अनुच्छेद 5.1 में क्षति को रोकने और समायोजन को सुकर बनाने के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का प्रावधान है। अतः एओएस के तहत क्षति मार्जिन के बराबर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाना आवश्यक नहीं है।

115. केपीसी ने 4-एडीपीए जो 6-पीपीडी हेतु एक कच्ची सामग्री है, की निर्बाध आपूर्ति के लिए सिनॉर्गकैम, चीन के साथ एक संविदा की है। इस संविदा को किसी विशेष संबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वैश्विक बाजार में केकेपीसी तथा सिनॉर्गकैम दोनों एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। बढ़े हुए आयातों का इन दोनों कंपनियों की उपर्युक्त दीर्घावधिक संविदा से कोई लेना-देना नहीं है।

116. चीन के आपूर्तिकर्ता भारत की तुलना में कम कीमत पर केकेपीसी को 4एडीपीए का निर्यात कर रहे हैं। केकेपीसी को कीमत संबंधी यह लाभ उसके द्वारा दिए गए बल्क ऑर्डर तथा दीर्घकालिक संविदा के कारण मिल रहा है। इसका अप्रत्याशित घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है।

117. घरेलू माँग की तुलना में केकेपीसी की बेशी क्षमता का अप्रत्याशित घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है।

118. विभिन्न देशों में कीमत संबंधी विभेद हमेशा मौजूद रहेगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में केवल कोरियाई कीमत से की गई है जबकि अन्य देशों से भी बड़ी मात्रा में आयात हुए

हैं। भारतीय बाजार में केपीसी की तुलना में याचिकाकर्ता द्वारा बिक्री कीमत का निर्धारण अधिक प्रभावशाली है।

119. वैश्विक मंदी के कारण वर्ष 2008-09 में भारत में 6 पीपीडी के आयात में गिरावट आई थी। इसके अतिरिक्त, 2007-09 की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता वैश्विक मंदी से प्रभावित नहीं हुआ है क्योंकि बिक्री तथा अन्य क्षति मानदण्डों से वृद्धि प्रदर्शित होती है।

120. घरेलू उद्योग ने कोचीन तथा लुधियाना पत्तन के संबंध में पूर्व में शामिल न किए गए आयात आंकड़ों को शामिल करने के बाद क्षति संबंधी संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तथापि कुछ चुनिंदा आयातों को शामिल न किए जाने से घरेलू उद्योग को हुई क्षति यथा नकद लाभ, निवेश आदि की मात्रा में परिवर्तन अथवा अत्यधिक अंतर नहीं आ सकता है। प्राधिकारी द्वारा क्षति संबंधी संशोधित आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसमें गंभीर त्रुटियाँ और व्याख्या संबंधी विसंगतियाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों पत्तनों सहित देश-वार आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

121. वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में घरेलू बिक्री और बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में लाभ में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 में आई नगण्य गिरावट किसी विशेष क्षति का संकेत नहीं है।

### मै. सॉल्यूशिया इंक, यूएसए के विचार

122. घरेलू उद्योग द्वारा महानिदेशक (रक्षोपाय) की दिनांक 21 दिसम्बर, 2009 की व्यापार सूचना में गोपनीयता के दावे के संबंध में उल्लिखित दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है। इस मामले में रक्षोपाय नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधानों का पालन भी नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने मात्रा संबंधी सूचना के बारे में भी गोपनीयता का दावा किया है जबकि यह गोपनीय सूचना की श्रेणी में शामिल नहीं है।

123. आवेदन अथवा जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में इस संबंध में कोई जाँच/विश्लेषण नहीं किया गया है कि मौजूदा जाँच को औचित्यपूर्ण कैसे माना जा सकता है जबकि संबद्ध वस्तु के लगभग सभी आयात ऐसे देशों से किए गए हैं जो पाटनरोधी जाँचों (निर्णायक समीक्षा अथवा मध्यावधि समीक्षा जाँच) के अधधीन हैं।

124. पाटनरोधी शुल्क के अतिरिक्त रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने के अनुरोध का मूल आधार ही दूरशायपूर्ण है। इसे क्षति मार्जिन की सीमा तक रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने संबंधी जाँच की शुरूआत हेतु सटीक एवं समुचित आधार नहीं माना जा सकता।

125. आवेदन अथवा जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में उन प्रत्याशित परिस्थितियों का कोई उल्लेख नहीं है जिनके परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि का दावा किया गया है।

126. आयातों और माँग की प्रवृत्ति में पूर्ण सामंजस्य है अतः मौजूदा मामले में आयातों की प्रवृत्ति को अप्रत्याशित परिस्थितियों का परिणाम नहीं माना जा सकता है ।

127. वर्ष 2009-10 की तुलना में अप्रैल, 10-सितम्बर, 10 के दौरान आयातों में मात्र 2.4% की वृद्धि हुई है जिसे उस सीमा तक आकस्मिक, अत्यधिक और उल्लेखनीय नहीं माना जा सकता जो किसी रक्षोपाय जाँच शुरुआत को समुचित ठहरा सके । पिछले पाँच वर्षों अथवा उससे पूर्व की अवधि में आयातों की प्रवृत्ति पूर्णतः असंगत है जैसाकि इस मामले में किया गया है ।

128. मै. लेनेक्सिस द्वारा किए गए आयातों को शामिल न किए जाने के लिए कोई कानूनी अथवा तर्कसंगत आधार नहीं दिया गया है ।

129. आवेदन तथा जाँच शुरुआत अधिसूचना में घरेलू उत्पादन की तुलना में आयातों के संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है जो जाँच की शुरुआत और रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए एक आवश्यक शर्त है ।

130. घरेलू उद्योग ने अपनी सुविधानुसार अलग-अलग मानदंडों के लिए अलग-अलग समयावधि को अपनाया है जो तर्कसंगत नहीं है ।

131. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में कीमत को क्षति के मानदंडों में से एक माना है जो गलत है क्योंकि किसी भी रक्षोपाय जाँच में कीमत और अन्य कारक संगत नहीं होते हैं ।

132. संबद्ध वस्तु के आयातों और कथित गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है ।

133. घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि को दिसम्बर, 2010 तक बढ़ा दिया है जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

134. घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत अप्रत्याशित घटनाक्रम पूर्णतः स्थानीय है और चुनिंदा कंपनियों तक सीमित है और उसका इस्तेमाल वैश्विक रक्षोपाय के लिए नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010 के लिए वैश्विक आर्थिक मंदी को अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं माना जा सकता है ।

135. पाटनरोधी संबंधी निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन तक सीमित होगा अथवा क्षति मार्जिन तक । इस अनुमान के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन तक सीमित रहेगा ।

136. रक्षोपाय जाँच में कीमत तथा अन्य कारण संगत नहीं होते हैं और उन्हें “ ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत ” शब्दों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

137. आयात संबंधी आंकड़ों और उसके परिणामस्वरूप क्षति संबंधी आंकड़ों को संशोधित किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग से नए सिरे से अनुरोध प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा जाना चाहिए और यह अनुरोध उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन की समयावधि के साथ हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

### आयातकों के विचार (एटीएमए)

138. आयातों में वृद्धि जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा आरोप लगाया गया है, कानून के तहत अपेक्षित आकस्मिक, हालिया और पर्याप्त रूप से अत्यधिक होने की पूर्व शर्तों को पूरा नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, अबोधगम्य कारणों से घरेलू उद्योग ने लेनेक्सिस द्वारा किए गए आयातों को कुल आयातों में शामिल नहीं किया है। घरेलू उद्योग के इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि उत्पादन स्थगित किए जाने के कारण लेनेक्सिस द्वारा किए गए आयात हानिकारक नहीं हैं।
139. पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान हुई आयातों में वृद्धि मात्र 2.3% है जो पूर्णतः नगण्य है और किसी रक्षोपाय की अपेक्षा नहीं रखती है।
140. यदि लैक्सिस द्वारा किए गए आयातों को शामिल किया जाता है, जैसा कि होना चाहिए था, तो उपर्युक्त क्रम सं. 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान आयात मात्राओं में वास्तव में 8% की कमी होगी।
141. ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी ने हाल के आयातों के बजाय एक लम्बी अवधि के दौरान किए गए आयातों की प्रवृत्ति पर विश्वास किया है जो एओएस के अनुच्छेद 2.1 तथा सीटीए, 75 के खण्ड 8ख के अधिदेश के विपरीत है।
142. घरेलू उद्योग ने एक ही जांच अवधि के दौरान यह दावा किया है कि तीन अलग-अलग स्रोतों (पाटनरोधी मध्यावधि समीक्षा, पाटनरोधी एसएसआर तथा रक्षोपाय) से एक ही उत्पाद को तीन अलग-अलग प्रकार से क्षति पहुंची है। यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू उद्योग ने किस आधार पर यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क पर्याप्त नहीं है और अलग प्रकार का शुल्क लगाने हेतु डीजी रक्षोपाय से अनुरोध किया है जबकि ऐसी शुल्क दर का निर्धारण डीजीएडी द्वारा किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उपचार हो सकेगा।
143. घरेलू उद्योग आपात परिस्थितियों तथा अनपेक्षित परिस्थितियों की उपस्थिति को दर्शाते हुए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है।
144. उत्पादन, संस्थापित क्षमता तथा क्षमता उपयोग जैसे क्षति मानदण्डों के अनुसार इस मामले में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। वर्ष 2010-11 में संस्थापित क्षमता में 44% तथा क्षमता उपयोग में 137% वृद्धि हुई है।
145. घरेलू बिक्री में बढ़ती हुई घरेलू मांग के अनुपात में वृद्धि हुई है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग की पाटित आयातों से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है।

146. घरेलू बाजार की लाभप्रदता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि वर्ष 2010-11 के प्रथम छह महीने की अवधि में घरेलू बिक्रियों का मूल्य वर्ष 2009-10 की संपूर्ण अवधि से 40% अधिक था और समनुरूपी अवधि के दौरान लाभप्रदता में 56% तक की वृद्धि हुई है ।
147. वर्ष 2001-02 तथा 2005-06 के दौरान भी, जब आयात मामूली रहे थे, घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के निर्यात को प्राथमिकता दी थी न कि घरेलू बाजार को आपूर्ति करने को । अतः यह तर्क कि घरेलू उद्योग को निर्यात करने से रोका गया था, सर्वथा गलत है । घरेलू उद्योग अपने उत्पाद के 50% से अधिक का निर्यात करता है ।
148. किसी जांच की अवधि अधिक से अधिक 5 से 6 वर्ष होती है परंतु ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि 10 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान कारकों की जांच की गई हो ।
149. आयातों में आयात उछाल उन मामलों जैसा नहीं है जिन पर डीजी-रक्षोपाय ने रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की थी ।
150. घरेलू उद्योग भारत में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है अतः पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के पश्चात भी आयात किया जा रहा है । देश में उत्पाद की मांग एवं आपूर्ति में अंतर है । वर्ष 2009-10 में मांग में 142% तक की वृद्धि हुई थी तथा घरेलू उद्योग 86% क्षमता पर प्रचालन करने के बाद भी मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं रहा था ।
151. यदि मांग-आपूर्ति के अंतर का आकलन करने के लिए अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात को शामिल नहीं किया जाता है तो आयातों में वृद्धि तथा क्षति विश्लेषण का आकलन करने के लिए भी कुल आयात में इन आयातों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।
152. मर्केम की वर्तमान एवं भावी क्षमता के आंकड़ों अटकलों पर आधारित हैं । इसके अलावा मै0 मर्केम का घरेलू बिक्री आंकड़ा भी अटकल मात्र है । अतः घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए मांग - आपूर्ति के आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।
153. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किए शुल्क का संविभाजन व्यवहार्य नहीं है क्योंकि केवल कोरिया से आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क ही पाटन मार्जिन पर ही है । ईयू, चीन ताईवान जैसे अन्य देशों के लिए वह क्षति मार्जिन पर है । अतः क्षति की सीमा तक अलग प्रकार का शुल्क केवल कोरिया से आयातों पर ही लागू होगा ।
154. रक्षोपाय शुल्क सार्वजनिक हित में नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किए जाने के बाद प्रयोक्ता उद्योग संपूर्ण रूप से घरेलू उत्पादकों पर निर्भर हो जाएगा जिससे भारतीय टायर उद्योग अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा ।

155. घरेलू उद्योग अपने निर्यातों को पुनः भारतीय बाजार में भेज रहा है क्योंकि घरेलू बिक्री अधिक आकर्षक है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू बाजार मजबूत है और गत 6 महीनों से यह उन्नति कर रहा है।
156. लैक्सेस के लिए मांग - आपूर्ति के अंतर को दर्शाने वाले उत्पादन आंकड़े, अनुमानों पर आधारित हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
157. वर्ष 2009-10 की घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि:-

'यद्यपि वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण निर्यात बाजार काफी संकुचित हुआ है तथापि घरेलू टायर बाजार में काफी सुधार आया है। कम्पनी इस बात के प्रति आशान्वित है कि घरेलू बाजार की बेहतर स्थिति को देखते हुए, वह घरेलू व्यापार में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु बेहतर स्थिति में होगा'।

158. उपर्युक्त वक्तव्य से यह प्रदर्शित होता है कि निर्यात बाजार में गिरावट आई है जिससे घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री करनी पड़ी है।
159. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित समायोजन योजना वर्ष 2012 तक तैयार हो पाएगी। इस बीच की अवधि के लिए इस बात की कोई कार्य योजना नहीं है कि प्रयोक्ता उद्योग देश में उपलब्ध सीमित संसाधनों से किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

#### अखिल भारतीय रबर उद्योग एसोसिएशन की ओर से किए गए निवेदन

160. घरेलू उद्योग को पहले ही काफी हद तक सुरक्षा प्राप्त है अर्थात् ईयू, चीनी ताइपेई, चीन एवं कोरिया से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया है।
161. घरेलू उद्योग तथा प्रस्तुत यह सूचना कि वर्तमान याचिका पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का प्रतिकार करने के अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दायर की गई है। यह नोट करना उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे की उपस्थिति को साबित नहीं कर सका है।
162. याचिकाकर्ताओं को हुई कथित गंभीर क्षति तथा आयातों में तथाकथित वृद्धि के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
163. इस मामले में याचिकाकर्ताओं की शिकायत में कीमत निर्धारण पर बल दिया गया है तथा फोकस किया गया है क्योंकि आंकड़े आयात में हुई तेजी से वृद्धि को नहीं दर्शाते हैं और इसलिए याचिकाकर्ताओं ने रक्षोपाय संबंधी जांच शुरू करने के लिए कीमत निर्धारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया है। तथापि यह नोट किया जाना चाहिए कि अनुचित कीमत निर्धारण संबंधी शिकायतों के लिए सही मंच डीजीएडी है न कि डीजी रक्षोपाय।

164. याचिकाकर्ता मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने के लिए डीजीएडी से अनुरोध करने और उसी उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लागू करने की मांग करके दोनों फोरमों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
165. प्रयोक्ता उद्योग इस तथ्य को विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता रहा है कि प्रयोक्ता उद्योग की मांग की आपूर्ति करने के लिए घरेलू क्षमता पहले से ही सीमित है। इसके अलावा यह तथ्य कि घरेलू उद्योग अपने अधिकांश उत्पादन का निर्यात करता है, से स्थिति और खराब हो जाती है तथा उससे विचाराधीन उत्पाद की घरेलू आपूर्ति कम होती है।
166. चूंकि प्रयोक्ता उद्योग अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण प्राकृतिक रबड़ (विचाराधीन उत्पाद का एक विकल्प) की उच्च लागत के कारण पहले से ही क्षति का सामना कर रहा है, अतः यह जांच सार्वजनिक हित के विपरीत है। अतः विचाराधीन उत्पाद की लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि से उत्पादन अलाभकारी हो जाएगा।

#### जांच एवं परिणाम:

167. मैने मामले से संबंधित रिकॉर्डों, घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों तथा निर्यात राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन तथा उनसे उठने वाले मुद्दों का नीचे दिए गए जांच परिणामों में उचित स्थानों पर समाधान किया गया है।

#### जांचाधीन उत्पाद:

168. जांच शुरू करने के संबंध में जारी किए गए नोटिस में विचाराधीन उत्पाद को रबड़ रसायन एन-1, 3-डायमिथाइल ब्यूटाइल-एन फेनिल पैराफेनिलीन-डायामाइन से रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे पीएक्स-13 अथवा 6-पीपीडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य व्यापारिक अथवा ब्राण्ड नाम हैं 6सी, पिलफेक्स 13, सिरनटॉक्स 4020, एंटी-ऑक्सिडेंट 4020, कमहोनैक्स 13, वल्कोनैक्स 4020। विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क वर्गीकरण शीर्ष 3812, 3810, तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के वर्गीकरण शीर्ष 2921, 2925, 2934 तथा 2942 (छह अंकीय स्तर पर) के विभिन्न उपशीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जाता है।
169. हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। अतः इस बात की अभिप्राय हो जाती है कि विचाराधीन उत्पाद रबड़ रसायन एन-1, 3-डायमिथाइल ब्यूटाइल-एन फेनिल पैराफेनिलीन-डायामाइन है जिसे पीएक्स-13 अथवा 6-पीपीडी के नाम से भी जाना जाता है।
170. पीएक्स-13 का उत्पादन एक भापसह पात्र में एक नोबल धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतुलित उच्च दाब पर 4-नाइट्रोडाईफेनाइलामाइन तथा मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन के मिश्रण के हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। इस अभिक्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त तत्व, जिसमें ऐसे कीटोन जिन पर अभिक्रिया नहीं की गई हो, उपोत्पाद आदि होते हैं, में से उत्प्रेरक की उपस्थिति

को समाप्त करने के लिए उसे फिल्टर किया जाता है, जिसे तत्पश्चात् पुनः संसाधित किया जाता है। लो-बॉयलर पदार्थों के हटाने के लिए इस फिल्टरेट को आसवित किया जाता है तथा अंतिम उत्पाद तैयार करने के लिए इसे कतलों में काटा जाता है। ऐसे कीटोन प्राप्त करने के लिए जिन पर अभिक्रिया नहीं हुई हो, लो बॉयलर पदार्थों को पुनः आसवित किया जाता है। उत्प्रेरक को तब तक पुनः संसाधित किया जाता है जब तक कि उसकी क्रिया कम न हो जाए, तत्पश्चात् उसे हटा लिया जाता है।

171. पीएक्स-13 का उपयोग विभिन्न रबड़ उत्पादों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त प्राकृतिक रबड़, कृत्रिम रबड़ (एसबीआर, ब्यूटाडाइन रबड़, नाइट्राइल रबड़ तथा कार्बोक्सिलेटेड रबड़) तथा अन्य कृत्रिम रबड़ आधारित यौगिकों को संसाधित करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इस उत्पाद का प्रयोग प्रमुख रूप से टायर विनिर्माता करते हैं। दूसरे उद्योग भी इस उत्पाद का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं कृत्रिम रबड़ को संसाधित करने के लिए करते हैं।
172. इस जांच के क्रम में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपर्युक्त पैरा 168 में उल्लिखित पीएक्स-13 जैसे विभिन्न ब्राण्ड आयातित उत्पाद तथा घरेलू तौर पर उत्पादित पीएक्स-13 के उत्पादन प्रक्रिया, विशेषताओं अथवा अंतिम उपयोगों के बीच किसी प्रकार का अंतर अभिज्ञात नहीं किया गया है। वास्तविक तथा रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण वितरण जैसे मानदण्डों के संदर्भ में दोनों उत्पादों की विशेषताएं तुलनीय हैं।
173. अतः यह माना गया है कि घरेलू रूप से उत्पादित रबड़ रसायन पीएक्स-13 अथवा 6 पीपीडी अथवा वल्कोनेक्स 4020 इत्यादि सभी तरह से आयातित रबड़ रसायन पीएक्स-13 जिसे 6 पीपीडी, वल्कोनेक्स 4020 भी कहा जाता है, के समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद के दायरे में आते हैं तथा घरेलू रूप से उत्पादित रबड़ केमिकल पीएक्स-13 अथवा 6-पीपीडी अथवा वल्कोनेक्स 4020, रक्षोपाय शुल्क नियम 1997 के नियम 2(ड.) के अर्थों के भीतर आयातित रबड़ रसायन पीएक्स-13 अथवा 6-पीपीडी (पैरा 168 में उल्लिखित अन्य नाम) के समान उत्पाद हैं।

### घरेलू उद्योग

174. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1875 की धारा 8ख (6) (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार निभाषित किया गया है:-

(ख) 'घरेलू उद्योग' से

(i) भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु के समग्र उत्पादक अभिप्रेत है; अथवा

(ii) वे उत्पादक जिसका भारत में समान वस्तु अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु का समग्र उत्पादन, भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।



175. मामले के रिकॉर्डों के अनुसार आवेदक मै0 एनओसीआईएल लि0 के अलावा, इस उत्पाद के तीन अन्य विनिर्माता हैं। ये हैं मै0 लैक्सस प्रा0 इंडिया लि0, मै0 पीएमसी खड़ प्रा0 लि0 हुगली तथा मै0 मर्कम, एर्णाकुलम। इनमें से एक उत्पादक मै0 लैक्सस एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है जिसकी उत्पादन सुविधाएं भारत एवं भारत से बाहर भी अवस्थित हैं। भारतीय उत्पादकों की उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	लैक्सस इंडिया प्रा.लि.				
2.	पीएमसी खड़				
3.	मर्कम लि0				
4.	एनओसीआईएल लि0 (आवेदक)				
5.	कुल भारतीय उत्पाद				
6.	एनओसीआईएल का हिस्सा	60% से अधिक	70% से अधिक	80% से अधिक	75% से अधिक

176. मै0 मर्कम प्रा0 लि0, एर्णाकुलम ने यह दावा करते हुए कि कम कीमत पर आयातों में वृद्धि होने से घरेलू विनिर्माताओं को गंभीर क्षति हो रही है अथवा क्षति का खतरा है, रक्षोपाय शुल्क लगाने का अनुरोध करते हुए किए गए आवेदन को लिखित निवेदन के जरिए समर्थन प्रदान किया है। मै0 मर्कम ने अपनी मौजूदा विनिर्माण क्षमता तथा भविष्य की योजना के अलावा, संगत आर्थिक मानदण्डों के संबंध में ब्यौरेवार आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे। उन्होंने प्राधिकारी द्वारा आगे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था और जांच में हिस्सा भी नहीं लिया था।

177. रक्षोपाय जांच में समर्थनकर्ता की कोई अवधारणा मौजूद नहीं है। अतः उन्हें संबद्ध जांच में घरेलू उद्योग नहीं माना गया है।

178. यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक का हिस्सा रखते हैं। अतः यह माना गया है कि आवेदक सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8ख (6) (ख) (ii) में दी गई परिभाषा के अनुसार घरेलू उद्योग है एवं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं।

### जांच की अवधि

179. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियम 1997, रक्षोपाय संबंधी करार तथा गैट के संगत अनुच्छेद XIX में विशिष्ट रूप से यह परिभाषित नहीं किया गया है कि जांच की अवधि क्या होनी चाहिए। तथापि कोरिया के विरुद्ध अमरीका-लाइन पाइप मामले में पैनल के जांच परिणामों में जांच की अवधि के मुद्दे का निपटारा किया गया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्णय दिया है कि "जांच की अवधि की लम्बाई" तथा "उस अवधि को अलग-अलग खण्डों में बांटने का निर्णय लेना आयातक सदस्य के जांचकर्ता प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है।

'हम नोट करते हैं कि करार में इस बात का कोई निर्धारण नहीं किया गया है कि रक्षोपाय जांच में जांच की अवधि कितनी लम्बी होनी चाहिए अथवा विश्लेषण के प्रयोजनार्थ अवधि को किस प्रकार अलग-अलग खण्डों में बांटा जाएगा। अतः जांच की अवधि तथा उसको अलग-अलग खण्डों में बांटने का निर्णय लेना जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है।

वर्तमान मामले में आईटीसी द्वारा चयनित अवधि पांच वर्ष एवं छह महीने की थी, जो लम्बाई में उस अवधि के समान है, जिसे अर्जेंटीना में वहां के जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा-फुटवियर रक्षोपाय मामले में चुना गया था। तथापि, हम नोट करते हैं कि जांच की अवधि की लम्बाई के मामले में तर्काधार हेतु कोरिया द्वारा अपनाए गए जांच परिणामों में अपीलीय निकाय ने स्वभावतः अवधि की लम्बाई पर जोर नहीं दिया था बल्कि यह तर्क दिया था कि फोकस का बिन्दु हाल में किए गए आयात होने चाहिए न कि जांच की अवधि के दौरान मौजूदा प्रवृत्तियां। लाइन पाइप जांच के मामले में आईटीसी ने केवल अंतिम बिन्दुओं की ही तुलना नहीं की है अथवा जांच की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्ति को ही ध्यान में नहीं रखा है (जैसा अर्जेंटीना-फुटवियर रक्षोपाय के मामले में जांच के दौरान किया था)। उन्होंने आयातों से संबंधित आंकड़ों का पूरे 5 वर्षों के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विश्लेषण किया था तथा इस बात पर भी विचार किया था कि क्या 1998 की अंतरिम अवधि की तुलना में 1999 की अंतरिम अवधि में वृद्धि हुई थी।

हमारा मानना है कि ऐसी जांच अवधि का चयन करके, जो 5 वर्ष तथा 6 महीने की अवधि है, आईटीसी ने अनुच्छेद 2.1 तथा अनुच्छेद XIX के असंगत कार्य नहीं किया है। यह निष्कर्ष निम्नलिखित बातों पर आधारित है: पहला करार में जांच की अवधि की लम्बाई के संबंध में कोई विशिष्ट नियम नहीं दिए गए हैं; दूसरा आईटीसी द्वारा चयनित अवधि, उन्हें हाल में किए गए आयातों पर फोकस करने की अनुमति देती है, और तीसरा, आईटीसी द्वारा चयनित अवधि बढ़ते हुए आयातों के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से लंबी है। (पैरा 7.196, 7.199 तथा 7.201)<sup>1</sup>

180. उसी अमरीका-लाइप पाइप के मामले में पैनल ने यह निर्णय दिया था कि:-

'किसी रक्षोपाय जांच में, बढ़ते आयात की जांच करने के लिए जांच की अवधि वही होती है जो घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति की जांच की अवधि होती है। यह पाटनरोधी अथवा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की स्थिति के विपरीत होती है जहां पाटन अथवा सब्सिडीकरण की मौजूदगी का मूल्यांकन करने की अवधि, वास्तविक क्षति की जांच करने की अवधि से सामान्यतः कम होती है। हमारा मानना है कि इस अंतर का एक कारण यह है, जैसा कि अर्जेंटीना-फुटवियर रक्षोपाय में अपीलीय निकाय द्वारा पाया गया था, "इतनी बड़ी मात्राओं में" "आयातों की अपेक्षा का निर्धारण" किया जाना केवल एक गणितीय अथवा तकनीकी निर्धारण नहीं है। अपीलीय निकाय ने नोट किया कि जहां बढ़ते हुए आयातों के निर्धारण की बात आती है वहां "सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच की अवधि के दौरान आयातों की प्रवृत्ति पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।" आयातों की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन तथा घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के निर्धारण हेतु संगत कारकों में प्रवृत्तियों की मूल्यांकन, एक अवधि के दौरान ही किया जा सकता

<sup>1</sup> डब्ल्यूटी/डीएस202/आरडीटी, 29/10/2001 अमरीका-लाइन पाइप मामले में पैनल रिपोर्ट

है। अतः हमारा निष्कर्ष यह है कि क्षति निर्धारण के लिए संगत अवधि के संबंध में अपीलीय निकाय द्वारा व्यक्त विचार, बढ़ते हुए आयात के निर्धारण पर भी लागू होते हैं।" (पैरा 7.209)<sup>2</sup>

181. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि न तो रक्षोपाय संबंधी घरेलू कानून और न ही रक्षोपाय करार एवं गैट के अनुच्छेद XIX में जांच की अवधि के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। संगत जांच अवधि, बढ़ते हुए आयात एवं गंभीर क्षति के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त रूप से लम्बी होनी चाहिए और यह अवधि ने केवल हाल ही में समाप्त हुई अवधि होनी चाहिए बल्कि जांच की अवधि भी हाल की अवधि होनी चाहिए।

182. आवेदक ने इस मामले में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के लम्बे इतिहास के कारण यह तर्क देते हुए कि इस मामले में लम्बी अवधि पर विचार किया जाना अपेक्षित है, वर्ष 2000-01 से 2010-11 (सितम्बर, 2010) तक के आयात एवं क्षति संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। आवेदक द्वारा 2000-01 से 2010-11 (सितम्बर, 2010) तक के आयात एवं क्षति संबंधी आंकड़ों के साथ जांच शुरू करने संबंधी नोटिस जारी किया गया था। तदनन्तर, आवेदक ने अक्टूबर-सितम्बर, 2010 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। 3 महीनों से संबंधित अतिरिक्त सूचना सभी संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी और इसे रक्षोपाय नियम 1997 के नियम 6(7) के तहत अपेक्षानुसार सार्वजनिक फाइल में रखा गया था।

183. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि यह अवधि अत्यंत लम्बी है और जांच के लिए तुलनात्मक रूप से छोटी और अर्थपूर्ण अवधि पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि इससे पहले किसी भी मामले में जांच की अवधि 6 वर्ष से अधिक नहीं रही है अतः सार्थक विश्लेषण हेतु एक अपेक्षाकृत छोटी अवधि का चयन किया जाना चाहिए।

184. विचाराधीन उत्पाद के पाटन के लम्बे इतिहास, वर्ष 2005 से लागू पाटनरोधी शुल्क पर विचार करते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बढ़ते हुए आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकालने और समय-समय पर मात्रा में अंतर के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए, चयनित अवधि पर्याप्त रूप से लम्बी होनी चाहिए, एक अपेक्षाकृत लम्बी अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2005-06 से 2010-11 (दिसम्बर तक) के वार्षिक आंकड़ों पर विचार किया गया है।

### सूचना का स्रोत

185. भारत को जांचाधीन उत्पाद का आयात सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (पैरा 168 देखें) के विभिन्न शीर्षों और उपशीर्षों के तहत किया जाता है। आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आईबीआईएस के आयात आंकड़ों के आधार पर रक्षोपाय जांच की शुरुआत की गई थी। उत्पाद का विवरण दर्शाते हुए सौदेवार आयात आंकड़े अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए थे। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने एक देश विशेष से वित्त वर्ष 2009-10 में एक निश्चित मात्रा (1154 मी. टन) को शामिल न करने तथा वित्त वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 (दिसम्बर तक) के लिए आईसीडी लुधियाना, कोचीन से औसत आयात निर्धारण को स्वीकार न करने जैसे अपवादों को छोड़कर, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सौदेवार आयात आंकड़ों की सत्यता पर प्रश्न नहीं उठाया है। उन्होंने इन दो पत्तनों पर वास्तविक आयात को

<sup>2</sup> डब्ल्यूटी/डीएस202/आरडीटी, 29/10/2001 अमरीका-लाइन पाइप मामले में पैनल रिपोर्ट

सुनिश्चित करने तथा सही आयात आंकड़ों का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है। तदनुसार सीमाशुल्क प्राधिकारियों से उपर्युक्त दो पत्तों के विषय में सौदेवार आयात आंकड़े प्राप्त किए गए थे और उन्हें सार्वजनिक फाइल में रखा गया था।

186. सभी संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों पर विचार किया गया था। आईसीडी लुधियाना एवं कोचीन से प्राप्त सौदेवार आंकड़ों, जिन्हें आयात मात्रा के संशोधित आंकड़ों के साथ आईबीआईएस आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया था सहित याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आईबीआईएस के सौदेवार आयात आंकड़ों को रक्षोपाय नियम के नियम 6(7) के अनुसार सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा सत्यापन एवं टिप्पणियों हेतु कुल मांग में आयात का हिस्सा इत्यादि जैसे आर्थिक मानदण्डों के संशोधित आंकड़ों संबंधी सार्वजनिक फाइल में रखा गया था। जांच में बढ़ते आयात के आकलन हेतु संकलित सौदेवार आयात आंकड़ों पर विचार किया गया था।

187. याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन-पत्र के साथ तथा जांच के दौरान प्रस्तुत अन्य आर्थिक मानदण्डों का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था और सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय रूपांतर सभी संबंधित पक्षकारों के अवलोकनार्थ सार्वजनिक फाइल में रखा गया था। इसके अलावा, केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राधिकरण, जो केन्द्र सरकार का एक कार्यालय है, के रिकॉर्ड के अनुसार विधिवत सत्यापित उत्पाद, बिक्री, क्षमता तथा उपयोग एवं वस्तुसूची जैसे विभिन्न आर्थिक मानदण्डों के आंकड़ों पर विचार किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण मुख्य रूप से घरेलू उद्योग के संबंध में किया गया है। तथापि आयातों के बाजार हिस्से का विश्लेषण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य उद्योग के यथासंभव सीमा तक सत्यापित आंकड़ों का संदर्भ लिया गया है। इसके अलावा केआईटीए के वेबसाइट पर उपलब्ध आयात आंकड़ों तथा एटीएमए की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना का संदर्भ लिया गया है।

कार्यरत सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित लागत संबंधी आंकड़ों पर विचार किया गया है। यदि कोई अन्य सूचना प्रयुक्त की गई है तो उसके स्रोत का भी उल्लेख किया गया है।

### प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता

188. घरेलू उद्योग ने सूचना गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की है और प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय उपाय हेतु आवेदन तथा व्यापार नोटिस सं.एसजी/टीएन/1/97 दिनांक 06.09.1997 सहित सभी निवेदनों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने आवेदन प्रस्तुत करते समय और सुनवाई उपरांत लिखित निवेदनों हेतु गोपनीयता की मांग करने के कारणों का ब्योरा प्रस्तुत किया है जिसका विवेचन इस जांच परिणाम के पैरा 30 से 32 में किया गया है।

189. निर्यातकों तथा प्रयोक्ता/आयातकों जैसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी सूचना की गोपनीयता हेतु अनुरोध किया है और सभी निवेदनों का गोपनीय एवं अगोपनीय पाठ प्रस्तुत किया है। तथापि उन्होंने घरेलू उद्योग के अत्यधिक गोपनीयता के दावे पर आपत्ति की थी और तर्क प्रस्तुत किया था कि केवल आर्थिक मानदण्डों से संबंधित वास्तविक आंकड़ों पर ही सार्थक तर्क दिए जा सकते हैं, अतः इन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

190. घरेलू उद्योग के निवेदन (इस जांच परिणाम का पैरा 30 से 32) पर विचार किया गया है। इसके अलावा यह देखा जा सकता है कि समान उत्पाद की पाटनरोधी जांच में पाटनरोधी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता की अनुमति प्रदान की गई है। यह भी देखा जा सकता है कि सभी भागीदार उद्योग जांचाधीन उत्पाद के विभिन्न आर्थिक मानदण्डों की गोपनीयता बनाए रखते हैं।

191. रक्षोपाय नियमावली के नियम 7 और डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.2 में गोपनीयता का प्रावधान है। याचिकाकर्ता को ऐसी सूचना प्रकट करना अपेक्षित नहीं है, जो कम्पनी की गोपनीय सूचना है जिसके प्रकट करने से कम्पनी के व्यावसायिक हित प्रतिकूलतः प्रभावित होते हैं और जिसे याचिकाकर्ता ने विगत में जनता के समक्ष प्रकट नहीं किया है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार गोपनीयता प्रदान की जाती है।

### वर्धित आयात

192. वर्धित आयात की कानूनी अपेक्षा निम्नानुसार है:-

- 1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख: केन्द्र सरकार का रक्षोपाय शुल्क लगाने का अधिकार

यदि केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच करने पर, जिसे वह उपयुक्त समझती है, इस बात से संतुष्ट है कि भारत में किसी वस्तु का आयात ऐसी वर्धित मात्राओं में और ऐसी स्थितियों में किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होती है अथवा होने का खतरा है तो वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क लगा सकती है।

- 2) रक्षोपाय करार का अनुच्छेद/ :

1. कोई सदस्य देश किसी उत्पाद पर रक्षोपाय उपाय केवल तभी लागू कर सकता है, यदि उस सदस्य देश ने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसरण में यह निर्धारण कर लिया है कि ऐसे उत्पाद का उसके राज्यक्षेत्र में आयात घरेलू उत्पादन के निरपेक्ष अथवा सापेक्ष ऐसी वर्धित मात्राओं में और ऐसी स्थितियों के अंतर्गत किया जा रहा है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होती है अथवा होने का खतरा है जिसके कारण समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उत्पादन किया जाता है।

193. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि आयात संबंधी आंकड़ों में वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 (सितम्बर, 10 तक) में केवल 2% से 3% की वृद्धि देखी गई है और इसलिए आयात में हाल ही में हुई वृद्धि तेज अथवा उल्लेखनीय नहीं है। पैनल ने यूएस-लाइन पाइप मामले में दिए गए एक वक्तव्य में कहा था कि "हाल ही में" शब्दों से तात्पर्य भूतलक्षी विश्लेषण से है; परंतु इससे तात्पर्य प्राधिकारी के निर्णय से तुरंत पूर्व की स्थिति के विश्लेषण से नहीं है और न ही इससे यह तात्पर्य है कि विश्लेषण में जांच अवधि के अंत में ही प्रचलित स्थितियों पर विशिष्ट रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए:

"(हम) नोट करते हैं कि अर्जेंटीना-फुटवियर रक्षोपाय में अपीलीय निकाय ने यह पाया था कि 'आयात किया जा रहा है' वाक्यांश का तात्पर्य है कि आयातों में हुई वृद्धि एकाएक और हाल में हुई होनी चाहिए। कोरिया के अनुसार 'ऐसी वर्धित मात्राओं में ..... आयात किया जा रहा है' वाक्यांश से प्राधिकारी के निर्णय से तत्काल पूर्व की अवधि अभिप्रेत है। 'हाल ही में' शब्द - जिसे अपीलीय निकाय ने 'आयात किया जा रहा है' वाक्यांश की व्याख्या में प्रयुक्त किया था - को 'बहुत पहले नहीं हुआ, प्रकट हुआ, अस्तित्व में आया अथवा हाल में अस्तित्व में आया' के रूप में परिभाषित किया है। दूसरे शब्दों में 'हाल ही में' शब्द से किसी किस्म का भूतलक्षी विश्लेषण अभिप्रेत है। इससे प्राधिकारी के निर्णय से तुरंत पूर्व प्रचलित स्थितियों का विश्लेषण अभिप्रेत नहीं है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि विश्लेषण में विशिष्ट रूप से जांच अवधि के अंत में व्याप्त स्थितियों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। हमारा विचार है कि ऐसा विश्लेषण जिसमें वर्ष 1998 के पूर्वार्द्ध की तुलना 1999 के पूर्वार्द्ध से की गई हो, उस ओक्षा के प्रतिकूल नहीं है जिसमें कहा गया है कि आयातों में वृद्धि 'हाल ही में' हुई हो। (पैरा 7.204)<sup>3</sup>

194. यूएस-स्टील रक्षोपाय मामले में अपीलीय निकाय द्वारा बरकरार रखे गए जांच परिणाम में पैनल ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि आयातों में वृद्धि कब हुई होनी चाहिए और कहा था कि:-

"जैसा कि यूएस-लाइन पाइप मामले में पैनल ने किया था, कि रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 में किसी उत्पाद का उल्लेख किया गया है, 'जिसका आयात ऐसी वर्धित मात्राओं में ..... किया जा रहा है।' इस प्रकार यह जरूरी नहीं कि आयातों में वृद्धि निर्धारण के समय हो रही हो; बल्कि जरूरी यह है कि आयातों में वृद्धि हुई है, यदि उत्पादों का आयात (ऐसी) वर्धित मात्राओं में 'किया जा रहा है'। अतः पैनल यूएस-लाइन पाइप पैनल के इस विचार से सहमत है कि यह बात कि आयातों में वृद्धि 'हाल ही में' हुई होनी चाहिए से यह अभिप्राय नहीं है कि यह जांच प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण की अवधि से तुरंत पूर्व की अवधि तक जारी रहनी चाहिए और न ही जांच की अवधि के अंत तक। जैसाकि यूएस-लाइन पाइप में पैनल ने उल्लेख किया है, हाल ही के आंकड़ों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, परंतु जांच अवधि की हाल की अवधि से संबंधित आंकड़ों से इसे अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। तथापि जैसा कि 'किए जा रहे हैं' से स्पष्ट है कि इस समय तात्पर्य आयातों के उच्चतर (अर्थात् वर्धित) स्तर पर होने से है।

अतः, क्या अलग-अलग मामले में जांच अवधि के अंत में आयातों में कमी रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 की भावना के अनुसार वर्धित आयातों के प्रतिकूल है, यह इस बात पर निर्भर होगा कि क्या परवर्ती कमी के बावजूद पूर्ववर्ती वृद्धि की परिणति उस उत्पाद की (ऐसी) वर्धित मात्राओं में आयात में (अभी भी) हो रही है। इस मूल्यांकन में जिन कारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए वे जांच की प्रासंगिक अवधि के अंत में कमी की अवधि एवं तीव्रता तथा उसका स्वरूप, उदाहरणार्थ पहले हुई वृद्धि की तीव्रता एवं सीमा हैं।

<sup>3</sup> डब्ल्यूटी/डीएस2001/आरबीटी, 29/10/2001 अमरीका-लाइन पाइप मामले में पैनल रिपोर्ट

चरम स्थिति के उदाहरणार्थ लघु एवं हाल ही में हुई मामूल कमी, समग्र वृद्धि से अलग नहीं होगी, यदि पूर्ववर्ती अनेक वर्षों के दौरान आयातों में दस गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके विपरीत विलोम चरम स्थिति के उदाहरण के रूप में हम किसी उत्पाद के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, जिसका आयात "(ऐसी) वर्धित मात्राओं में किया जा रहा है" अथवा वास्तव में इतनी वर्धित मात्राओं में किया जा रहा है, यदि निर्धारण के समय आयात की संख्या घटकर लगभग शून्य हो गई है अथवा जांच अवधि में विगत किसी समय से निचले स्तर पर आ गई है। (पैरा 10.162 से 10.165<sup>4</sup>)

195. यूएस-स्टील रक्षोपाय में ही अपीलीय निकाय ने पुष्टि की थी कि यह जरूरी नहीं कि निर्धारण के समय आयातों में वृद्धि हो और जांच की अवधि के दौरान आयातों की प्रवृत्ति की जांच के बारे में जांच अधिकारी के दायित्व पर जोर दिया था:-

"हम यूनाइटेड स्टेट्स से सहमत हैं कि अनुच्छेद 2.1 में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि निर्धारण के समय आयातों में वृद्धि होनी जरूरी है। बल्कि "ऐसी वर्धित मात्राओं में आयात किया जा रहा है" वाक्यांश का सरल तात्पर्य केवल इतना है कि आयातों में वृद्धि हुई होगी और संबंधित उत्पादों का (इतनी) वर्धित मात्राओं में आयात किया जाना जारी है। हम यह भी नहीं मानते हैं कि जांच अवधि के अन्त में आयातों में कमी जांच प्राधिकारी को यह जांच करने से रोकेगी कि इसके बावजूद उत्पादों का आयात इतनी वर्धित मात्राओं में किया जा रहा है।" (पैरा 367)<sup>5</sup>

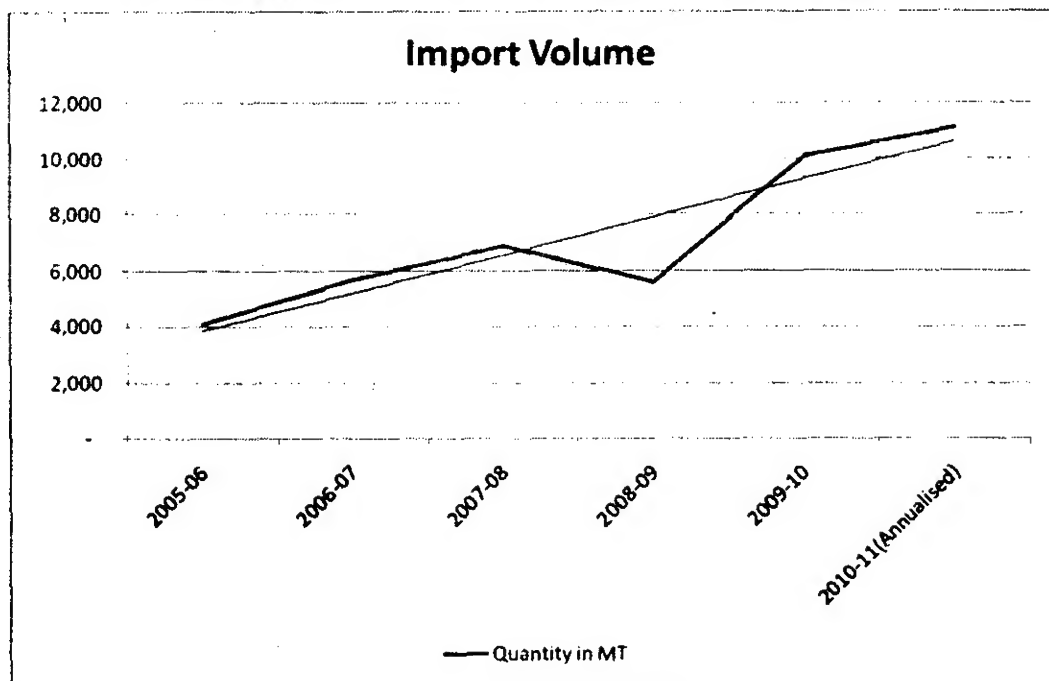
196. निम्नलिखित तालिका में जांच अवधि अर्थात् 2005-06 से 2010-11 (दिसम्बर तक) के आयात संबंधी आंकड़े दर्शाए गए हैं :-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	मात्रा मी. टन में	वृद्धि मी. टन में
1.	2005-06	4,077	
2.	2006-07	5,652	1,575
3.	2007-08	6,860	1,208
4.	2008-09	5,606	-1,254
5.	2009-10	10,090	4,483
6.	2010-11(वार्षिकीकृत)	11,109	1,020
7.	2010-11 (दिसम्बर, 2010 तक)	8,332	
	वर्ष 2005-06 से समग्र वृद्धि	7,032	

आयात की मात्रा

<sup>4</sup> डब्ल्यूटी/डीएस248/आर दिनांक 11/07/2003 यूएस स्टील रक्षोपाय मामले से संबंधित पैनल रिपोर्ट

<sup>5</sup> डब्ल्यूटी/डीएस 248-54/एबी/आर एण्ड डब्ल्यूटी/डीएस 258-59/एबी/आर यूएस स्टील रक्षोपाय मामले से संबंधित अपीलीय निकाय रिपोर्ट



197. आयात से संबंधित उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि आधार वर्ष 2005-06 के संदर्भ में आयातों में वर्ष 2010-11 (दिसम्बर 10 तक) 172% की वृद्धि हुई है।

198. आयातों की अन्तर्वर्ती प्रवृत्ति: आयातों में 2005-06 की तुलना में 2006-07 के दौरान 39% की वृद्धि हुई और 2007-08 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि हुई। वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान आयात में 18% की गिरावट आई थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान आई अस्थायी गिरावट उस वर्ष कोरिया व चीन से किए गए आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के कारण आई थी, जो जांचाधीन उत्पाद के प्रमुख निर्यातक देश हैं। निम्नलिखित तालिका में कोरिया व चीन से किए गए आयातों से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं :-

**चीन और कोरिया से 6 पीपीडी का आयात**

वित्तीय वर्ष	चीन से किया गया आयात (मी. टन)	कोरिया से किया गया आयात (मी. टन)
2006-07	1570	3336
2007-08	3287	3158
2008-09	1795	2980
2009-10	1831	6030
2010-11( दिसम्बर तक)	1258	5328

199. वर्ष 2007-08 में कोरिया और चीन से जांचाधीन उत्पाद का निर्यात लगभग एक समान वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान कोरिया और चीन से कुल आयात में 26% की कमी आई थी। कोरिया से कमी 5% से कम थी। तथापि वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 के दौरान



कुल आयात में अचानक एवं अत्यधिक वृद्धि हुई और यह 5606 मी. टन बढ़कर 10,090 मी. टन (79.98%) हो गया था। उल्लिखित 4483 मी. टन की कुल वृद्धि में कोरिया का योगदान 3050 मी. टन और चीन का योगदान केवल 36 मी. टन का था। वित्तीय वर्ष 2008-09 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद कोरिया से आयात में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान 102% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2010-11 (दिसम्बर तक) में भी जारी रही।

200. आयात में तुलनात्मक वृद्धि - भारतीय उत्पादन की तुलना में आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	उत्पादन की तुलना में आयात (सूचीबद्ध)	उत्पादन की तुलना में आयात (% में)
2005-06	100	88.74
2006-07	153	135.60
2007-08	124	109.60
2008-09	100	88.43
2009-10	157	139.02
2010-11 (दिसम्बर तक) वार्षिकीकृत	207	184.87

201. उत्पादन की तुलना में आयात में वृद्धि हुई है और वर्ष 2010-11 में यह शीर्ष स्तर तक पहुँच गया है। भारतीय उत्पादन की तुलना में आयात में आधार वर्ष की तुलना में 96% की वृद्धि हुई है। उत्पादन की तुलना में आयात में वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में 51% और वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान 45% की वृद्धि हुई है।

202. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह अभिमत व्यक्त किया जाता है कि आयातों में वृद्धि निरपेक्ष तथा तुलनात्मक रूप से हुई थी और आयात में हुई वृद्धि हाल ही में हुई थी, एकाएक हुई थी और तेजी से हुई थी।

### अप्रत्याशित घटनाक्रम

203. अर्जेंटीना - फुटवियर (ईसी मामला) में अपीलीय निकाय ने अभिमत व्यक्त किया है कि अप्रत्याशित घटनाक्रम शब्द से तात्पर्य उन घटनाओं से हैं जो अप्रत्याशित थीं। 'अप्रत्याशित घटनाक्रम' से वह घटनाक्रम अपेक्षित है जिसमें उत्पाद का आयात ऐसी मात्रा में तथा ऐसी स्थितियों में किया जाता है, जिससे घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई हो अथवा होने का खतरा हो जो 'अप्रत्याशित' हो। निकाय ने इसी मामले में गैट पैनल की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया था जिसमें कहा गया था कि टैरिफ वार्ता के दौरान घटनाक्रम अप्रत्याशित रहा होना चाहिए। अपीलीय निकाय ने कोरिया - डेयरी मामले<sup>6</sup> में अभिमत दिया था कि अप्रत्याशित घटनाक्रम वह घटनाक्रम होता है जब सदस्य देश ने वचनबद्धता की थी और तब वह घटनाक्रम उसके लिए प्रत्याशित अथवा आशान्वित नहीं था।

<sup>6</sup> कोरिया डेयरी मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का पैरा 86

204. अपीलीय निकाय ने अर्जेंटीना-फुटवियर (ईसी) मामले में अभिमत दिया था कि 'अप्रत्याशित घटनाक्रम' की अपेक्षा से रक्षोपाय उपाय लागू करने की 'स्थिति' अलग से सिद्ध नहीं होती परंतु निकाय ने कतिपय 'घटनाक्रमों' का उल्लेख किया था ।

205. यूएस-स्टील रक्षोपाय संबंधी पैनल का निष्कर्ष था कि अनेक घटनाओं का मिला-जुला रूप अप्रत्याशित घटनाक्रम का आधार निर्मित करता है:-

'यूनाइटेड स्टेट्स ने तर्क दिया है कि अमरीकी डॉलर में आई मजबूती एक ऐसा घटनाक्रम था, जिसके साथ हुई अन्य घटनाओं जैसे एशिया तथा पूर्व सोवियत संघ में नकदी संकट और अन्य बाजारों में गिरावट आने पर यूनाइटेड स्टेट्स में इस्पात की मांग में लगातार वृद्धि के कारण आयातों में वृद्धि हुई थी ।'

206. याचिकाकर्ता ने दो घटनाओं का उल्लेख किया है जो अप्रत्याशित घटनाक्रम हैं अर्थात् (क) केकेपीसी एवं साइनऑर्गकेम के बीच विशेष संबंध और (ख) वैश्विक बाजार में मंदी जिसके कारण विकसित देशों और चीन में उत्पाद की मांग में उल्लेखनीय गिरावट । याचिकाकर्ता ने इनका साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है (इस जांच परिणाम का पैरा 27 देखें) ।

207. यह नोट किया जाता है कि कोरिया कुम्हो की वर्ष 2009 की वार्षिक रिपोर्ट में मेसर्स साइनऑर्गकेम के साथ विशेष संबंध का उल्लेख है:

-हमारे स्पेशियलिटी रसायन व्यवसाय - जो 6पीपीडी की उत्पादन क्षमता के संदर्भ में उद्योग जगत में अग्रणी स्थान पर है - में चीन के प्रतिस्पर्धियों द्वारा कीमत कम रखने की कार्यनीति अपनाए जाने के कारण बिक्री में और कीमतों में गिरावट आई है । फीडस्टॉक बाजार में 4एडीपीए की कमी और फीडस्टॉक की आपूर्ति करने वाले साइनऑर्गकेम के साथ अपने विशेष संबंध के कारण चीन के बाजार में प्रवेश की हमारी क्षमता पर प्रतिबंध के कारण प्रचालन दर में गिरावट आई, जिसके कारण लाभप्रदता और अधिक प्रभावित हुई ।

208. चीन और कोरिया से आयातित वस्तुओं पर वित्तीय वर्ष 2008-09<sup>7</sup> के दौरान क्रमशः 42.70 रूपए/किग्रा. तथा 10.35 रूपए/किग्रा. की दर से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । नीचे दी गई तालिका में कोरिया के आयात आंकड़ों में उसी वित्तीय वर्ष अर्थात् 2008-09 के बाद 4एडीपीए, जो 6 पीपीडी हेतु उपांत्य मध्यवर्ती अवस्था है, के आयातों में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है ।

209. इसके अलावा चीन से कोरिया में 4एडीपीए के आयात की इकाई कीमत कमी आई और यह वर्ष 2008-09 में 3.54 अम.डॉलर/किग्रा. से घटकर 2.68 अम.डॉलर/किग्रा. रह गई थी, जबकि चीन पर उच्चतर दर पर पाटनरोधी शुल्क इसी वर्ष लगाया गया था ।

#### कोरिया से चीन में 4 एडीपीए का आयात

वित्तीय वर्ष	मात्रा मी. टन में	दर अम.डॉलर/किग्रा. में
--------------	-------------------	------------------------

<sup>7</sup> वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. .... एनटी दिनांक .....

क्र.सं.			
1	2005-06	10815	3.20
2	2006-07	11492	2.57
3	2007-08	15465	2.67
4	2008-09	23631	3.54
5	2009-10	23118	2.68
6.	2010-11( सितम्बर तक)	13036	2.69

स्रोत: कोरिया सीमाशुल्क आंकड़े (केआईटीए साईट)

210. ईयू तथा चीन से 4 एडीपीए की इकाई आयात कीमत का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि कोरिया से चीन में 4 एडीपीए की आयात कीमत चीन और ईयू से भारत में इसी वस्तु की आयात कीमत से बहुत कम है। इसके अलावा चीन से कोरिया में 4 एडीपीए के आयात में वृद्धि भारत में चीन के आयातों पर उच्चतर दर पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने वाले वर्ष अर्थात् 2008-09 में हुई थी।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	ईयू से अम.डॉलर/ किग्रा. दर	चीन से अम.डॉलर/ किग्रा. दर
1	2006-07	3.09	2.85
2	2007-08	3.13	3.02
3	2008-09	3.83	3.88
4	2009-10		2.91
5	2010-11( सितम्बर तक)	3.10	2.94

यह देखा गया है कि केकेपीसी के पास उपलब्ध क्षमता कोरिया में मांग की तुलना में अधिक है। बेशी क्षमता के बावजूद उक्त कम्पनी ने 70,000 मी. टन तक क्षमता का विस्तार किया है, जो कोरिया की कुल मांग की तुलना में भी काफी अधिक है। निर्यात बाजार तथा अतिरिक्त बाजार अवसरों हेतु बढ़ाई यह क्षमता कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को न्यायोचित ठहराने के लिए अपेक्षित होगी।

211. इस जांच परिणाम के पैरा 198 में दी गई तालिका में कोरिया तथा चीन से भारत में जांचाधीन उत्पाद के आयात संबंधी आंकड़े दर्शाए गए हैं। यह देखा गया है कि चीन से आयातित जांचाधीन उत्पाद पर उच्चतर दर पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कोरिया से आयातों में 3050 मी. टन (102%) की वृद्धि हुई और चीन से हुए आयातों में तेजी से गिरावट आई।

212. विश्वव्यापी मंदी के दौरान ऑटोमोबाइल उद्योग पर आए संकट के कारण शेष विश्व (मुख्यतः अमेरीका, ईयू तथा चीन) में टायरों और ट्यूबों की मांग में गिरावट आई थी। तथापि भारत में टायर व ट्यूबों के उत्पादन<sup>8</sup> से संबंधित आंकड़ों से यह देखा गया कि विश्वव्यापी मंदी के दौरान भी भारत में टायर व ट्यूबों के उत्पादन में वृद्धि हुई। नीचे दिए गए आंकड़े वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2005-06 की तुलना में निरंतर वृद्धि दर्शाते हैं। वर्ष 2005-06 की तुलना में टायरों के उत्पादन में 62% और ट्यूबों के उत्पादन में 52% की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप

<sup>8</sup> स्रोत: अखिल भारतीय टायर विनिर्माता एसोसिएशन की वेबसाइट

पीएक्स-13 की मांग में शेष विश्व की तुलना में भारत में अत्यधिक वृद्धि हुई और भस्त में इसके आयातों में वृद्धि हुई ।

#### टायर एवं ट्यूब का कुल उत्पादन

वित्तीय वर्ष	टायरों का उत्पादन 000 नग में	ट्यूबों का उत्पादन 000 नग में
2005-06	60032	53421
2006-07	73545	62326
2007-08	81103	70810
2008-09	82107	69733
2009-10	97137	81448

214. उपर्युक्त घटनाक्रम अप्रत्याशित है और इससे मांग-आपूर्ति का अनुपात बदल गया और घरेलू एवं आयातित वस्तुओं के बीच कीमत में अंतर उत्पन्न हुआ जिसकी परिणति वस्तुओं के आयातों में वृद्धि में हुई ।

#### गंभीर क्षति और गंभीर क्षति का खतरा

215. **सांविधिक कार्य ढांचा :** "गंभीर क्षति " से घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र विकृति पैदा करने वाली कोई क्षति अभिप्रेत है ;<sup>9</sup> और "गंभीर क्षति के खतरे" से गंभीर क्षति का स्पष्ट और आसन्नवर्ती खतरा अभिप्रेत है ।<sup>10</sup>

216. पैनल ने अमरीका - आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ताजे शीतित अथवा प्रशीतित मैमना मांस के मामले में यह निर्णय दिया कि <sup>11</sup> :

हम नोट करते हैं कि हमारी राय में रक्षोपाय अनुच्छेद 4.1 (ख) और 4.2(क) के अंतर्गत सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारी के लिए यह प्रदर्शित करना अपेक्षित नहीं है कि प्रत्येक सूचीबद्ध क्षति कारक में गिरावट आ रही है अर्थात् गंभीर क्षति अथवा उसके खतरे की स्थिति उत्पन्न हो रही है । सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकारी के लिए समग्र रूप में क्षति कारकों के घटनाक्रमों के आरोप में अपना निर्धारण करना अपेक्षित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संगत उद्योग आसन्नवर्ती उद्योग की स्थितियों में "समग्र अत्यधिक विकृति" का सामना कर रहा है । हम अर्जेन्टीना-फुटवियर के मामले में अपीलीय निकाय के इस वक्तव्य से सहमत हैं कि :

"ऐसा तभी होता है जब उक्त उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उद्योग की स्थिति में "पर्याप्त समग्र विकृति" उत्पन्न हुई है --- प्रत्येक सूचीबद्ध कारक के मूल्यांकन में इस बात को प्रदर्शित करना अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक ऐसे कारक में "गिरावट" आ रही है । उदाहरणार्थ किसी एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पादकता

<sup>9</sup> सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (6) (ग)

<sup>10</sup> सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख (6) (घ)

<sup>11</sup> अमरीका - आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ताजे शीतित अथवा प्रशीतित मैमना मांस के मामले में पैनल रिपोर्ट डब्ल्यू टी/डी एस 1775178/आर दिनांक 21-12-2000 का पैरा 7.203

में पर्याप्त गिरावट आ सकती है जिससे उद्योग की स्थिति में "पर्याप्त समग्र विकृति का पता चलेगा और इसलिए गंभीर क्षति के जांच परिणाम को न्यायोचित ठहराया जाएगा । दूसरे मामले में कुछ कारकों में गिरावट नहीं आ सकती है परंतु इसके बावजूद समग्र स्थिति से घरेलू उद्योग की "पर्याप्त समग्र विकृति" का पता चल सकता है । "

217. यह देखा जाता है कि - रक्षोपाय करार के अनुच्छे 4.2 (क) और सी.शु.टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान और निर्धारण) नियम 1997 के नियम 8 के अनुबंध में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि कि कुछेक सूचीबद्ध कारकों और अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण किया जा सके । तथापि, इन उपबंधों में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि ऐसे किसी मूल्यांकन में इस बात का प्रदर्शन किया जाना चाहिए कि ऐसा कोई मूल्यांकन किसी विशेष मामले के तथ्यों और संबंधित उद्योग की स्थिति पर निर्भर रहते हुए अलग-अलग मामलों में अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग-अलग होगा । प्रत्येक सूचीबद्ध कारक के मूल्यांकन में अनिवार्यतः यह प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे प्रत्येक कारक में "गिरावट" आ रही है । उदाहरणार्थ एक मामले में बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में पर्याप्त गिरावट आ सकती है जिससे उद्योग की स्थिति में "पर्याप्त समग्र विकृति का पता चलेगा और इसलिए गंभीर क्षति के जांच परिणाम को न्यायोचित ठहराया जाएगा । दूसरे मामले में कुछ कारकों में गिरावट नहीं आ सकती है परंतु इसके बावजूद समग्र स्थिति से घरेलू उद्योग की "पर्याप्त समग्र विकृति" का पता चल सकता है । इस प्रकार समस्त सूचीबद्ध कारकों और किसी अन्य संगत कारक की तकनीकी जांच के अलावा यह जरूरी है कि उक्त उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाए ।<sup>12</sup>

218. तदनुसार गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का विश्लेषण करने में नियमों में उल्लिखित सभी कारकों और गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के निर्धारण के लिए संगत अन्य कारकों पर विचार किया गया है । किसी भी कारक को अप्रभावी नहीं माना गया है । संगत कारोबार चक्र के भीतर समस्त संगत कारकों और प्रभावित उद्योग के लिए संगत प्रतिस्पर्धा की स्थितियों पर विचार किया गया है । गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण उक्त उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत कारकों के मद्देनजर घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है ।

219. संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा ले लिया है : तालिका में भारतीय उद्योगों का हिस्सा और भारतीय बाजार में हुए आयात निहित हैं ।

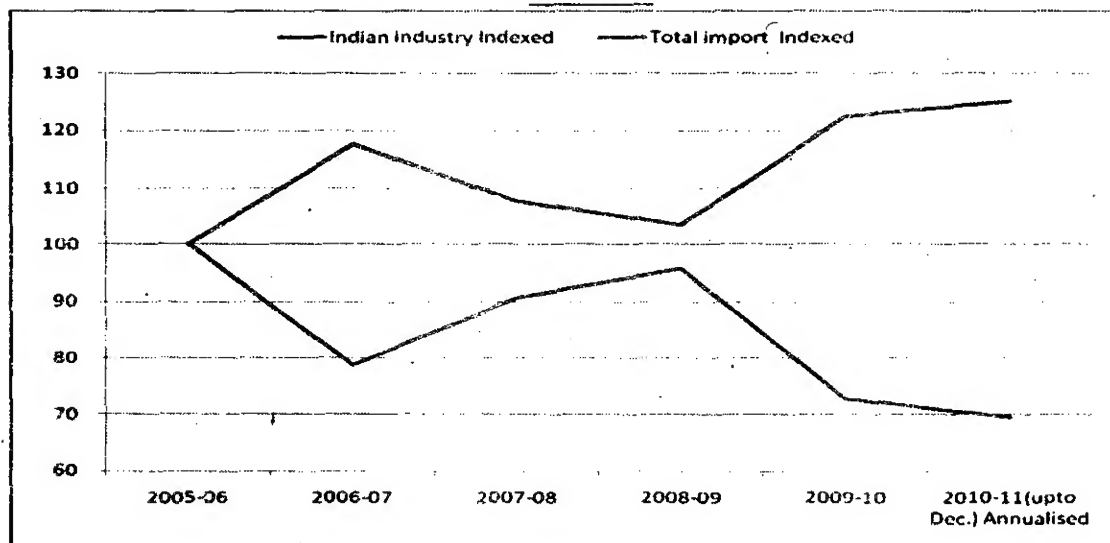
तालिका 7

वित्त वर्ष	कुल बाजार क्षेत्र में भारतीय उद्योग का हिस्सा % (सूचीबद्ध)	कुल बाजार क्षेत्र में आयात का हिस्सा %	कुल बाजार क्षेत्र में घ. उ. का % हिस्सा (सूचीबद्ध)
2005-06	100	54.92	100

<sup>12</sup> अर्जेन्टीना फुटबियर मामले में डब्ल्यू टी ओ के अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के पैरा 139 पर आधारित ।

2006-07	79	64.57	60
2007-08	91	59.19	62
2008-09	96	56.83	70
2009-10	73	67.21	69
2010-11(दिस. तक.) वार्षिक	69	68.92	66

रेखाचित्र -2



220. उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2008-09 को छोड़कर जब कोरिया और चीन से हुए आयातों को छोड़कर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, भारतीय उद्योग के हिस्से में गिरावट आ रही है और आयातों का हिस्सा बढ़ रहा है। आधार वर्ष की तुलना में भारतीय उद्योग के हिस्से में \*\* और वर्ष 2008-09 की तुलना में \*\* की गिरावट आई है। भारतीय उद्योग ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 में प्रमुख हिस्सा गंवाया है जब आयातों में तेजी से वृद्धि हुई थी। आवेदक घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष के \*\* की तुलना में \*\*% हिस्सा गंवाया है और वह 2010-11 में घटकर \*\*% हो गया है।

221. बाजार हिस्सा संवर्धित आयातों के कारण गंवाया गया है।

222. निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग की बिक्री, कुल मांग और मांग के प्रतिशत के रूप में बिक्री निहित है :

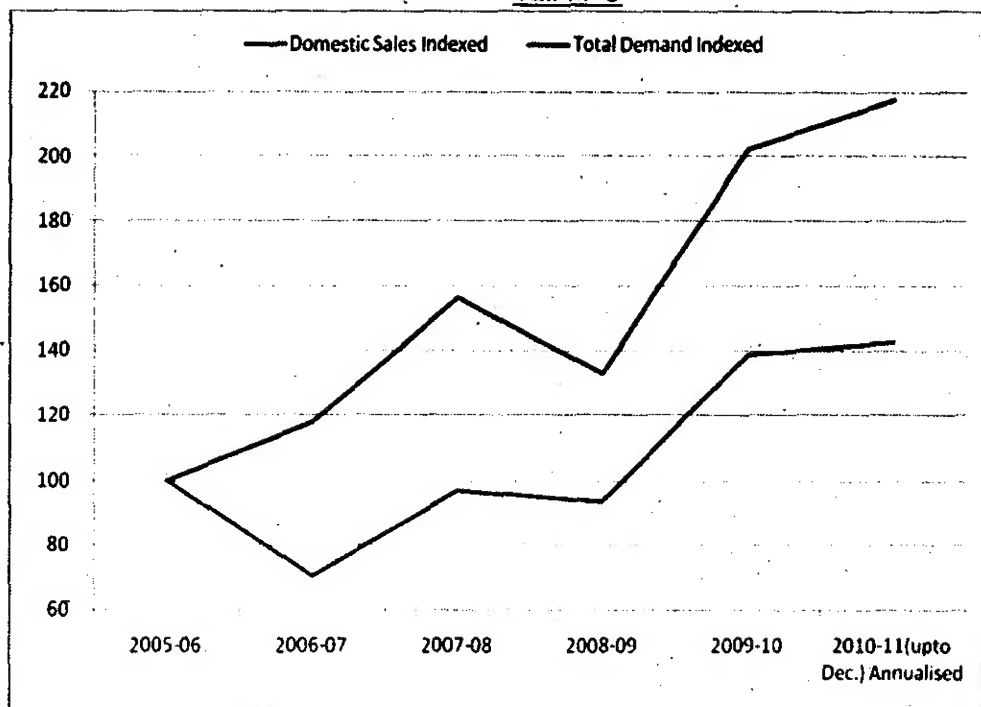
तालिका-8

सूचीबद्ध

वित्तीय वर्ष	म.उ. द्वारा बिक्री	कुल मांग	बिक्री के रूप में मांग का %
2005-06	100	100	100

2006-07	70	118	60
2007-08	97	156	62
2008-09	93	133	70
2009-10	139	202	69
2010-11(दिसंबर तक.) वार्षिकीकृत	143	217	66

रेखाचित्र -3



223 वर्ष 2005-06 से जांचाधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है परंतु घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है। तथापि, वर्ष 2008-09 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि शुरू हुई। बिक्री में हुई वृद्धि घरेलू मांग में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है। जिसे वर्ष 2008-09 के बाद संवर्धित आयातों ने ले लिया है।

224. निम्नलिखित तालिका में पाटनरोधी शुल्क के साथ आयात की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत दर्शायी गई है।

तालिका-9

वित्तीय वर्ष	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11 (दिसं. तक)
पाटनरोधी शुल्क सहित आयातों की पहुंच कीमत (रु./किग्रा.)	229.73	192.66	147.02	247.29	192.59	189.84
घरेलू उद्योग की घरेलू	100	90	82	113	103	103

बिक्री कीमत (रु./किग्रा.)						
घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत	100	90	79	110	93	89

225. उपर्युक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्ष 2008-09 के बाद हुए आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम पर हो रहे थे और यह कीमत घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत से भी कम थी। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कम कीमत पर संवर्धित आयातों के कारण उच्च घरेलू मांग के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री प्रभावित हुई है।

226. उत्पादन:- निम्नलिखित तालिका में वार्षिक आधार पर जांचाधीन उत्पाद का उत्पादन दर्शाया गया है।

तालिका-10

सूचीबद्ध

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	उत्पादन क्षमता(म.ट.)	उत्पादन मी.ट. में
1	2005-06	100	100
2	2006-07	104	91
3	2007-08	140	136
4	2008-09	140	138
5	2009-10	149	158
6	2010-11(दिसं. तक.) वार्षिकीकृत	149	131

227. पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2006-07 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई। तत्पश्चात घरेलू बाजार में जांचाधीन उत्पाद की मांग वर्ष 2009-10 में \*\*\* मी.ट. से बढ़कर \*\*\* मी.ट. हो जाने के कारण घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की। तथापि, मांग में हुई उच्च वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का उत्पादन क्षमता के अनुरूप नहीं रहा। आयात में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पादन वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 में घटकर \*\*\*% हो गया।

228. घरेलू बाजार में मांग के संदर्भ में जांचाधीन उत्पाद का क्षमता उपयोग निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-11

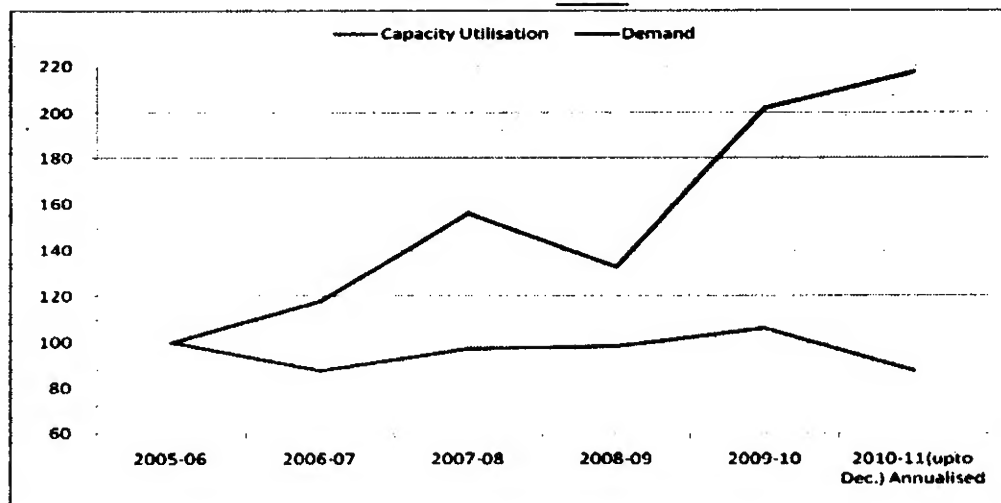
वित्तीय वर्ष	क्षमता उपयोग % में (सूचीबद्ध)	मांग मी.ट. में
2005-06	100	7,424
2006-07	88	8,753
2007-08	97	11,590



2008-09	98	9,864
2009-10	106	15,011
2010-11(दिसं. तक.) वार्षिकीकृत	88	16,117

229. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में मांग में \*\*\*% की वृद्धि होने के बावजूद आधार वर्ष से \*\*\*% और वर्ष 2009-10 से 2010-11 में \*\*\*% की गिरावट आई। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। मांग में वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग में गिरावट संवर्धित आयातों के कारण आई है।

ग्राफ-4



230. निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग द्वारा गंवाए गए उत्पादन घंटों के आंकड़े दिए गए हैं। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर सका और वर्ष 2010-11 में उत्पादन घाटा सबसे अधिक रहा है।

तालिका-12

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
गंवाए गए उत्पादन घंटे	100	780	297	947
गंवाया गया उत्पादन मीट. में	100	780	297	948

231. मालसूची: निम्नलिखित तालिका में वार्षिक आधार पर औसत मालसूची दर्शायी गई है। इसके अलावा, निम्नलिखित ग्राफ वार्षिक औसत मालसूची तथा वार्षिक उत्पादन के आंकड़े सूचीबद्ध रूप में लेते हुए तैयार किया गया है।

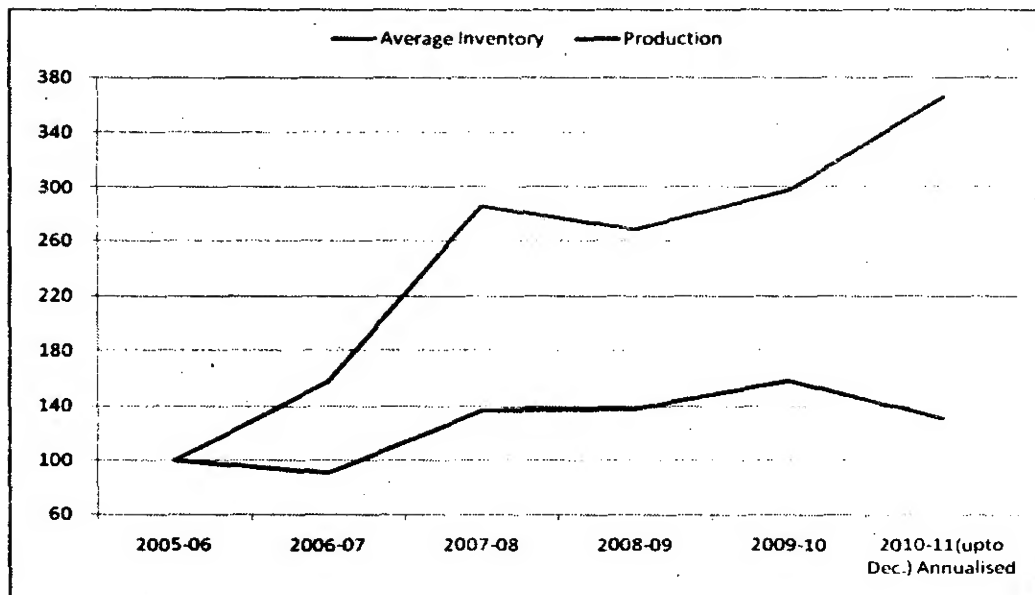
तालिका-13

सूचीबद्ध

क्रसं	वित्तीय वर्ष	औसत मालसूची	उत्पादन
1	2005-06	100	100
2	2006-07	157	91

3	2007-08	286	136
4	2008-09	268	138
5	2009-10	298	158
6	2010-11(दिसं. तक.) वार्षिकीकृत	365	131

ग्राफ-5



232. उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में वर्ष 2005-06 से वृद्धि हो रही है। मालसूची में यह वृद्धि वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में जारी रही। मालसूची में 2009-10 की तुलना में जब इसी अवधि के दौरान उत्पादन में \*\*\*% की गिरावट आई थी, वर्ष 2010-11 में \*\*\*% की वृद्धि हुई।

233. मालसूची में वृद्धि कम कीमत पर संवर्धित आयातों के कारण हुई है।

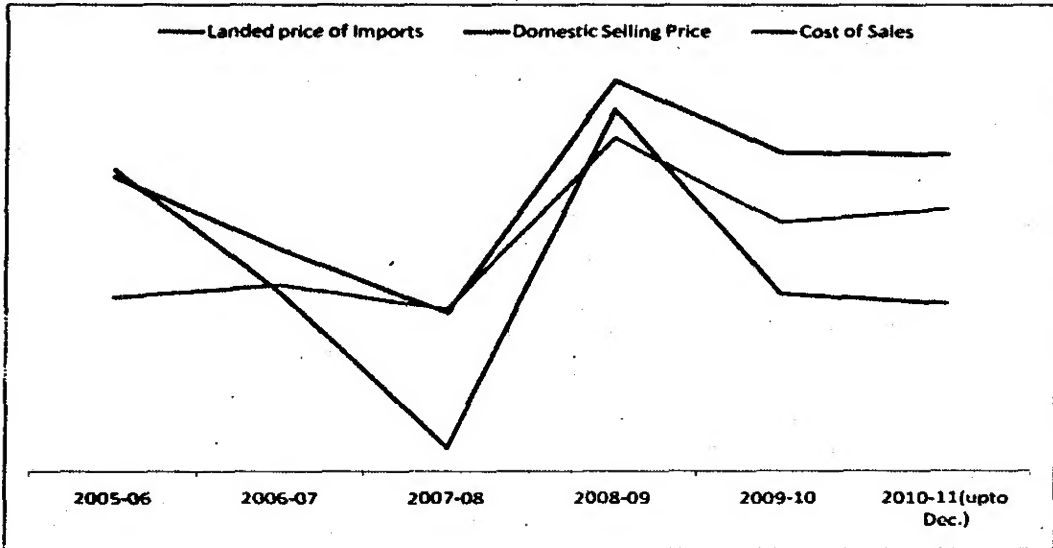
234. **कीमत प्रभाव :** यह तर्क दिया गया है कि कीमत रक्षोपाय जांच में विचारार्थ कोई संगत कारक नहीं है। आयात किस कीमत पर हो रहे हैं वह कारक संगत नहीं है क्योंकि यह अनुचित प्रतिस्पर्धा नहीं है जो रक्षोपाय कार्रवाई की विषय वस्तु है। परंतु यह घरेलू उत्पादकों को संवर्धित आयातों के कारण मिली पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है भले ही आयात उचित कीमत पर हो रहे हों। इसी संदर्भ में आयात कीमत संगत नहीं है। तथापि, जब गंभीर क्षति अथवा बाजार विकृति अथवा उसके खतरे का निर्धारण किया जाता है, तब कानून में घरेलू उत्पादकों की बिक्री, उत्पादकता आदि के स्तर में परिवर्तन की जांच अपेक्षित होती है। ये कारक निस्संदेह प्रतिस्पर्धी उत्पादों की कीमत पर निर्भर होते हैं और इस संदर्भ में आयात कीमत प्रासंगिक बन जाती है और खासकर घरेलू उद्योग की स्थिति पर उनके प्रभाव का निर्धारण करने और आयात में वृद्धि के कारणों को जानने के लिए जांच अपेक्षित होती है।

235. निम्नलिखित तालिका में पाटनरोधी शुल्क के साथ आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत दर्शायी गई है ।

तालिका-14

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आयात की सी आई एफ कीमत	आयातों की पहुंच कीमत पाटनरोधी शुल्क सहित	घ.उ. की बिक्री कीमत (सूचीबद्ध)	घ.उ. की बिक्री लागत (सूचीबद्ध)
1.	2005-06	198.98	229.73	100	100
2.	2006-07	167.28	192.66	90	102
3.	2007-08	135.55	147.02	82	98
4.	2008-09	205.66	247.29	113	125
5.	2009-10	162.14	192.59	103	112
6.	2010-11(दिसं. तक.) वार्षिकीकृत	161.98	189.84	103	114

ग्राफ -6



236. पाटनरोधी शुल्क (केवल ई यू तथा ताइवान से हुए आयातों का) के साथ आयात की वार्षिक औसत पहुंच कीमत में वर्ष 2005-06 से गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो गई है । कोरिया तथा चीन से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद पाटनरोधी शुल्क के साथ आयात की पहुंच कीमत में सुधार हुआ था । तथापि, कीमत में आगे और गिरावट आई और वह वर्ष 2009-

10 तथा 2010-11 में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के स्तर से कम हो गई । इसकी वजह से वर्ष 2009-10 से घरेलू उत्पादकों की कीमत में कमी आई ।

237. घरेलू बिक्री कीमत में सतत हास घरेलू उद्योग को हो रही क्षति का एक संकेतक है जिसके कारण आयातों की वजह से बाजार हिस्से का नुकसान हुआ । आयातों के कारण वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के बावजूद कीमत में भारी कटौती हो रही है ।

238. बिक्री लागत में वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक \*\*\* रुपए/किग्रा. की वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में केवल \*\*\* रुपए/किग्रा. की वृद्धि हुई परंतु पाटनरोधी शुल्क के साथ सी आई एफ आयात कीमत में 36.85 रुपए/किग्रा. की गिरावट आई और पहुंच कीमत में 37.14 रुपए/किग्रा. की कमी आई । इसके अलावा, चालू वर्ष 2010-11 में वर्ष 2005-06 की तुलना में लागत में \*\*\* रुपए/किग्रा. की वृद्धि हुई परंतु बिक्री कीमत में केवल \*\*\* रुपए/किग्रा. की वृद्धि हुई और पाटनरोधी शुल्क के साथ सी आई एफ आयात कीमत में 37 रुपए/किग्रा. और आयात की पहुंच कीमत में 39.89 रुपए/किग्रा. की कमी आई । कम कीमत पर संवर्धित आयात के कारण घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी घरेलू बिक्री कीमत नहीं बढ़ा सका ।

239. आयात कीमत और घरेलू बिक्री कीमत में अंतर इतना अधिक है कि आयात लाभदायक बन गए और संवर्धित आयात का खतरा उत्पन्न हो गया ।

240. लाभ/हानि : निम्नलिखित तालिका में लाभ/हानि तथा लगाई गई पूंजी पर आय दर्शायी गई है ।

तालिका-15

सूचीबद्ध

वित्तीय वर्ष	लाभ/हानि रु./किग्रा में	लगाई गई पूंजी पर आय % में
2005-06	100	100
2006-07	29	20
2007-08	(3)	(1)
2008-09	48	47
2009-10	57	53
2010-11 (दिसं. तक.)	45	39

241. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2007-08 तक लगातार गिरावट आई । तत्पश्चात वर्ष 2008-09 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण इसमें सुधार हुआ जब आयातों में गिरावट आई थी । उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू हुई और वित्त वर्ष 2010-11 में लाभ में वर्ष 2009-10 की तुलना में और अधिक गिरावट आई तथा यह 2008-09 के स्तर से कम हो गया । घरेलू उद्योग वर्ष 2005-06 का अपना लाभ मार्जिन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ ।

242. लगाई गई पूंजी पर आय में वर्ष 2007-08 तक गिरावट आई और उसके बाद वृद्धि हुई । तथापि, इसमें वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 में \*\*\*% की गिरावट आई ।

243. आयात तथा घरेलू बिक्री कीमत के बीच बढ़ते हुए कीमत अंतर के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता घट रही है ।

244. अत्यधिक वैश्विक बेशी क्षमता : घरेलू उद्योग ने मांग से अधिक क्षमता के बारे में निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध है, जिसकी वजह से भारत में कम कीमत पर संवर्धित आयात हो रहे हैं जिससे घरेलू विनिर्माताओं को गंभीर क्षति हो रही है/गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो गया है ।

सभी आंकड़े मी.ट. में

तालिका-16

क्र.सं.	देश	उत्पादक	क्षमता मी.ट. में	घरेलू मांग	बेशी
1	कोरिया	कोरिया कुम्हो (केकेपीसी)	70,000	8,000	62,000
2	चीन	सिनोर्गचेम	120,000	-	-
		नानजिंग केमिकल्स	30,000	-	-
		टोंगलिंग जैडा	10,000	-	-
		नॉर्थ ईस्ट ऑक्स	10,000	-	-
		सांग्यू लिक्सिंग	2,000	-	-
		जियांगशूडांगलांग	8,000	-	-
		चाइना सनसाइन	15,000	-	-
	कुल चीन		195,000	90,000	105,000
3	ई यू क्षेत्र	फ्लैक्सिस	65,000	-	-
		लैंगसिस	38,000	-	-
		डूसलो	18,000	-	-
	कुल ई यू		123,000	32,000	91,000
4	जापान	सुमितोमो	10,000	17,000	-7,000
5	भारत		11,500	14,500	-3,000
6	शेष विश्व		शून्य	87,000	-
7	कुल विश्व		407,500	248,500	159,000
8	भारतीय मांग				14,500
9	भारतीय मांग के % के यप में वैश्विक बेशी क्षमता				1097%

245. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच से यह पता चलता है कि कोरियाई और चीन के आपूर्तिकर्ताओं के पास मांग से काफी अधिक बेशी क्षमता है। इसके अलावा, कोरियाई आपूर्तिकर्ता ने इस तथ्य के बावजूद कि वह अपनी क्षमता से कम पर विचार-विमर्श कर रहा है और कोरिया में कुल मांग मौजूदा क्षमता से काफी कम है, अपनी क्षमता \*\*\* मी.ट. से बढ़ाकर 2009-10 में \*\*\* मी.ट. कर दी है। विदेशी आपूर्तिकर्ता के पास बेशी अनपयुक्त क्षमता का होना अतिरिक्त बाजार में प्रचलित कीमत से कम कीमत पर अपने उत्पाद के लिए अतिरिक्त बाजार का पता लगाने अथवा उसका सृजन करने का कारण है। इससे भारत में घरेलू उद्योग के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

246. सी. शु. टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 (ख) के खंड 6(घ) में "गंभीर क्षति के खतरे" को परिभाषित किया गया है, जिसका तात्पर्य गंभीर क्षति के स्पष्ट और आसन्नवर्ती खतरे से है। उपर्युक्त विभिन्न मापदंडों की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2009-10 से प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा है और इसमें 2010-11 में और विकृति आई है। आवेदक उद्योग वर्ष 2009-10 की तुलना में 2010-11 में उत्पादन, क्षमता उपयोग, संवर्धित मालसूची, बिक्री प्राप्ति, लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय के कारण घटा हुआ है। घरेलू मांग में वृद्धि की तुलना में बिक्री में वृद्धि काफी कम रही है। इसके अलावा, निर्यातकों के पास जांचाधीन उत्पाद की भारी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। अतः यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग भी गंभीर क्षति के खतरे का सामना कर रहा है।

### अन्य कारक

247. निर्यात : कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग उत्पादन के 50% से अधिक का निर्यात करता है और वर्ष 2010-11 में निर्यात मात्रा में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण हो सकती है। निम्नलिखित तालिका में पाटनरोधी शुल्क के साथ आयात की पहुंच कीमत, निर्यात कीमत तथा घरेलू बिक्री कीमत दर्शायी गई है।

तालिका-17

वित्तीय वर्ष	आयात की पहुंच कीमत पाटनरोधी शुल्क सहित (रु./किग्रा.)	निर्यात कीमत (सूचीबद्ध)	घरेलू बिक्री कीमत (सूचीबद्ध)
2005-06	229.73	100	100
2006-07	192.66	90	90
2007-08	147.02	79	82
2008-09	247.29	110	113
2009-10	192.59	93	103
2010-11 (विश्ल.)	189.84	89	103

248. उपर्युक्त तालिका के आंकड़ों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत हमेशा घरेलू बिक्री कीमत से कम रही है। घरेलू उद्योग को उस कीमत से कम पर बेहतर घरेलू मांग के बावजूद वस्तु का निर्यात करना होता है जो निर्यात कीमत से भी कम है। इस बात को देखते हुए घरेलू उद्योग के लिए निर्यात कोई लाभप्रद विकल्प नहीं है। घरेलू उद्योग को घाटा कम करने के लिए निर्यात करना पड़ता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि निर्यात घरेलू उद्योग की प्राथमिकता है। इसके अलावा, यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है कि घरेलू उद्योग ने भारत में प्रयोक्ता उद्योग द्वारा निर्यात हेतु घरेलू आपूर्ति से मना किया है।

249. तथापि, क्षति विश्लेषण में निर्यात कार्यकलापों के प्रभाव को अलग रखा गया है। घरेलू बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, घरेलू बिक्री कीमत, लाभ आदि जैसे कारकों का निर्यात निष्पादन से कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि निर्यात के बिना उत्पादन में 2010-11 में गिरावट आई है और उत्पादन में 2009-10 तक हुई वृद्धि मांग में हुई वृद्धि से काफी कम रही है। अतः क्षति विश्लेषण करते समय निर्यात कार्यकलापों के प्रभाव को अलग रखने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है और इसलिए यह माना जाता है कि निर्यात निष्पादन घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति कारण नहीं है।

250. पी एक्स-13 की मांग और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उत्पादकों की क्षमता: कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति का कारण संवर्धित आयात नहीं था क्योंकि घरेलू आपूर्ति और घरेलू मांग के बीच अंतर को पाटने के लिए आयात आवश्यक थे। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत जांचाधीन उत्पाद के शुल्कमुक्त आयात को छोड़ने के बाद उनके पास घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है। उन्होंने तर्क दिया है कि मांग में वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा संवर्धित आयातों ने ले लिया है और उन्हें घाटा कम करने के लिए घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर जांचाधीन उत्पाद का निर्यात करना पड़ा है। घरेलू उद्योग ने अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

क्षमता, मात्रा मी.ट. में

तालिका-18

मद	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
नोसिल क्षमता	***	***	***	***	***	***	***	***	***
नोसिल नई क्षमताएं	***	***	***	***	***	***	***	***	***
मालसूची/अथ स्टॉक	***	***	***	***	***	***	***	***	***
मरकैम क्षमता	***	***	***	***	***	***	***	***	***
पी एम सी क्षमता	***	***	***	***	***	***	***	***	***
लेंगसिस क्षमता	***	***	***	***	***	***	***	***	***
शुल्क मुक्त आयात	1734	1916	1867	1761	3069	2373	2741	3289	3947
कुल उपलब्धता	11568	11689	14236	14158	15867	15848	19228	28419	38831

मांग	7424	8753	11095	10053	14572	15691	18123	22110	26974
बेशी/कमी	4144	2936	3141	4105	1295	157	1105	6309	11857

स्रोत:- आवेदकों का अनुरोध ।

251. घरेलू उद्योग ने उपर्युक्त तालिका में आंकड़े दाहेज स्थित अपनी विस्तार योजना के आधार पर प्रस्तुत किए हैं जिन्हें समायोजन योजना; लागत लेखाकार प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित उस तारीख की स्थिति के अनुसार अधिकतम मालसूची; बाजारी स्रोत के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादक की क्षमता और अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत जांचाधीन उत्पाद के शुल्कमुक्त आयात की गणना करने के लिए टायर निर्यात आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया गया है । आवेदक ने वाणिज्य विभाग के निर्यात-आयात डाटा बैंक से प्राप्त टायर निर्यात के सौदेवार आंकड़ों सहित समर्थकारी दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं ताकि ए एल एस के अंतर्गत पी एक्स 13 के आयात की गणना की जा सके । इसके अलावा आवेदक ने अनुरोध किया है कि माने गए निर्यात के लिए वे कोई बिक्री नहीं करते हैं जैसा कि उत्पादन की ईआर-1 से स्पष्ट हो जाता है ।

252. मांग-आपूर्ति के समर्थन में आवेदक का उपयुक्त अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए रक्षोपाय नियम, 1997 के नियम 6(7) के अनुसार सार्वजनिक फाइल में रखे गए थे । प्रयोक्ता/आयातकों ने यह तर्क दिया कि यदि मांग-आपूर्ति में अंतर के निर्धारण हेतु ए एल एस के अंतर्गत आयात अलग रखे जाते हैं तो उन्हें संवर्धित आयातों के निर्धारण से ही अलग रखा जाना चाहिए । प्रयोक्ता उद्योग ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत जांचाधीन उत्पाद के शुल्क मुक्त आयात की मात्रा की संत्यता पर प्रश्न नहीं उठाया है । प्रयोक्ता उद्योग ने लेंसस की वास्तविक क्षमता का पता लगाने और यह जानने का अनुरोध किया है कि क्या वे जांचाधीन उत्पाद का विनिर्माण कर रहे हैं और मध्यवर्ती अर्थात् 4 ए डी पी ए के आयात आंकड़ों के बारे में निष्कर्ष न निकालने का अनुरोध किया है । इस बात की पुष्टि के. उ. शु. से की गई है ।

253. उपर्युक्त अनुरोध से यह देखा जाता है कि घरेलू मांग में से ए एल एस के अंतर्गत हुए आयातों को अलग रखे जाने की स्थिति में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है । इसके अलावा, प्रयोक्ता उद्योग के दावे के अनुसार यदि ए एल एस के अंतर्गत आयात के बारे में प्रदत्त आंकड़े कुल आयातों में से घटा दिए जाएं तो वर्ष वार आयात 2005-06 = 2343 मी.ट.; 2006-07=3736मी.ट.; 2007-08=4993 मी.ट., 2008-09=3845मी.ट.; 2009-10=7021मी.ट. तथा 2010-11= 8736 मी.ट । इससे यह पता चलता है कि ए एल एस के अंतर्गत शुल्क मुक्त आयात घटाने के बाद भी आयात में वृद्धि हुई है ।

254. यद्यपि, घरेलू उद्योग ने यह दावा किया था कि अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत टायरों का निर्यात किया जाता है, तथापि, उनके द्वारा प्रस्तुत टायर के सौदेवार निर्यात आंकड़ों में उस निर्यात संवर्धन स्कीम का उल्लेख नहीं है, जिसके अंतर्गत निर्यात किए गए हैं । इसके अलावा, ए एल एस धारक के पास कच्ची सामग्री का शुल्कमुक्त आयात करने अथवा अग्रिम रिलीज ऑर्ड के अंतर्गत घरेलू बाजार से उसकी खरीद करने का विकल्प होता है । समग्र मांग के निर्धारण हेतु ए एल एस के अंतर्गत आयात के प्रस्तुत आंकड़ों को अलग रखना सही नहीं हो सकता । तथापि, रक्षोपाय शुल्क लागू होने के बाद ए एल एस के अंतर्गत शुल्कमुक्त आयात की घरेलू बिक्री से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी ।



255. भारतीय उत्पादकों के पास क्षमता वर्ष 2005-06, 06-07, 07-08 और 2008-09 में 7424 मी.ट., 8753 मी.ट., 11590 मी.ट. और 9864 मी.ट. की घरेलू मांग की तुलना में क्रमशः \*\*\* मी.ट., \*\*\* मी.ट., \*\*\* मी.ट. तथा \*\*\* मी.ट. रही थी । आवेदक घरेलू उद्योग ने \*\*\* % से अधिक क्षमता हासिल की है और अन्य भारतीय उद्योग ने \*\*\*% और उससे अधिक का क्षमता उपयोग किया है । उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता वर्ष 2005-06 से 2008-09 के बीच घरेलू मांग से अधिक रही थी लेकिन इस अवधि में आयात में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर वस्तु का निर्यात करना पड़ा ।

256. वित्त वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 (दिसं. तक, वार्षिक) में भारतीय उद्योगों के पास क्षमता \*\*\* मी.ट. तथा \*\*\* मी.ट. थी । उपर्युक्त वर्षों में घरेलू मांग 15011 मी.ट. और 16117 मी.ट. रही थी । भारतीय उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता उपर्युक्त दोनों वर्षों में घरेलू मांग से कम रही थी । तथापि, घरेलू मांग में वर्ष 2009-10 में अचानक 45% की वृद्धि हुई जबकि मांग में औसत वार्षिक वृद्धि 22% प्रति वर्ष की है । घरेलू उद्योग तथा अन्य उत्पादकों ने \*\*\*% से अधिक का क्षमता उपयोग किया और वे क्षमता के लगभग बराबर उत्पादन करने में समर्थ हैं । तथापि, घरेलू उद्योग कम लाभकारी कीमत पर हुए आयात के कारण क्षमता प्राप्त करने में विफल रहा जिसने घरेलू मांग का एक बड़ा हिस्सा ले लिया । इसी अवधि में संवर्धित आयातों के कारण आवेदक की औसत मालसूची बढ़कर \*\*\* मी.ट. और \*\*\* मी.ट. हो गई । इसके अलावा, वर्ष 2009-10 में घरेलू मांग में आयात का हिस्सा 55.77% से बढ़कर पूर्ववर्ती वर्ष 2008-09 की तुलना में 69.02% हो गया । घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में बिक्री करने में समर्थ नहीं रहा और घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर जांचाधीन उत्पाद का निर्यात करने के लिए बाध्य हुआ ।

257. ऐसी स्थिति में जब देश में आरोपित मांग-आपूर्ति के बीच अंतर है, घरेलू उद्योग अत्यधिक निर्यात और वह भी घरेलू बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर नहीं करेगा । घरेलू उद्योग संवर्धित आयात के कारण घरेलू बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ है । इस आशय का कोई साक्ष्य/आरोप रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है कि उपभोक्ता घरेलू उद्योग से सामग्री मांगते हैं और उसकी आपूर्ति नहीं करते हैं ।

258. घरेलू उद्योग के पास उच्च मांग के बावजूद पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता बनी रही और क्षमता उपयोग घटकर वर्ष 2010-11 में \*\*\*% हो गया । घरेलू उद्योग वर्ष 2008-09 में \*\*\* मी.ट. से 2009-10 में \*\*\* मी.ट. और 2010-11 में \*\*\* मी.ट. की संवर्धित औसत मालसूची का सामना करना पड़ रहा है । मांग-आपूर्ति में अंतर होने पर घरेलू उद्योग ऐसी स्थिति का सामना नहीं करेगा । इस तथ्य से कि घरेलू उद्योग को घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर निर्यात करना पड़ा, यह पता चलता है कि आयात में वृद्धि मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण नहीं हुई है ।

259. भारतीय उद्योग के पास वर्तमान घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और कार्यान्वयन के अग्रिम चरण पर चल रही विस्तार योजना भावी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है । आयात में वृद्धि घरेलू मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण नहीं हुई है ।

260. पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू होने की स्थिति में रक्षोपाय शुल्क लगाना : इस मुद्दे की जांच की गई है कि क्या रक्षोपाय शुल्क उस समय लगाया जा सकता है जब पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लागू है । सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क पाटन मार्जिन से अनधिक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबंधित है । धारा 8 ख कुछेक परिस्थितियों में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से संबंधित है । जिन परिस्थितियों में दोनों शुल्क लगाए जा सकते हैं, वे अलग-अलग हैं । इसके अलावा धारा 8 ख की उपधारा (3) में सी.शु टैरिफ अधिनियम, 1975 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत साथ-साथ कई शुल्क लगाने का प्रावधान है । उपधारा 3 निम्नानुसार है ।

"इस धारा के अंतर्गत प्रभार्य शुल्क इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत लगाए गए किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा"

261. तदनुसार, पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू होने के कारण रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने पर कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं है ।

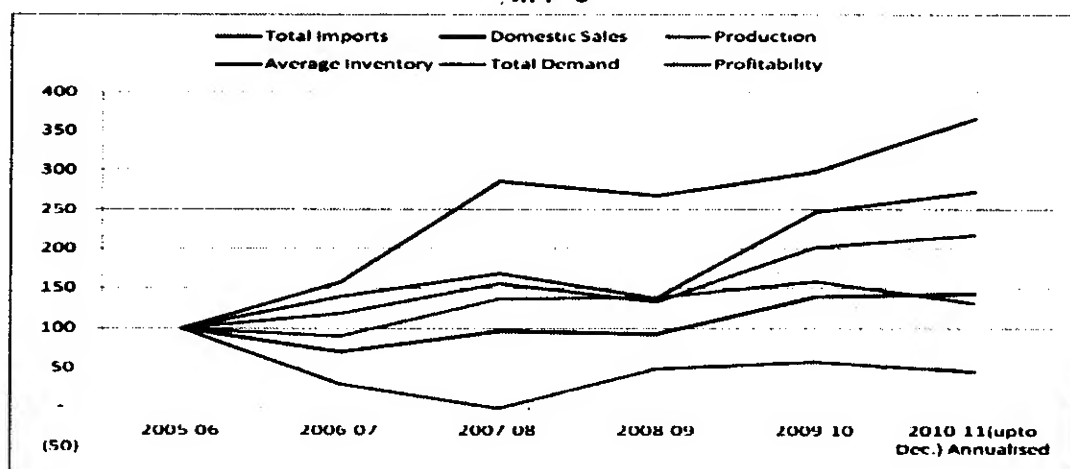
262. तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न अनुरोध किए हैं जिन्होंने पाटनरोधी तथा रक्षोपाय, दोनों शुल्कों को एक साथ लगाए जाने के खिलाफ अनुरोध किया है । उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क साथ-साथ लगाना लोकहित में नहीं है । इस मुद्दे का विश्लेषण किया गया है । पाटनरोधी शुल्क टैरिफ बाधाएं लगाकर पाटित आयातों के दुष्प्रभाव का मुकाबला करने और उसे निष्प्रभावी बनाने के लिए व्यापार उपचारात्मक उपाय है । रक्षोपाय शुल्क टैरिफ बाधा लगाकर संवर्धित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों से घरेलू उद्योग की रक्षा करने का एक उपाय है । दोनों शुल्कों का अन्य कार्यों के अलावा एक सामान्य कार्य है अर्थात् आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को निष्प्रभावी करना । अतः यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुल्क तभी लगाया जाए और उसे जारी रखा जाए जब मौजूदा व्यापार उपचारात्मक उपाय चाहे वे किसी रूप में हो घरेलू उद्योग की रक्षा करने में समर्थ न रहे हों । यह भी माना जाता है कि बहु-रक्षा आवश्यक समझी गई सीमा तक ही उपलब्ध हो ।

263. वर्तमान मामले में यह सच है कि आयातों में वित्त वर्ष 2008-09 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है । कम कीमत पर आयातों में हुई वृद्धि से गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो गया है ।

264. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि उस समय जब अमरीका, ई यू तथा चीन के बड़े बाजारों में मांग में कमी आई, भारत में जांचाधीन उत्पाद की उच्च मांग होने के साथ-साथ कोरियाई और चीन के निर्यातक के बीच विशेष संबंध संवर्धित आयातों के लिए जिम्मेवार था । पाटनरोधी शुल्क सहित मौजूदा टैरिफ बाधा बड़ी मात्रा में हो रहे आयातों की रोकथाम के लिए पर्याप्त नहीं था । अतः आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए बहु-व्यापार उपचारात्मक उपाय न्यायोचित है । तथापि, बहु-व्यापार उपचारात्मक उपायों के उपयोग में औचित्य के लिए यह अपेक्षित है कि यह समुचित अवधि और मात्रा तक सीमित रहे ताकि अंतिम प्रयोक्ताओं पर रक्षोपाय शुल्क का भार न्यायोचित ठहराया जा सके ।

## कारणात्मक संबंध

ग्राफ-8



265. घरेलू उद्योग के निष्पादन से यह पता चलता है कि जांचाधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई और आयात के हिस्से में वृद्धि हुई है।

266. आयात की पहुंच कीमत तथा घरेलू बिक्री कीमत के बीच अंतर काफी अधिक है और इसमें वर्ष 2005-06 से वृद्धि हो रही है।

तालिका-19

वित्तीय वर्ष	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11 (दिसंबर तक) वार्षिकीकृत
आयात और घरेलू बिक्री के बीच कीमत अंतर (सूचीबद्ध)	-100	648	2020	456	2114	2228
आयात मात्रा मी. ट. में	4077	5652	6860	5606	10090	11109

267. यह नोट किया जाता है कि आयात की मात्रा और कीमत अंतर में वर्ष 2008-09 (जब पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था) में गिरावट आई तत्पश्चात कीमत अंतर में वृद्धि हुई और आयात में पुनः बढ़ोत्तरी हो गई। आयात में यह वृद्धि आयात कीमत तथा घरेलू बिक्री कीमत के बीच कीमत अंतर के अनुरूप रही है।

268. अत्यधिक कीमत में अंतर पाटनरोधी शुल्क के बावजूद कीमत कटौती के रूप में उभरा। बाद में जब घरेलू उद्योग की बिक्री बढ़ी तब यह माँग में हुई वृद्धि से कम रही थी। इससे घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई। अतः घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आयातों में वृद्धि के कारण आई है।

269. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में बाजार वृद्धि से कम की बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उत्पादन में गिरावट 2010-11 में शुरू हुई जिसे पुनः उत्पादन घंटों में कमी और मालसूची में वृद्धि से देखा जा सकता है। उत्पादन के संबंध में प्रतिकूल निष्पादन संवर्धित आयातों के कारण रहा है।

270. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई और आयात में वृद्धि हुई। परिणामतः घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि के बावजूद मालसूची में वृद्धि संवर्धित आयातों के कारण हुई है।

271. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में परिवर्तन के अनुसार कीमत विनियमित नहीं कर सकता। पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पूर्ववर्ती स्तर पर नहीं आ रही है जो संवर्धित आयातों के कारण हुआ है।

272. आयातों में वृद्धि के साथ-साथ क्षमता उपयोग, उत्पादन, लाभप्रदता में गिरावट आई। कम कीमत पर संवर्धित आयातों के कारण भारत में कीमत ह्रास हुआ जिससे लाभप्रदता और लाभ में कमी आई। केवल संवर्धित आयात से बाजार हिस्से का नुकसान हुआ। आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई। भारतीय बाजार में माँग में वृद्धि संवर्धित आयातों के कारण नहीं हुई है।

273. आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हुआ है।

274. समायोजन योजना : यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए व्यवहार्य समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है। याचिकाकर्ता ने आवेदन और परवर्ती लिखित अनुरोधों के साथ समायोजन योजना प्रस्तुत की थी (जाँच परिणाम का पैरा 33-38)।

275. यह देखा जाता है कि पैनल ने कोरिया-बेरी मामले में इस मत को स्वीकार कर दिया है कि अनुच्छेद 5.1 के अंतर्गत समायोजन योजना पर विचार करना लाजिमी है (संदर्भ देना है)।

- हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम अनुच्छेद 5.1 की व्याख्या प्राधिकारियों द्वारा किसी समायोजन योजना पर विचार करने की अपेक्षा के रूप में नहीं कर रहे हैं.....

पैनल इस आशय की कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं पाता है कि ऐसी किसी समायोजन योजना का अनुरोध किया जाए और रक्षोपाय करार के पाठ में उन पर विचार किया जाए। यद्यपि उसके दो उपबंधों में औद्योगिक समायोजन का हवाला दिया गया है तथापि, रक्षोपाय करार के पाठ में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि कोई उपाय लागू किए जाने से पूर्व विशिष्ट समायोजन योजना पर विचार किया जाए। इसके बजाय हमारा यह मानना है कि गंभीर क्षति को रोकने या उसे दूर करने के प्रश्न के साथ-साथ समायोजन का प्रश्न प्राधिकारियों द्वारा लागू करने के लिए चुने गए उपाय के सुस्पष्ट स्पष्टीकरण का एक भाग होना चाहिए। इसके अलावा, हम नोट करते हैं कि रक्षोपाय लागू करने के संदर्भ में इसी समायोजन योजना की जाँच इस बात का मजबूत साक्ष्य होगा कि प्राधिकारियों ने इस बात की जाँच की है कि क्या उक्त उपाय गंभीर क्षति को रोकने या उसे दूर करने तथा समायोजन को सुकर बनाने के उद्देश्य के अनुरूप थी।

276. रक्षोपाय नियम, 1997 के नियम 5(2) के अंतर्गत “आयात प्रतिस्पर्धा के लिए सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जाने वाले अथवा किए जाने के लिए नियोजित अथवा दोनों प्रकार के प्रयासों” के बारे में एक विवरण देना अपेक्षित है। डब्ल्यूटीओ रक्षोपाय करार में यह उपबंध है कि कोई सदस्य उस सीमा तक ही रक्षोपाय लागू करेगा जिस सीमा तक वह गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसे दूर करने और समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक है।

277. निश्चयात्मक रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को वह सीमित अवधि प्रदान करना है जिसके भीतर वह अपना पुनर्गठन कर सकें ताकि आयातों के साथ अधिक कारगर प्रतिस्पर्धा की जा सके। इस संबंध में रक्षोपाय नियम, 1997 के नियम 16(2) और सीटीए, 75 की धारा 8(ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें उस स्थिति में उपाय के किसी संभावित विस्तार का निषेध है यदि इस आशय का साक्ष्य हो कि घरेलू उत्पादक समायोजन कर रहे हैं।

278. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठन योजना बढ़ती हुई माँग की पूर्ति करने और लागत को घटाने हेतु क्षमता विस्तार पर केन्द्रित है।

279. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि वे आयातों के साथ उचित प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। अन्य भारतीय उत्पादकों की क्षमता के साथ-साथ घरेलू उद्योग की विस्तारित क्षमता आयातों के साथ उत्पाद की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। आवेदक घरेलू उद्योग \*\*\* करोड़ रु. की लागत से \*\*\* मी.

टन की क्षमता का विस्तार कर रहा है। 30.04.2011 की स्थिति के अनुसार \*\*\* करोड़ रु. की राशि वचनबद्ध की गई है। उक्त राशि में से \*\*\* करोड़ रु. की राशि खर्च की जा चुकी है। विस्तार कार्य मार्च, 2012 में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और उत्पादन अप्रैल, 2012 से शुरू होने की आशा है।

280. आवेदक ने यह दावा किया है कि विस्तार के परिणामस्वरूप \*\*\* रु./कि.ग्रा. की न्यूनतम लागत बचत होगी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ऊपरी लागत के लिए लागत में कटौती के प्रति आशान्वित है यदि वह बाजार में अधिक बिक्री करता है।

281. पुनर्गठन योजना के ब्यौरे माँगे गए थे। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के दावे का विधिवत समर्थन विस्तार एवं नई योजना हेतु व्यय के बारे में सनदी इंजीनियर प्रमाण पत्र और किए गए व्यय तथा उत्पादन लागत के दावे के बारे में प्रेक्टिसरत लागत लेखाकार प्रमाण पत्र द्वारा की गई है। यह नोट किया जाता है कि कंपनी की समायोजन योजना उचित और व्यवहार्य है।

282. समायोजन योजना पर शुल्क के उत्तरोत्तर उदारीकरण हेतु विचार किया गया है।

### सार्वजनिक हित

283. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जाँचाधीन उत्पाद पर रक्षोपाय सार्वजनिक हित में नहीं है तथापि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इसे पुष्ट करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

284. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि टायर उद्योग में पीएक्स-13 का हिस्सा 0.71% से 1.11% के बीच है और गैर-टायर खण्ड 0.5% है। इस तथ्य का खण्डन वर्तमान जाँच में टायर गिनतीवालों का प्रतिनिधित्व करने वाले एटीएमए तथा ऑल इंडिया रबड़ मैनु. एसो. नाम का जाँच करनी है) द्वारा नहीं किया गया है।

285. संपर्युक्त हिस्से और पीएक्स-13 की नगण्य लागत पर विचार करते हुए यह नोट किया जाता है कि टायर की कीमत तथा गैर-टायर खण्ड पर रक्षोपाय शुल्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अथवा अति अल्प प्रभाव पड़ेगा।

286. आवेदक और एक अन्य घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं का विस्तार शुरू किया है और उस जाँच परिणाम के पैरा 278 में की गई चर्चा के अनुसार पर्याप्त प्रगति की जा चुकी है। अकेला आवेदक \*\*\* व्यक्तियों से अधिक को रोजगार देगा। इसके अलावा, निवेश का

एक बड़ा हिस्सा वित्तीय संस्था से प्राप्त हुआ है। यदि भारतीय विनिर्माताओं को संवर्धित आयातों से पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है तो रोजगार और सार्वजनिक हित जोखिम में पड़ जाएंगे।

287. इसके अलावा, आवेदक घरेलू उद्योग के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय उत्पादक जाँचाधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु अंतिम मध्यवर्ती 4एडीपीए के विदेशी उत्पादकों पर आश्रित हैं। आवेदक उद्योग बंद हो जाने की स्थिति में अन्य भारतीय उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी कीमत पर 4एडीपीए समय पर मिलने की कोई गारंटी नहीं है। अतः आवेदक घरेलू उत्पादकों का बचा रहना उपभोक्ताओं के हित में है। इसके अलावा, इस समय आवेदक के पास कार्यरत \*\*\* से अधिक व्यक्तियों का रोजगार भी जोखिम में पड़ता है।

288. रक्षोपाय शुल्क, जिससे घरेलू उद्योग संवर्धित आयातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ होगा, जांचाधीन उत्पाद के क्रेताओं के अंततः सार्वजनिक हित में और उससे विनिर्मित उत्पादों के क्रेताओं के भी हित में होगा। अतः यह माना जाता है कि जांचाधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क लगाना सार्वजनिक हित में है।

### विकासशील देश

289. विकासशील देशों से हुए आयातों के प्रतिशत की भी जाँच की गई है। चीन को छोड़कर जिसका हिस्सा वित्त वर्ष 2009-10 और 2010-11 में भारत में हुए कुल आयातों का क्रमशः 18.14% तथा 15.09% रहा है, अन्य विकासशील देशों का अलग-अलग हिस्सा भारत में हुए कुल आयातों के 3% से कम है। अतः चीन को छोड़कर विकासशील देशों के मूल के विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) के परंतुक के अनुसार रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

290. उपर्युक्त जाँच परिणाम के मद्देनजर अंतिम निर्धारण यह है कि भारत में एन 1,3-डाइमिथाइलब्यूटाइल-एन फिनाइलिनडाइएमीन (पीएक्स-13 अथवा 6पीपीडी) के संवर्धित आयातों के कारण एन 1,3-डाइमिथाइलब्यूटाइल-एन फिनाइलिनडाइएमीन (पीएक्स-13 अथवा 6पीपीडी) के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति होने का खतरा भी उत्पन्न हुआ है। रक्षोपाय शुल्क की वह राशि निकालने के लिए जो घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त होगी तथा सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए लगाई गई पूंजी पर उचित आय पर भारित औसत बिक्री लागत तथा आयातों की औसत पहुँच लागत (मूल सीमाशुल्क, उपकरण को हिसाब में लेते हुए) पर विचार किया गया है। रक्षोपाय शुल्क की राशि निकालते समय जांचाधीन

उत्पाद पर लागू पाटनरोधी शुल्क पर भी विचार किया गया है। इसके अलावा, परिकलित रक्षोपाय शुल्क में अधोगामी समायोजन भी किया गया है ताकि अंतिम प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं के हित में घरेलू बाजार में आयातों की प्रतिस्पर्धा बनाए रखी जा सके। सार्वजनिक हित पर भी विस्तार से विचार किया गया है।

291. घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए रक्षोपाय शुल्क को उत्तरोत्तर उदार बनाने की जरूरत पर विचार करते हुए यह सिफारिश की जाती है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 3812, 3810, 2921, 2925, 2934 तथा 2942 (6-अंकीय स्तर पर) के अंतर्गत आने वाले एन 1,3-डाइमिथाइलब्यूटाइल-एन फिनाइलिनडाइएमीन (पीएक्स-13 जिसे 6पीपीडी, 6सी, फिलफेक्स 13, सिरान्टॉक्स 4020, एन्टीऑक्सीडेंट 4020, कुमहोनैक्स 13, वल्कोनैक्स 4020) के आयातों पर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने और गंभीर क्षति के खतरे से बचाने के लिए न्यूनतम अपेक्षित रक्षोपाय शुल्क मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट दरों पर 2 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाए।

क्र. सं.	अवधि	रक्षोपाय शुल्क
1	प्रथम वर्ष	30% घटा संदेय पाटनरोधी शुल्क
2	द्वितीय वर्ष	25% घटा संदेय पाटनरोधी शुल्क

292. चूँकि चीन को छोड़कर विकासशील देशों से हुए अलग-अलग आयात 3% से अधिक नहीं हैं इसलिए चीन को छोड़कर विकासशील देशों के मूल के विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(ख) के परंतुक के अनुसार रक्षोपाय शुल्क लागू नहीं किया जा सकता।



**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th June, 2011

**Sub. :Safeguard investigation concerning imports of N 1, 3-dimethyl butyl-N' Phenylenediamine (PX-13 also known as 6PPD, Vulconox 4020 etc.) into India—Final Findings.**

**G.S.R. 433(E).**—Having regard to the Custom Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 thereof.

**PROCEDURE**

1. An application was filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997[hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by M/s NOCIL Ltd., C-37, TTC Industrial Area, Thane-Belapur Road, Navi Mumbai-400705 for imposition of Safeguard Duty on imports of N 1,3-dimethyl butyl-N'Phenylenediamine (PX-13 also known as 6PPD, Vulconox 4020 etc.) into India alleging that increased imports of N 1,3-dimethyl butyl-N'Phenylenediamine (PX-13 also known as 6PPD, Vulconox 4020 etc.) was causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of N 1,3-dimethyl butyl-N'Phenylenediamine (PX-13 also known as 6PPD, vulconox 4020 etc.) in India. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met with, safeguard investigation against imports of N 1,3-dimethyl butyl-N'Phenylenediamine (PX-13 also known as 6PPD, Vulconox etc.) was initiated vide notice of initiation dated 27<sup>th</sup> December, 2011 and published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day.
2. A copy of the notice was sent to the governments of major exporting countries through their embassies in New Delhi. A copy of initiation notice was also sent to all known interested parties listed below:

**3. Domestic Producers**

SN	NAME OF UNIT	FACTORY ADDRESS
1	NOCIL Limited	C-37, T.T.C. Industrial Area, Off Thane Belapur Road, Navi Mumbai – 400705 Ph.: 022-2767/2735/2789

		Fax: 022=2767/1865 Email: gadgilrm@nocilindia.com
2.	PMC Rubber Chemicals India Private Limited	103 G.T. Road West PO Rishra 712248, Dist : Hooghly West Bengal, India
3.	Lanxess India Private Limited	Kolshet Road, Thane – 400 607, Maharashtra India
4.	Merchem Ltd.	Grove Centre, 44 Development Plot, Kalamassery, Cochin-683109, Kerala, India.

#### 4. Importers

- a. J.K. Industries Ltd., 7, Council House Street, Kolkata – 700 001
- b. CEAT Limited, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 030.
- c. Apollo Tyres Ltd., 6<sup>th</sup> Floor, Cherupushpam Building, Shanmugham Road, Kochi – 682031, Kerala.
- d. Birla Tyre, C/o Kesoram Industries Ltd., 8<sup>th</sup> Floor, 9/1, R.N. Mukherjee Road, Kolkata – 700 001.
- e. MRF Limited, 126, Greams Road, Chennai – 600 006
- f. Metro Tyres Limited, B-27, Focal Point, Ludhiana – 141 010.
- g. Poddar Tyres Ltd., Poddar Nagar, GT Road, Jugiana, Ludhiana – 141010.
- h. Raison Industries Ltd., 14, 3 Palmohan Aptt., Punjabi Bagh West, New Delhi – 110 026.
- i. Rubber Products Ltd., Wagie Estate, Near Precitex, Thane – 400 601.

- j. Puneet Resins Ltd., 84 Atlanta, Nariman Point, Mumbai – 21.
- k. Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., 65 Atlanta, Nariman Point, Mumbai – 21.
- l. Automotive Tyre Manufacturers Association, PHD House (4<sup>th</sup> Floor), Opp. Asian Games Village, Siri Fort Institutional Area, N. Delhi – 110 016.
- m. All India Rubber industries association, 1009, Padma Tower-1, 5, Rajendra Place, New Delhi-110008.

### **Exporters**

- l. Solutia Inc., St. Louis, Missouri, USA (World Headquarters) 575 Maryville Centre Drive, St. Louis, Missouri 63141, USA
- m. Lanxess NV, 51369, Leverkusen, Germany
- n. Dusio, a.s., Administrativna budova ev. C. 1236, 927, Q3 Safa, Slovak Republic
- o. Jingasu Sinorgchem Technology Co., Ltd., Shanghai Operation Centre, Jingasu Sinorgchem Technology Co. Ltd., 22F, Yongda International Tower, No. 2277, Longyang Road, Pudong New Area, Shanghai, PR China
- p. Korea Kumho Petrochemicals Co. Ltd., 21-24F Kumho Asiana Main Tower #115, Sinmunno 1-Ga, Jongno-Cu, Seoul 110-857, Korea
- q. Flexsys SA/NV (Part of Solutia Inc.) Parc Scientifique-Fleming, Rue Laid Burniat 3, Louvain – La – Neuve, 1348, BELGIUM
- r. Nanjing Chemical Industry Corporation, No. 560, Heyen Road, Nanjing, Jingasu Province, China – 210038.
- s. Shangyu Lixing Chemical Co. Ltd., Shangyu Fine Chemical Zone 5 RD, Zhejiang, China P.C. : 312369.
- t. Northeast Auxillary Chemical Industry Co. Ltd., Wuqiang Industry Park, Hebei, China.
- u. United Rubber Chemical Corp. Office Address : Suite 1505 Building A, Nanxincang International Tower, 22, Dongsishitiao, Dongcheng District, Beijing, China 100007
- v. The Organic Chemical Industry Limited of Tongling Chemical Industry Group, Address : No. 1269 JinlingDao, Tongling City Anhui Province, China, Postal Code : 244003.

### **5. Exporting Nations:**

- i. European Union

- ii. Germany
  - iii. Czech Republic
  - iv. Belgium
  - v. PR China
  - vi. Republic of Korea
  - vii. Arab Republic of Egypt
  - viii. USA
6. Questionnaires were sent to all known domestic producers, importers and exporters and were asked to submit their response within 30 days.
7. Request to consider them as interested parties were received from the following parties/exporting nations and all the requests were accepted:
- i. M/s Puneet Resins Ltd., Mumbai
  - ii. M/s Rishiroop Polymers Pvt. Ltd., Mumbai
  - iii. M/s Solutia Inc., USA
  - iv. Sh. Abdelrahman Fawzy, Ministry of Trade and Industry of Egypt
8. Requests for extension of time to submit their replies were made by the following parties:
- i. M/s Jiangsu Sinorgchem Technology Co., Ltd., China PR
  - ii. M/s Kumho Petrochemicals, Korea
  - iii. Automotive Tyre Manufacturers Association, New Delhi.
9. After taking into account the time limits for completing the investigation within the prescribed period, requests for extension of time to submit reply as per Rule 6(4) of Safeguard Rules were allowed, as prayed for, and the parties concerned were accordingly informed.
10. The information presented by the applicant i.e. M/s NOCIL was verified by on-site visits to the plants of the domestic producers and through the Central Excise records to the extent considered necessary. The applicants have submitted cost data verified and duly certified by practicing cost accountant. The non confidential version of verification report is kept in the public file.
11. All the written submissions of applicant and interested parties were taken on record. The non confidential information received or acquired has been kept in the public file.
12. A public hearing was held on 21.02.2011, notice for which was sent on 28<sup>th</sup> January 2010. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997. Copy of written submission filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinder, if any, to the written submissions of other interested parties.
13. Some of the interested parties requested data from the applicant in the format "Questionnaire for Domestic Producers". The same was provided to the concerned

interested parties and also kept in the Public File. The interested parties were given the desired extra time to file their response to the above submission of applicant.

14. All further submissions filed by Domestic Industry were made available to the other interested parties and kept in the Public file. The interested parties were given sufficient time to file response of the same. The additional data of import procured during the course of investigation was kept in Public file. The submissions of applicant on increased import and other economic parameter like market size, share of import in total domestic demand etc. after adding the additional import data were made available to other interested parties and kept in public file giving sufficient time to file reply.
15. All the views expressed by the interested parties and other domestic producers either in the written submissions or in the rejoinders and response to the domestic industry submissions were examined and have been taken into account in making appropriate determination. As there are large number of interested parties who have filed their submissions, their contentions and the issues arising there-from are dealt with at appropriate places without referring to specific name of the interested party for the sake of brevity.

### **Views of Domestic Industries and other Interested Parties**

#### **Applicants**

16. The product for which application has been filed for SG duty is a Rubber Chemical PX-13 or 6PPD which is extensively used in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, and Carboxylated Rubber and other synthetic rubber based compounds used for manufacture of various rubber products.
17. There are three more producers of the goods but the applicant M/s NOCIL account for more than 50% of production and hence is a major producers.
18. The product is being imported in the Indian market for a long period and has the history of dumping from various sources. The details of dumping cases are given in the Table below:-

Description	Case 1	Case 2
Countries Involved	Taiwan and EU	China and Korea
Initiation	August, 2004	July, 2007
Period of Investigation	Jan., 03 – Dec., 03	April 2006-March 2007.
Interim Duty	8th April 2005	28th.Feb. 2008
Customs	7 <sup>th</sup> July, 2005	5 <sup>th</sup> May, 2008

Definitive Duty	16th August 2005	1st October, 2008
Customs	7 <sup>th</sup> July, 2005	12 <sup>th</sup> Dec, 2008
Duty Imposed	<u>EU</u> - US\$ 816-840 pmt	<u>Korea</u> – Rs. 10.35 per/kg
Review	May 2010 (SSR)	August, 2010 (MTR)
Period of Investigation	April 09 to March 10	April, 09 to March, 10

19. The import and injury related data from 2000-01 to 2010-11(Dec.2010) has been filed by the applicant with argument that the product has dumping history since 2003. There are number of cases wherein the Investigating Authorities of other member countries have taken long period for injury analysis and submitted a statement showing various cases and number of years considered in these investigations. Further there is no specific obligation in the AoS regarding period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authority which is also in conformity with US-Line Pipe case.
20. The applicant claimed that Imports "increased" in the recent past, but not necessarily be increasing up to the end of the period of investigation at the same rate. The petitioner submits that the data of the recent past cannot be seen in isolation as has been argued by the opposition. Also in the present case, the increase in imports has to be determined in the light of the existing anti-dumping duties. There has been a sudden, sharp and significant increase in imports of the subject goods during the injury period in spite of anti-dumping duties in force.
21. There has been a decline in imports in the year 2008-09 due to anti-dumping duty imposed on imports from China and Korea. This decline was temporary in nature and the imports once again started increasing at a higher pace in the subsequent years.
22. There are two important unforeseeable events that led to the increase in imports. They are (a) Special Relationship between KKPC and Sinorgchem and (b) Recession in the global market leading to significant drop in demand for the product in developed countries and China.
23. Korea Petrochemicals (KKPC) is the sole producer of 6PPD in Korea. The production of 6PPD requires 4-ADPA as the penultimate stage intermediate for 6-PPD. KKPC does not have its own facilities for production of 4-ADPA. Sinorgchem is one of the producers of Rubber Chemicals in China, engaged in production of only 6PPD and 4-ADPA. The company has been involved in a major legal dispute over patent issues in the U.S. for violation and use of production technology patented by a leading Global producer (Flexsys). On being prevented from selling in the very large U.S. market, Sinorgchem has drawn alternate market strategies. It is towards this end that Sinorgchem has gone in for some arrangement with KKPC wherein Sinorgchem will produce and

supply 4-ADPA to KKPC, KKPC will produce 6PPD and will supply the same in the existing and new market of Sinorgchem and KKPC globally. The Special Relationship has been stated even in the Annual Report of KKPC for the year 2008-09. Sinorgchem has been selling 4-ADPA at subsidized price to KKPC. The price at which Sinorgchem has sold 4-ADPA in Indian market is higher than the price at which the company has sold to KKPC. Korea market for 6PPD was close to 7000-8000 M.tons. About 50% of the demand in Korean market was being met through imports. Thus, KKPC has a domestic demand of about 4000 MT. Despite existing capacities far beyond this, the company went for further and significant expansion only because of the relationship between the two parties and with a view to get other global producers out of market.

24. The special relationship is the cause of significant price difference despite of current anti-dumping duties on Korean goods.
25. The recent global recession led to the significant drop in demand of the product in major markets (which includes China, Europe and USA). The global market for tyres continues to be sluggish after the global recession, whereas the Indian market is quite strong. The information published by the tyre industry and its association is clearly indicative of the increase in demand/consumption. Resultantly, the Indian market is increasingly becoming lucrative to the foreign producers. Further, petitioner submits that there is decline in exports of tyres in Europe and EU markets and consequent decline in PX-13 consumption in third countries exporting to Europe which lead to accumulation of inventories with the producers. Therefore the only option left with them was to increase their export into markets less affected by the recession. India being one such market was targeted and the imports increased in huge quantities.
26. The current enhancement in the applicable duty in force on imports from Korea and the revised anti-dumping duty that may be determined in the mid-term review by Designated Authority following the current review would still fall far below the injury margin in the current period of investigation. Therefore, the domestic industry has filed the present safeguard petition seeking imposition of safeguard duty only to the extent of unaddressed injury. In fact, the domestic industry was cautious of the situation that it was not entitled to dual remedy for the same injury and in order to address the aforementioned situation, the domestic industry on its own has clarified to the Director General (Safeguards) that the domestic industry is looking for safeguard duty only to the extent of unaddressed injury as a result of imposition of anti dumping duty.
27. The petitioner submits that, the penultimate intermediate required for this product PX – 13 is 4 ADPA. The 4 ADPA required by Korean Manufacturer is sourced from China which is a Non Market Economy as classified by the Anti Dumping Authorities. Further the Chinese Government offers various direct and indirect incentives to its domestic industry like Export Tax Rebates, a Weak Currency (RMB), etc. It may be noted for the same product PX 13, the ADD levied on the Chinese source is determined at Rs. 42.70/Kg whereas for Korea, it is determined at Rs. 10.35/Kg. The major difference on this front is treatment of Korea as a Market Economy despite the major input 4ADPA is being

sourced out of China and that the value addition from 4 ADPA to PX 13 is not very significant.

28. In the recent case of Caustic Soda in India, the Director General has recommended for levy of Safeguard duty in addition to the Anti-dumping duty already in force. The Government of India accepted the recommendation and imposed Safeguard duty along with the Anti-dumping duty. Hence it is wrong to say that both duty can not be levied.

29. The petitioner submits that domestic industry is legally justified in filing the present application. WTO laws also permits the same. No violation of either domestic or international law has been pointed out by the interested parties. The petitioner refers and relies on the reply of European Union to the issues raised by China on dual remedy (G/SG/Q2/EEC/4) which is as follows:

*—The EU received requests for a safeguard investigation, as well as an anti-dumping and an anti-subsidy proceeding. In all three cases, the requisite conditions for the initiation of the cases were met. Indeed, as far as the safeguard investigation is concerned, an analysis of the evidence submitted by Belgium in its request for safeguard measures indicated that there was a sudden, recent and sharp increase in imports and that this increase caused serious injury.*

30. The petitioner claimed confidentiality as per Rule 7 of Safeguard Rules 1997 on factual information relating to product under consideration alone, such as capacity, production, sales volumes (domestic & exports), inventories, costs, prices, profit/loss, market share, etc. Petitioner has not claimed confidentiality on any information that is contained in the annual report, or information that the petitioner has placed in public domain. Petitioner submits that disclosure of actual information with regard to petitioner domestic industry can also jeopardize the future business in the product. The implications of disclosure of information that may have to be disclosed as a result of argument by the interested parties are—Firstly, there is only one petitioner in this case, which would mean all parties would know actual information about that company. Secondly, there are three other companies in India, competing with each other and domestic industry fiercely in the Indian market, and trying their level best to know business secrets of other company in order to draw their future business strategy. The moment such information is disclosed, all these companies can derive the information about the other company in matter of minutes – something which they might be trying to know for a very long period and for which they might have even spent huge money and yet might be unaware. Thirdly, the moment the information is disclosed, each & every consumer would come to know how their procurement price was in the past, i.e., were they paying high or low or just & fair price vis-à-vis their competitors buying from the same source (which directly impact the competition). Fourthly, the consumers would instantly know how their prices are vis-à-vis cost structures of their supplier, which would directly impact the future price negotiation between these parties. Fifthly, the foreign producers would come to such huge business information about the majority Indian Producer that they can draw clear plans for eliminating the Indian Producer (which is the entire intent). The information can be gold mine



information for a prospective Indian Producer trying to set up a plant in India, having no definitive information about the actual current performance of current producers. Sixthly, the consumers are competing in the downstream product and pricing to other buyers is the biggest business information for them. If so, the consumer would immediately get tremendous business information about its competitor who is otherwise a producer of one of the inputs.

31. The petitioner contended that past cases in DG Safeguards were without such confidentiality because the number of applicants were more and the information given in the petition was already in Public domain i.e. in Annual Report of the applicant companies. The present case justify confidentiality as in rubber chemicals industry no player in the said business ever discloses product wise installed capacities – production, sales volume, etc. Even if one looks at the balance sheets (Annual Reports) of Indian competitors, viz. Lanxess India Pvt. Ltd., PMC Rubber Chemicals India Pvt. Ltd., one does not get any breakup of individual product wise capacities, sales volumes, production, etc. Even in a company like China Sunshin or Lanxess or Solutia Inc., one does not get product wise production capacity, sales volume, etc. In case of Lanxess, Solutia Inc., rubber chemicals get clubbed with other business. Even KKPC, rubber chemicals get clubbed with other business
32. Petitioner has so far participated in three completed investigations and three ongoing investigations. Petitioner has not disclosed any of these information in their dumping petitions. Such claim of the petitioner has been accepted/admitted by the Designated Authority. Under the circumstances, disclosure of this information now in safeguard petition would seriously jeopardize the petitioner's claim before the Designated Authority on Anti-dumping.
33. As regards Adjustment Plan at the outset, petitioner submits that the Panel in the Korea — Dairy Safeguard case rejected the view that Article 5.1 imposes an obligation to consider adjustment plans.
34. The Indian Producers have laid down adjustment plan which focuses on a) Cost reduction b) Further utilization of existing production capacity c) Capacity expansion to cater the growing demand.
35. The petitioner industry i.e. NOCIL is setting up another manufacturing facility at Dahej wherein the company intends- to produce \*\*\*MT of PX-13 at an estimated expenditure of Rs.\*\*\*Cr. The total commitment as on 30<sup>th</sup>-April 2011 stands at Rs. \*\*\* Crores and the amount already spent upto 30.04.2011 is Rs. \*\*\* Crores. The project is slated to be commissioned from March 2012 and production from April 2012. A certificate from Chartered Engineer has been submitted giving detail of the work done and to be done and certifying that it is quite possible to commence production from April 2012. Also a certificate from practicing cost accountant giving detail of the expenditure already done and committed has been submitted.

36. The expanded capacity would be sufficient to take care of present and potential demand of PX-13 in the Country after taking into account the production capacities with other Indian producers and likely growth in demand and imports of PX-13 against exports.
37. The expansion would result in minimum cost saving of Rs.\*\*\*Kg to the company. The applicant submitted a certificate from practicing cost accountant in support of the same. Further the petitioner is hopeful of cost reduction on account of overhead cost once it is able to sell more material in the market.
38. Further, this expansion would enable the company to face fair competition from imports. The petitioner requested safeguard duty for a period of three years so that it is in a position to face the import competition.
39. The Adjustment Plan is not required to be fully operational when Safeguard duty is imposed. The domestic industry is required to give adjustment plan in such a way that if safeguard duty is imposed, the same would enable domestic industry to facilitate positive adjustment.
40. It is relevant to point out that one of the Indian producers, M/s. Laxness is a multinational company having production facilities in India and outside India. The petitioner submitted that M/s. Laxness had temporarily suspended its production and in order to meet out its customers requirements it has resorted to supplies of the material from its production facilities outside India. If the production had not been suspended, the company would have produced the same quantities of subject goods domestically. Owing to the absence of permanence in the said arrangement, the imports were excluded as the inclusion would have otherwise distorted the data.
41. The said manufacturer M/s Lanxess have started production as is evident from import of 4 ADPA by them. Import data of 4ADPA at JNPT, Nhava Sheva is submitted in support of the said claim.
42. The petitioner informed that the average import of preceding years for ICD Ludhiana and Cochin port has been added in the import figure of 2009-10 and 2010-11 as the same was not available. Appropriateness of the same has not been disputed by the interested parties at the time of oral hearing. Petitioner submits that these imports are required to be added in order to arrive at imports of the product under consideration in India during relevant period.
43. It was argued at the time of oral hearing that the petitioner has shown increased imports by excluding imports made by Lanxess (and there is no justification in excluding these imports). It was further argued that once these imports are excluded, imports show a decline. Interested parties even presented graphs showing decline in imports. Petitioner submits that all these submissions are misplaced as there is increase in import whether the data of Lanxess is included or excluded from the total import.
44. The imports in relation to production has increased throughout the period from 2000-01 to 2010-11. Imports has also increased with reference to consumption.

Surge in imports is leading to injury to the domestic industry. Market Share of domestic industry steeply declined whereas that of imports steadily and steeply increased. Capacity utilisation of domestic industry declined. This decline in capacity utilisation is despite increase in demand for the product under consideration in the Country.

45. Domestic industry is being forced to export its production, despite significant domestic demand. Such exports are not a matter of choice, but a compulsion for the domestic industry, driven out of continuous increased imports of the product in the Country. It has been argued by the opposing parties that it is a false case that the domestic industry is constrained to export. The petitioner submits that in the presence of sound demand in the domestic market, the petitioner is exporting the product at prices lower than what it can fetch in the domestic market in the normal circumstances. The only reason for these increased imports can be lower prices. The petitioner is unable to get demand for its products in the domestic market, and therefore is compelled to export the product under consideration. The petitioner submitted data on Korean Landed price of Import and their domestic sale and Export price in support of their claim.
46. Profitability and return on investments are still lower than the levels registered in the past. This is despite of improvement by atleast \*\*\*% on the cost position over the last 4-5 yrs.
47. Production of the domestic industry, which was increasing till 2009-10, declined thereafter. The domestic industry enhanced its capacities in view of rising demand. Even when demand for the product in the Country is significantly high, the domestic industry was not able to fully utilize its capacity. Further, even though the domestic sales increased over the injury period, the same were far below the production level and domestic demand. In fact, the domestic industry was constrained to export a very substantial part of its sales in view of its inability to sell more volumes in the domestic market. It is pointed out in this regard that exports of the domestic industry are more of a compulsion than a choice or preference.
48. The fact that the petitioner has not been able to utilize its production capacities for the product under consideration can be seen from the data they have submitted on Production Hour lost since 2007-08 to 2010-11 (upto Dec.).
49. The landed price of imports is lower than the (a) selling price of the domestic industry and (b) cost of production of the domestic industry. The imports are significantly undercutting the domestic selling prices. The price undercutting is resulting in price suppression or depression.
50. Petitioner submits that the impact of increased imports shall be on commercialization of additional capacities being set up in India [by NOCIL and Merchem]. Firstly, given the surge in imports, the producers may not even find market for the additional capacities that are coming up. Secondly, even if the producers find some market, the prices are likely to be quite adverse. NOCIL alone is investing about Rs. \*\*\* crores. Significant investment is being made by Merchem. NOCIL alone will have an employment strength of more than \*\*\*

persons. Significant part of these investments have come from financial institutions. Thus, all these investments and employment are at stake due to surge in imports.

51. The petitioner submitted that there is no gap in demand and supply. They claimed that the import under duty free Advance Licence Scheme for use in export should be excluded from calculation for domestic demand. After considering the capacity available with the other Indian producer (present and future expansion), inventory available with the DI there is no demand and supply gap. On the contrary, the DI has excess capacity than domestic demand.
52. The domestic industry is losing sales opportunities. Consequently, production, capacity utilization, profits, return on investment and cash flow is not improving even after imposition of anti dumping duties due to continued presence of low price increased imports. Given the low prices offered by the foreign producers and significant freely disposable production capacities with foreign producers, the imports are surging further despite low prices offered by the domestic industry. Increased imports have led to increase in market share of imports and reduction in market share of the domestic industry. Decline in market share of the domestic industry has adversely impacted the production and capacity utilization of the domestic industry. It is thus evident that injury to the domestic industry has been caused by the increased imports.
53. Petitioner claimed that in addition to the serious injury already inflicted on the domestic industry, increased imports of PX-13 are threatening serious injury to the domestic industry. The threat of serious injury is established by the following factors:-
  - (a) The price difference between domestic and imported product is too high even after considering the prevailing anti dumping duties. Thus, the imports continue to remain lucrative;
  - (b) The foreign producers are holding significant unutilized capacities. Resultantly, the foreign producers are looking for additional markets to the extent possible;
  - (c) The special arrangements between the Chinese and Korea producer is providing significant mileage to the Korean producer. The Korean producer is therefore likely to intensify its activities in the Indian market;
  - (d) The global market for tyres continues to be sluggish after the global recession, whereas the Indian market is quite strong. The information published by the tyre industry and its association is clearly indicative of the increase in demand/consumption. Resultantly, the Indian market is increasingly becoming lucrative to the foreign producers.

54. Imposition of Safeguard duty is in Public interest. The PUI does not constitute a major cost element for the consumers. Majority consumption of 6-PPD is by tyre industry. Costs on account of 6-PPD constitutes below 1% of the price of tyre industry. In any case, there is no basis for a presumption that NOCIL will increase its prices as a result and to the extent of safeguard duty. NOCIL is only looking for additional market from the consumers. In the instant case, imposition of safeguard duty would be in public interests for the following reasons.
55. 6-PPD constitutes a major product for the producers of this product. Presence of domestic industry has kept the prices to reasonable levels. The intention of the Korean and in turn Chinese producer is to eliminate production of the product in India and then charge high prices. Should the domestic industry survive, benefit of the same will come to the consumers.
56. Fresh investment of about Rs. \*\*\* crores is being made by NOCIL alone. Significant investment is being made by Merchem as well. Majority of these investments are from financial institutions. The surge in imports is clearly likely to have serious impact on these public funds. NOCIL alone has employment of more than \*\*\* persons. This employment is clearly at stake if the domestic producers do not survive.

#### **Submission of Merchem Ltd (Domestic Producers)**

57. The company is in Rubber Chemical manufacturing and have capacity of \*\*\* MT. They are going to enhance the capacity to \*\*\*MT and the production of expanded capacity is expected from July 2011. The expansion would create employment of \*\*\* person.
58. The company strongly supports the imposition of safeguard duty on the PUI.
59. The import of PUI has shown an increasing trend. The increased import at price much below the production cost is causing serious injury and is threatening to cause serious injury.
60. The cost of production of 6-PPD (Ref: standard input output norm Sl. No. A1412) is approx. Rs. \*\*\*/kg. but the imports are taking place at price US\$3.30/kg(Rs. 148/kg).
61. The increased imports at low price has caused price depression and prevented price increase of the PUI in domestic market.
62. The increased import has made impossible to retain customers due to unviable price. The major producers of 6 PPD in developed countries are dumping their surplus quantities into India.
63. The imports have affected our profitability and operations very severely. This will further adversely impact our cash flow, growth opportunity etc. If the safeguard measure is not taken our plants will go in loss and would eventually be forced to close down.

**VIEWS OF EXPORTING NATIONS****Views of European Commission**

64. On the basis of information provided in the application, prima facie there appears to be no serious injury or even threat thereof as required by Article 4.1(b) of the WTC\*Safeguard Agreement (WTO SA).
65. The most recent data on imports given in the application is incomplete as per the claim of applicant that several ICDs could not make them available due to migrations of their databases. The same is required to be verified.
66. The petitioner is unable to identify unforeseen developments. As per Article XIX of the GATT, Safeguard measures should only be taken in exceptional circumstances.
67. No “critical circumstance” exists as required by Article 6 of the WTO justifying the imposition of provisional measures.
68. The imports from several countries were already under Anti Dumping duties in 2005 and 2008 and that these measures are currently under review (sunset and mid-term review) and any double remedy should be excluded.
69. The increase in imports is not recent, sharp, and significant enough and there is no unforeseen developments. As per application, the imports in the most recent period increased by only 2% (from 8834 in 2009 to 9043 in 2010) which is not a sharp and significant increase in imports.
70. No serious injury or threat thereof. Capacity and production increased considerably between 2007-08 and 2009-10. During the same period, production and sales increased significantly.
71. No causal link between increased imports and the impairment in the position of industry. Negative effects produced by other factors having a bearing on the situation of the petitioner should not be attributed to imports.

**Views of Arab Republic of Egypt**

72. As there is no Egyptian exports of the subject goods (PX-13), therefore, as per Article 9.1 of the Agreement on Safeguards, any safeguards measures that may be imposed on imports of PX-13, should exclude Egypt.

**Views of the Republic of Korea**

73. Double jeopardy resulting from the simultaneous imposition of anti-dumping and safeguards duties. The Korean companies that are exporting PX-13 have already been imposed anti dumping duties by Government of India since October, 2008. Furthermore, in July, 2010, the Indian anti-dumping authorities launched a mid-term review at the request of its domestic industry.

74. As per Article 4 of the WTO Safeguard Agreement, in determining whether serious injury or threat is present, investigating authorities are to evaluate all relevant factors having a bearing on the condition of the industry, and are not to attribute to import injury caused by other factors.
75. No injury to domestic industry. As per the data in the petition filed by applicant, taking year 2006-07 as the base year, the production has increased from 100 to 161.15; capacity utilization from 100 to 112.20; domestic sales have doubled and profits have more than trebled i.e. profits have increased from 100 to 325.
76. No unforeseen developments and import increase was not 'recent, sudden, sharp and significant.

### Views of the Exporters

#### Views of Jiangsu Sinorgchem Technology Co. Ltd, China PR

77. Application for the initiation of safeguard investigation is without factual and legal basis. The investigating authority has not carried out due scrutiny of the application before the same was initiated.
78. The Indian Anti Dumping Authority had already initiated and imposed Anti-dumping Investigation on the subject product before the current safeguard investigation and Anti Dumping Duty is in place on almost all sources.
79. The Domestic Industry in India has always, by one way or the other, been protected by the Government of India in the past. The Domestic Industry in India is in a habit of seeking protection by way of trade barriers from the Government of India even though the same are not justified.
80. Deliberately details of imports from USA have been deleted from the information submitted to DG (Safeguards) to show increase in imports during the proposed period of investigation of Safeguards investigation (April 2010 to Sept 2010 Annualized). The trends in case of actual imports reported by Applicant Domestic Industry to DGAD is

Year	Imports Claimed with DGS (Mt)	Percentage Increase	Imports Claimed with DGAD (Mt)	Percentage Increase
2009-10	8834	100%	9828	100%

PERIOD OF INVESTIGATION ( Annualised)	9043	102%	9043	92%
--	------	------	------	-----

81. Trends of increase in imports during the period of investigation from 2009-10 have shown decline and not increase as claimed by the Applicant Domestic Industry.
82. Article 2.1 of AoS and Art. XIX ,1(a) of GATT 1994 requires that the increase in import must be recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough both in quantitative and qualitative term to cause serious injury. In India the data to determine the increased import provided is of most recent three years eg. Acetylene Black case. The 10 year period of investigation is abnormally long and against the practice of Safeguard.
83. Domestic Industry may be asked to file complete and comprehensive details as per Domestic Industry Questionnaire and then other interested parties may be given opportunity by way of filing response to the Questionnaire. The DI has not provided information required in the said questionnaire for adjustment plan like Project report by Chartered Engineering firm and project cost by practicing cost accountant.
84. Nothing has been submitted on Unforeseen development that lead to increased imports. Hence the investigation should not have been initiated.
85. The relationship between KKPC and Sinorgchem is normal business relationship and is not special. Sinorgchem has never sold 4ADPA to KKPC at low price but at a profitable market price.
86. The adjustment of VAT refund rates for products from time to time is normal practice for many countries. The Government of China applies the VAT refund rates at 17% on many products and is not limited to 6PPD and this can not be termed as Unforeseen development.
87. The Director's report of DI for the year 2009-10 clearly says that there is no effect of recession in 2009-10. The Indian industry and global tyre industry is operating at their normal level. Hence claim of Unforeseen development is not correct.
88. As required under the Annexure to Trade Notice No.SG/TN/1/97 dated 6/09/97, no detailed adjustment plan has been offered by the Domestic Industry to the Directorate General (Safeguards) as part of their application. It is not clear from the Initiation Notification that what measures have been proposed by the Domestic Industry to adjust itself to the competition being faced due to alleged surge in imports. In absence of viable Adjustment plan the investigation is not proper as per the law.



89. The Domestic Industry has failed to prove objectively the alleged imports, absolute or relative, the alleged serious injury or threat of serious injury to the Domestic Industry and a causal link between increase in imports and the alleged serious injury or threat thereof.
90. Main reason for decline in production, market share of the Domestic Industry and share of domestic producers in domestic consumption and fall in capacity utilization of the Domestic Industry is mainly due to shut down of plant by one of the domestic producers.
91. In line with the rulings of the Appellate Body in US-Lamb case we are of the opinion that the mandatory requirement has not been fulfilled and the Initiation Notification is grossly vitiated due to none compliance of Article 4.2(b).
92. The applicant failed to demonstrate the existence of causality between surge in import and serious injury and threat of serious injury.

**Views of Kumho Petrochemical Co. Ltd., Korea**

93. The petitioner has not made out any development that was unforeseen which resulted in the increased imports of goods into India and hence the conditions prescribed under Article XIX: 1(a) is not fulfilled.
94. Secondly, the petition has not brought out that the increase in imports was due to the effect of obligations undertaken by India under GATT, including tariff concessions. Merely because India is a member of WTO and has undertaken some obligations under GATT, one cannot presume that the increase in imports in the subject goods was due to the effect of those generic obligations undertaken under WTO.
95. Application should be referred to DGAD as the domestic industry has claimed before the DGAD that dumping was causing material injury to them. At the same time, the domestic industry has claimed before the DG (SGD) that increased imports was causing serious injury to them. In such situations, what shall be done according to the law is the question to be answered in this case.
96. In this case, it may be seen that close to 97% of the imports are coming only from dumped sources or countries that have been found to be dumping the goods into India by DGAD. Rightfully, antidumping duties are already in places against almost all countries that export the subject goods to India. Since the antidumping duty has already been put in place and the existing duties are under review, there is no warrant for the DG(SGD) to initiate one more set of investigation to see whether safeguard duty is required to be levied. Only to prevent such situations, the rules provide that the DG(SGD) shall forward the application to the DG(AD) as the goods are dumped.
97. Import data has been manipulated. Though the petitioner has included the imports made by the Lanxess(the other domestic producer in their petition before

the DGAD), however, they have excluded such import without any legal basis to place on record manipulated figures to get undue advantages.

98. Initiation of the proceedings by the Authority is in gross violation of the provisions of Rule 5. It is mandatory for the Domestic Industry to submit a statement on the efforts being taken to meet the import competition. Understanding the extraordinary nature of safeguard measure and the obligation of the Domestic Industry to establish the efforts taken by it to adjust to global competition, the DG has prescribed the Questionnaire Format for Domestic Industry requiring them in section IV to provide 'Information on Adjustment Plan'. However, the Petitioner has not filed the questionnaire till date.

99. There is no increased imports as is evident from the data below:-

S. No	Year	Import of subject goods (MT)	Increase in imports (MT)	Increase in imports (%)
1	2009-10	8,834		
2	2010-11- April to September	4,533	209	2.37
	2010-11- annualised	9043		

100. It is clearly evident that the increase in import of the subject goods during the

first half of 2010-11 is a mere 289 Tones or 2.37% on an annualized basis. Thus,

there was no significant increase in imports.

101. While all the other injury parameters like fall in production, capacity utilisation etc. have been considered for M/s NOCIL Ltd alone, the fall in market share has been considered for all the producers put together.

102. Safeguard measure is an emergency device designed to relieve a domestic industry of an acute injury caused by radical increase in imports. Gradual or even sporadic increase in imports over a long period of time is unlikely to put a domestic industry in a situation that justifies an emergency remedy like safeguard duty.

103. Increase from 5655 MT in 2004-05 to 9066 MT in 2010-11 representing an increase of 60%, even if considered significant, has happened over a period of 7 years and hence is not recent enough. Increase in imports from 8834 MT in 2009-10 to 9066 MT in 2010-11 represents a mere 2.62% increase and hence is not significant enough. The increase is definitely not sharp enough or sudden enough or significant enough.

104. A close examination of the following injury data reveals that there is no injury to the Domestic Industry.

S. No.	Particulars	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	(Annualised) Change in 2010-11 compared to 2007-09
1	Installed capacity	258	258	274	274	6%
2	Production	235	238	273	253	8%
3	Domestic sales volume	122	117	174	177	45%
4	Export Sales volume	441	474	418	282	-36%
5	Cost of sale	107	137	122	124	25%
6	Selling Price	96	132	121	120	25%
7	Profit/Loss per Kg	-5	89	106	88	1860%
8	Profit as a % of selling price	-1	56	63	52	5300%
9	Cash Profit	24	110	1871	162	575%
10	ROCE	-1	83	95	76	7700%
11	Wages	74	71	97	107	45%

105. Capacity has increased from 100 in 2000-01 to 274 in 2010-11. Even if we consider the performance during the last four years, capacity has increased from 258 in 2007-08 to 274 during 2010-11 – an increase of 6%. Production has increased by 2.53 times during the past decade. More specifically, production increased from 235 in 2007-08 to 253 in 2010-11 – an increase of 8%. Capacity utilisation has been maintained at around 91%-92% despite significant capacity additions. Domestic sales have increased from 122 in 2007-08 to 177 in 2010-11 – an increase of 45%.

106. Only export volume recorded a fall of 36% in 2010-11 as compared to 2007-08, which could be the only cause for injury suffered by the Domestic Industry.

107. Cost of sales increased from 107 in 2007-08 to 124 in 2010-11 as compared to the increase in selling price from 96 to 120 during the same period. Thus, while cost of sale increased by 17 basis points, selling price increased by 24 basis points.

108. From a loss of (5) in 2007-08, the domestic industry has achieved a profit of 88 during 2010-11 recording an increase of 93 basis points. ROCE has increased

from (-1) to 76 during the said period.

109. The above data presented by the petitioner in the application does not show any evidence of 'serious injury' suffered by them due to increased imports. On the contrary, the domestic industry has grown from strength to strength in the last 4 years.

110. The goods subject to safeguard investigation are used in manufacture of tyres, which is one of the primary requirements of automobile industry. The automobile industry is facing serious competition from import of tyres. If a safeguard duty is imposed on the import of 6 PPD, the prices of the tyres in the domestic market would increase. This would lead to a situation in which imported tyres would be more competitive as compared to the domestically produced tyres. It will be detrimental to the interest of tyre manufacturers as well as automobile manufacturers and ultimately costly to the common man.

111. In the absence of feasible adjustment plan provided by Domestic Industry, the authority cannot impose safeguard duty. In the final finding of White/ yellow phosphorous case the Director General did not recommend Safeguard duty even after ascertaining material injury caused by increased imports because the DI in the Adjustment plan did not establish that it would be in position to compete with international competition. The said order was held by Hon'ble High Court and Supreme Court of India.

112. Though this may be permissible interpretation of Art. 5.1 of AoS that there is no obligation on part of investigating authority to consider adjustment plan but

Rule 5 of Safeguard Rules 1997 specifically provide for Adjustment plan. The domestic law regarding Adjustment Plan should prevail over international law.

113. The domestic industry is not interested in their expansion at Dahej in Gujrat as stated in the Adjustment plan. They have invested only 10% of the project money even after three years as is evident from their Chairman's statement in the shareholder meeting available in public domain.
114. The claim of DI for Safeguard duty as difference between injury margin and Anti dumping duty has no legal basis. Art. 11.1 of ADA provides levy of anti dumping duty to the extent necessary to counteract dumping. Art. 5.1 of AoS authorize levy of Safeguard measure to prevent injury and facilitate adjustment. Hence under AoS it is not necessary to impose Safeguard duty equal to the injury margin.
115. KPC has entered into a contract with Sinorgchem China for uninterrupted supply of 4-ADPA, a raw material of 6-PPD. This contract cannot be termed as special relationship. Both KKPC and Sinorgchem compete with each other in global market. The increase import has nothing to do with the above long time contract of the two companies.
116. The Chinese supplier is exporting 4ADPA to KKPC at lower price than to India. The KKPC is getting preferential pricing because of bulk order and longtime contract. It has nothing to do with unforeseen development.
117. The capacity of KKPC in excess to domestic demand has nothing to do with unforeseen development.
118. The price variation between different countries will always exist. Also only Korean price is compared with domestic selling price whereas there are significant import from other countries. The petitioner is more dominant in determining the sale price than KPC in Indian market.
119. The global recession caused decreased in import of 6 PPD in India in 2008-09. Further the global recession between 2007-09 has not impacted the petitioner as its sale and other injury parameter shows increase.
120. The DI has submitted revised injury data after addition of omitted import data of Cochin and Ludhiana port. However, non inclusion of certain import can not alter or vary the injury suffered by the DI like cash profit investment etc. The revised injury data should not be entertained by the authority as the same suffers from serious inherent errors and misrepresentations. Further countrywise import from two ports is not available.
121. Domestic sale and sale value has increased in 2010-11 compare to 2009-10. The profit has increased in 2008-09 and 2009-10. A slight decrease in 2010-11 compare to 2009-10 does not indicate serious injury.

**Views of M/s Solutia Inc., USA**

122. The domestic industry has flouted the guidelines prescribed in Director General Safeguards Trade Notice dated 21 Dec 2009 regarding claiming confidentiality. The provisions contained in Rule 7 of Safeguard Duty Rules have also not been adhered to in this case. The Domestic Industry has claimed confidentiality even on the volume related information which does not fall in the category of confidential information.
123. There is no examination/analysis either in the application or in the initiation notification as to how the present investigation is justified when almost all the imports of the subject goods are from countries which are subject to anti-dumping investigations either sunset review or midterm reviews.
124. The very basis for seeking additional protection of safeguard duty over and above the anti-dumping duties is presumptuous and contrived. This could not have formed an accurate and adequate basis for initiation of the investigation seeking safeguard duty up to full extent of injury margin.
125. There is no mention with respect to unforeseen circumstances having led to increase in imports either in the application or in the initiation notification.
126. There is complete harmony between imports and demand pattern and therefore the pattern of imports in the present case cannot be regarded as a consequence of unforeseen circumstances.
127. There is an increase of merely 2.4% in imports during Apr10-Sep 10 vis a vis 2009-10 which cannot be regarded as recent, sudden, sharp and significant enough to warrant any safeguard initiation. Trend of imports in last five years or earlier period is totally irrelevant as has been done in this case.
128. No legal or logical justification has been given for excluding the imports by M/s Lanxess.
129. There are no details in the application or in the initiation notification with respect to imports in relation to domestic production which is a necessary condition for initiation and imposition of safeguard duty.
130. The domestic industry has taken different time periods for different parameters as per their convenience which is illogical.
131. Domestic industry has taken price as one of the indicators of injury in the application which is wrong as price and other factors are not relevant in a safeguard investigation.
132. There is no causal link between the imports of the subject goods and the alleged serious injury.
133. Domestic Industry has further extended the investigation period upto Dec.2010 which may not be allowed.

134. The unforeseen development cited by DI is highly localized and specific to specific companies and can not be used for Global Safeguard protection. Further global recession can not be Unforeseen development for the year 2010.
135. The Designated authority for Antidumping has so far not disclosed whether the Anti dumping duty will be restricted to dumping margin or injury margin. There is no evidence in support of the presumption that the Anti dumping duty may be restricted to Dumping margin.
136. The price and other factors are not relevant in Safeguard investigation and should not be brought under the phrase "under such circumstances".
137. In the event of revision of import data and consequently the injury data, the domestic Industry may be asked to file fresh submission and the same should to made available to the interested parties with 30 days time to reply.

#### **Views of Importers(ATMA)**

138. The surge in imports alleged by the DI does not fulfil the prerequisites of being sharp, recent, sudden and significant enough as is required under law. Further, the domestic industry has excluded imports made by Lanxess from total imports for inexplicable reasons. DI's argument that imports by Lanxess on account of suspension of production are not injurious holds no merit.
139. The increase in imports during 2010-11(annualized) vis a vis preceding year is a meager 2.3% only which is totally insignificant and does not warrant any safeguard measure.
140. In case imports made by Lanxess are included, which should have been the case, there is actually a decrease of 8% in the import volumes during the period stated above.
141. Competent authority seems to have relied on trends in imports over a period of time instead of recent imports which is against the mandate under Article 2.1 of the AOS and Sec 8B of CTA, 75.
142. The domestic industry is claiming three different injuries for the same product against three different sources (Antidumping MTR, Antidumping SSR and Safeguards) involving the same period of investigation. It is not clear on what basis does the domestic industry is arguing that Antidumping duty is not sufficient and is approaching the DG Safeguards for differential duty when DGAD is bound to determine a rate of duty which would remedy the injury to the domestic industry.
143. The domestic industry has failed to adduce any evidence to show that there is presence of critical circumstances and unforeseen circumstances.
144. There is no injury as per the injury parameters viz production, installed capacity and capacity utilization to the domestic industry in this case. Installed

capacity has increased by 44 % and capacity utilization has increased to 137% in 2010-11.

145. Domestic sales have risen proportionately to the increased domestic demand, which shows that the domestic industry faces no competition from dumped imports.
146. The profitability of the domestic market is evident from the fact that in first six months period of 2010-11, the value of domestic sales was 40% higher than the entire year comprising 2009-10 and profitability increased by 56% during the same period.
147. Even during the years from 2001-02 and 2005-06, when imports have been marginal, the domestic industry preferred to export the product under consideration and not supply to the domestic market. Hence, the argument that DI is constrained to export is patently false. The DI exports more than 50% of its product.
148. An investigation can maximum comprise a period of 5-6 years but examination of factors over 10 years is unprecedented.
149. The surge in import is not as has been in cases where DG Safeguard has recommended Safeguard duty.
150. The DI is not able to fulfill the demand of consumers in India and hence import is taking place even after imposition of Antidumping duty. There is demand supply gap of the product in country. In 2009-10, the demand increased by 142% and the DI even on operating at \*\*\*% capacity is not able to fulfill the same.
151. If duty free import under Advance licence is excluded for assessing demand supply gap then these import should also be excluded from the total import to assess increase import and injury analysis.
152. The present and future capacity of Merchem is a speculative figure. Further the domestic sale figure of M/s Merchem is also speculative. Hence the demand – supply figure provided by DI should not be accepted.
153. Apportionment of duty asked for by DI is not tenable as only Anti dumping duty imposed on import from Korea is on dumping margin. For other countries namely EU, China and Taiwan it is on injury margin. Hence differential duty to the extent of injury will hold merit only in case of Korean import.
154. The safeguard duty is not in public interest. Once the DI builds the additional capacity, the user industry will entirely be at the mercy of Domestic Producers which will make the Indian Tyre industry uncompetitive.
155. The DI is redirecting its exports in Indian market as the domestic Sale is more lucrative. This shows that the domestic market is robust and thriving in last 6 months.



156. The production figure for Lanxess to show the demand supply gap is based on conjuncture and should not be accepted.
157. The DI Annual report of 2009-10 says that-
- “ Although the export market has shrunk considerably due to global economic showdown, the domestic tyre market has improved considerably. The company is hopeful that given the improved domestic market, it would be in a better position to strengthen its domestic business presence.”*
158. The above statement is for the fact that there is fall in export market prompting the DI to go for domestic sales.
159. The adjustment Plan as proposed by DI will take shape in 2012 at the earliest. There is no plan of action as to how the user industry should manage in the interim within the limited resource available in the country.

**Submissions on behalf of All India Rubber Industries Association**

160. The domestic industry is already enjoying a considerable degree of protection i.e. antidumping duty on imports from EU, Chinese Taipei, China and Korea.
161. The data submitted by the domestic industry that the present petition has been filed purely with the ulterior motive of further countering international competition. It is significant to note that the domestic industry has not been able to establish either present serious injury or threat of serious injury.
162. There is no causal link between the alleged serious injury faced by the Petitioners and the supposed increase in imports.
163. The emphasis and focus of the Petitioners complaint in this case is based on pricing as the data does not support rapid increases in imports and thus the Petitioners have resorted to allegation of adverse effects on pricing to initiate a safeguards case. However it should be noted that the right forum for grievances against unfair pricing is the DGAD and not DG Safeguards.
164. The petitioners are forum shopping by approaching the DGAD for enhancement of existing antidumping duty and seeking to impose a safeguards duty on the same product.
165. The user industry is already agitating the fact that there already subsists limited domestic capacity to supply to cater to the demand of the user industry before various authorities. Moreover, the fact that the domestic industry exports majority of its production further exacerbates the situation and curtails local supply of the PUC.
166. The investigation is against public interest as the user industry is already suffering on account of high cost of natural rubber (an alternative to the PUC) due

to international prices. Thus, any increase in the cost of the PUC shall result in making production unprofitable.

### **Examination and Findings:**

167. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting nations. Submissions made by the various parties and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places in the findings below.

### **Product Under Investigation:-**

168. The product under investigation has been defined in the Notice of Initiation as Rubber Chemical N-1, 3-dimethyl butyl-N'Phenyl Paraphenylenediamine, also known as PX-13 or 6-PPD. The other trade or brand name for it are 6C, Pilflex 13, Sirantox 4020, Anti-oxidant 4020, Kumhonax 13, Vulconax 4020. The product under consideration is classified under various subheadings of customs classification heads 3812, 3810, as well as under 2921, 2925, 2934 and 2942 (at six digit levels) of the Customs Tariff Act 1975.

169. The interested parties have not raised any issue with regard to the product under investigation. Therefore, it is confirmed that the product under investigation is Rubber Chemical N-1, 3 Dimethyl butyl- N'Phenyl Paraphenylenediamine also known as PX-13 or 6-PPD.

170. PX-13 is produced by hydrogenation of a mixture of 4-nitrodiphenylamine and methyl isobutyl ketone in an autoclave at moderately high pressure in the presence of a noble metal catalyst. The resulting reaction mass, which contains unreacted ketone, by-products, etc., is filtered to remove the catalyst, which is then recycled. The filtrate is distilled to remove low boilers and is then flaked to give the finished product. The low boilers are redistilled to recover the unreacted ketone. Catalyst is recycled until the activity is reduced. It is then removed from the system.

171. PX-13 is extensively used in treating natural rubber, synthetic rubber (SBR, Butadiene Rubber, Nitrile Rubber, and Carboxylated Rubber) and other synthetic rubber based compounds used for manufacture of various rubber products. The user industry are mainly the tyre manufacturer. Even the other industry also use the product for processing the various types of natural and synthetic rubbers.

172. No differences in the production process, characteristics or end-uses between imported product with different brand like PX-13 etc. named in para 168 above and domestically produced PX-13 were identified or raised by any of the interested parties during the course of this investigation. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution.

173. Therefore, it is held that domestically produced Rubber Chemical PX-13 or 6PPD or vulconox 4020 etc falls under the ambit of like or directly competitive product in all respects to the imported Rubber Chemical PX-13 also known as 6PPD , vulconox 4020 and that the domestically produced Rubber Chemical PX-13 or 6-PPD or vulconox 4020 is a like article to the imported Rubber Chemical PX-13 or 6-PPD( or other names referred in para 168) within the meaning of Rule 2(e) of Safeguard Duty Rules 1997.

### Domestic Industry

174. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as follows:

(b) "Domestic industry" means producers -

(i) *as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or*

(ii) *whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India*

175. As per the records of the case, besides applicant M/s NOCIL Ltd. there are three other manufacturers of this product. They are M/s Lanxess Pvt India ltd. M/s PMC Rubber Pvt Ltd. Hooghly and M/s Merchem, Ernakulam. One of the producer namely M/s Lanxess is a multinational company having production facilities in India and outside India. The production capacity of the Indian producers are as follows:-

### in MT

Sl.No	Name of Company	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11(Annualised )
1	Lanxess India Pvt. Ltd	***	***	***	***
2	PMC Rubber	***	***	***	***
3	Merchem Ltd	***	***	***	***
4	NOCIL Ltd. (Applicant)	***	***	***	***
5	Total Indian Production	***	***	***	***
6	Share NOCIL	Above 65%	Above 65%	Above 75%	Above 70%

176. M/s Merchem Pvt. Ltd. Ernakulam , through written submission supported the application for levy of Safeguard duty claiming that the increased low price import is causing serious injury and threatening to cause injury to the domestic manufacturers. Besides their existing manufacturing capacity and future plan M/s Merchem did not submit data on relevant economic parameter in detail.They did

not responded to the further query of the authority and also not participated in investigation.

177. There is no concept of supporter in safeguard investigation. Hence they are not treated as Domestic Industry in subject investigation.
178. It is found that the petitioner accounts for more than 50% of the Indian production of the PUI. Therefore, it is held that the applicant domestic producer constitute and represent the domestic industry as defines in Section 8B(6)(b)(ii) of the Customs Tariff Act 1975.

### Period of Investigation

179. The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguard and the relevant Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. However the issue of period of investigation has been dealt in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea. The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Member to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown":

*"We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities.*

*In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analysed the data regarding imports on a year-to-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998.*

*We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports." (paras. 7.196, 7.199 and 7.201)<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

180. The Panel in the same US-Line pipe case ruled that:

*"In a safeguard investigation, the period of investigation for examination of the increased imports tends to be the same as that for the examination of the serious injury to the domestic industry. This contrasts with the situation in an anti-dumping or countervailing duty investigation where the period for evaluating the existence of dumping or subsidization is usually shorter than the period of investigation for a finding of material injury. We are of the view that one of the reasons behind this difference is that, as found by the Appellate Body in Argentina – Footwear Safeguard, "the determination of whether the requirement of imports "in such increased quantities" is met is not a merely mathematical or technical determination." The Appellate Body noted that when it comes to a determination of increased imports "the competent authorities are required to consider the trends in imports over the period of investigation". The evaluation of trends in imports, as with the evaluation of trends in the factors relevant for determination of serious injury to the domestic industry, can only be carried out over a period of time. Therefore, we conclude that the considerations that the Appellate Body has expressed with respect to the period relevant to an injury determination also apply to an increased imports determination." (Para 7.209)<sup>2</sup>*

181. From the above it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguard and Art. XIX of GATT provides specific guidelines on the period of investigation. The relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury and it should not only end in the very recent past but the investigation period should be the recent past.

182. The applicant in this case submitted import and injury data from 2000-01 to 2010-11(Sep. 2010) contending that longer period is required to be taken in this case because of long dumping history of the PUI. The Notice of Initiation was issued with import and injury data submitted by applicant from 2000-01 to 2010-2011(upto Sep.2010). Subsequently, the applicant submitted figure from October to December 2010. The additional information of 3 months was made available to all concerned and kept in the Public File as required under Rule 6(7) of Safeguard Rules 1997.

183. The interested parties claimed that the period is too long and relatively shorter and meaningful period should be taken for investigation. They contended that even past precedence is also not of more than 6 years and hence for meaningful analysis shorter period may be taken.

184. Considering the long History of Dumping of the PUI, Levy of Antidumping Duty since 2005 and that the period selected should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn regarding existence of increased imports and to neutralize the effect of seasonal variation longer sample size i.e. Annual Data has been considered from F.Y. 2005-06 to 2010-11(Upto December).

<sup>2</sup> WT/DS202/R DT. 29/10/2001 panel report in US –Line Pipe case

### Source of Information

185. The product under investigation is imported into India under various heading and sub heading of Customs Tariff Act 1975(refer para 168).The Safeguard investigation was initiated on the basis of import data of IBIS submitted by the applicant domestic industry. The transaction wise import data containing description of the product, was made available to the other interested parties. None of the interested parties have questioned the correctness of the transaction wise import data except for exclusion of certain quantity(1154MT) in the F.Y. 2009-2010 from a particular country and for taking average import for ICD Ludhiana, Cochin for the F.Y. 2009-10 and the 2010-11(upto dec.) submitted by DI. They requested authority to ascertain the actual import at these two ports and to arrive at the correct import figure. Accordingly, the transaction wise import data was procured from the Custom authorities of above two ports and kept in the Public File.
186. The submissions of all concerned were taken into account. The IBIS transaction wise import data submitted by the petitioner including the transaction wise data procured from ICD Ludhiana and Cochin which were not included in IBIS data with revised figure of import volume were placed in Public File with related revised data of economic parameters like total demand, share of import in total demand etc., for verification by all concerned and comments as per Rule 6(7) of Safeguard Rules. The compiled transaction wise import data was considered for assessment of increased import in the investigation.
187. The other economic parameters relating to the petitioner submitted with application and during investigation have been verified to the extent necessary and the non confidential version of verification report was placed in Public file for all concerned. Further, the data on various economic parameters like production, sales, capacity and utilization and inventory duly verified with the record of Central Excise Authority, an office of Central Government, has been considered. The analysis of data has been done primarily in relation to domestic industry only. However in order to analyse the market share of imports, the data of other industry provided by the Domestic Industry and ascertained from concerned Central Excise has been referred to. Further the import data available at the website of KITA and information available at the website of ATMA have been referred. The cost data duly certified by the practicing Chartered Accountant has been considered. If any other information is used the source is mentioned with the information.

### Confidentiality of Information submitted

188. The DI has provided information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The DI provided non confidential version of all submission including the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dt. 06.09.1997. Further the DI has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application and also post hearing written submission which has been discussed in para 30 to 32 of this findings.

189. The other interested parties like exporters and User/Importers have also requested for confidentiality of information and have submitted the confidential and non confidential version of all submissions. However they objected to the excessive confidentiality claimed by the DI and argued that meaningful argument can be put forward only with actual data on economic parameters and hence the same should not be granted.
190. The submission of domestic industry (para 30 to 32 of this finding) has been considered. Further it is seen that confidentiality has been allowed by designated authority of Anti Dumping in ADD investigation of identical product. It is also seen that all the participating industry maintains confidentiality of various economic parameter for the PUI.
191. Rule 7 of the Safeguards Rules and Art. 3.2 of WTO AoS provide for confidentiality. The petitioner is not required to disclose such information which is confidential information of the company, disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of the company, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past. Accordingly confidentiality, as prayed for by DI, is granted.

### Increased Imports

192. The legal requirement for increased import are:-

- 1) Section 8B of Customs Tariff Act, 1975: Power of Central Government to Impose Safeguard Duty

*If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article.*

- 2) Article 2 of Safeguard Agreement:

*1. A Member may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products.*

193. It has been claimed by the interested parties that the import data shows increase of only 2%-3% in 2010-11 (upto Sep.10) compare to 2009-10 and hence the recent increase in import is not sharp and significant. The Panel in US- Line Pipe case observed in a statement that the word "recent" implies a retrospective analysis; but that it does not imply an analysis of the conditions immediately



preceding the authority's decision nor does it may imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of investigation:

*"[W]e note that the Appellate Body in Argentina-Footwear Safeguard found that 'the phrase "is being imported" implies that the increase in imports must have been sudden and recent'. According to Korea, the phrase 'is being imported ... in such increased quantities' refers to 'the period immediately preceding the authority's decision'. The word 'recent' — which was used by the Appellate Body in interpreting the phrase 'is being imported' — is defined as 'not long past; that happened, appeared, began to exist, or existed lately'. In other words, the word 'recent' implies some form of retrospective analysis. It does not imply an analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision. Nor does it imply that the analysis must focus exclusively on conditions at the very end of the period of investigation. We consider that an analysis that compares the first semester of 1998 with the first semester of 1999 is not inconsistent with the requirement that the increase in imports be 'recent'." ( para. 7.204)<sup>3</sup>*

194. In the US-Steel Safeguard case the Panel in findings upheld by the Appellate Body addressed the question of how recently the imports must have increased and stated :

*"As the Panel in US — Line Pipe did, that Article 2.1 of the Agreement on Safeguards speaks of a product that 'is being imported ... in such increased quantities'. Thus, imports need not be increasing at the time of the determination; what is necessary is that imports have increased, if the products continue 'being imported' in (such) increased quantities. The Panel, therefore, agrees with the US — Line Pipe Panel's view that the fact that the increase in imports must be 'recent' does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority's determination, nor up to the very end of the period of investigation. As pointed out by the Panel in US — Line Pipe, the most recent data must be the focus, but should not be considered in isolation from the data pertaining to the less recent portion of the period of investigation. However, as indicated by the present continuous 'are being', there is an implication that imports, in the present, remain at higher (i.e. increased) levels.*

*Whether a decrease in imports at the end of the period of investigation, in the individual case, prevents a finding of increased imports in the sense of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards will, therefore, depend on whether, despite the later decrease, a previous increase nevertheless results in the product (still) 'being imported in (such) increased quantities'. In this evaluation, factors that must be taken into account are the duration and the degree of the decrease at the end of the relevant period of investigation, as well as the nature, for instance the sharpness and the extent, of the increase that intervened beforehand.*

<sup>3</sup> WT/DS202/R DT. 29.10.2001 Panel report in US- Line Pipe case



*To give an extreme example, a short and very recent slight decrease would not detract from an overall increase if imports have increased tenfold over the several years beforehand. Conversely, to give an opposite extreme example, one could no longer talk about a product that 'is being imported in (such) increased quantities', or in fact in any increased quantities at all, if, at the time of the determination, import numbers have plummeted nearly to zero or to a level below any past point in the period of investigation. (paras. 10.162 to 10.164<sup>4</sup>).*

195. In the same US-Steel Safeguards, the Appellate Body confirmed that imports need not be increasing at the time of determination and insisted on the investigating authority's obligation to examine the trend of imports over the entire period of investigation :

*"We agree with the United States that Article 2.1 does not require that imports need to be increasing at the time of the determination. Rather, the plain meaning of the phrase 'is being imported in such increased quantities' suggests merely that imports must have increased, and that the relevant products continue 'being imported' in (such) increased quantities. We also do not believe that a decrease in imports at the end of the period of investigation would necessarily prevent an investigating authority from finding that, nevertheless, products continue to be imported 'in such increased quantities.'"* (para. 367)<sup>5</sup>.

196. The table below contains the import data for period under investigation i.e. from 2005-06 to 2010-11 (upto Dec.).

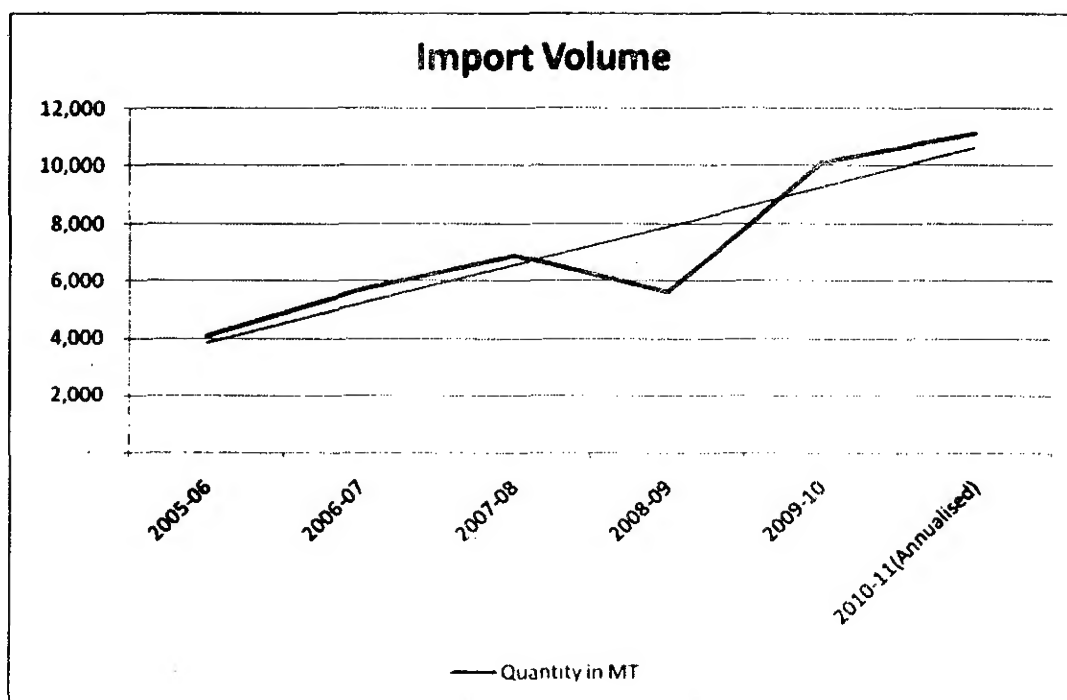
**TABLE-1**

Sl. No.	Financial Year	Quantity in MT	Increase in MT
1.	2005-06	4,077	
2.	2006-07	5,652	1,575
3.	2007-08	6,860	1,208
4.	2008-09	5,606	-1,254
5.	2009-10	10,090	4,483
6.	2010-11 (Annualised)	11,109	1,020
7.	2010-11 (Upto Dec. 2010)	8,332	

<sup>4</sup> WT/DS248/R DT. 11.07.2003 Panel Report in US-Steel Safeguard case

<sup>5</sup> WT/DS 248-54/AB/R & WT/DS 258-59/AB/R Appellate Body report in US- Steel Safeguard case.

	Overall increase since 2005-06	7,032	
--	--------------------------------	-------	--

**GRAPH-1**

197. The import data above shows that the import has increased by 172% in 2010-11(Annualised) with reference to the base year 2005-06. The increase in 2009-2010 with respect to 2008-09 was of 79% and in 2010-11 with respect to previous year was by 10%.

198. Intervening trend of imports: The imports increased by 39% in 06-07 compare to 05-06 and by 21% in 07-08 compare to preceding year. There was decrease in import by 18% in 2008-09 compare to 2007-08. The temporary decrease in f.y. 2008-09 was due to levy of Anti-dumping duty on imports from Korea and China, the main exporting countries of the PUI. The Table below contains data of Import of PUI from Korea and China.

**TABLE-2**

Financial Year	Import from China (in MT)	Import from Korea (in MT)
2006-07	1570	3336
2007-08	3287	3158
2008-09	1795	2980
2009-10	1831	6030
2010-11(upto Dec.)	1258	5328

199. The import of PUI from Korea and China were almost equal in 2007-08. The total import from Korea and China decreased by 26% in 2008-09 compare to 2007-08. The decrease from Korea was less than 5%. However there was sudden

and sharp surge of total import in 2009-10 compare to 2008-09 from 5606 MT to 10,090 MT (79.98%). The Korea accounted for 3050 MT and China only 36 MT in the said total increase of 4483 MT. The increase in import from Korea by 102% in F.Y. 2009-10 was despite of levy of Anti-dumping duty in F.Y. 2008-09. The increase continued in F.Y 2010-11(upto Dec.).

200. Relative increase in import-The import in relation to Indian production is as below :-

**TABLE-3**

Financial Year	Import in relation to production (Indexed)	Import in relation to production (in %)
2005-06	100	***
2006-07	153	***
2007-08	124	***
2008-09	100	***
2009-10	157	***
2010-11(upto Dec.) Annualised	207	***

201. The import has increased in relation to production and has reached maximum level in 2010-11. The import in relation to Indian production has increased by \*\*\*% from base year. The import in relation to production increased by \*\*\*% in 2009-10 compare to 2008-09 and \*\*\*% 2010-11 compare to 2009-10.
202. In view of above it is held that there was increase in import in absolute and relative term and that the increase in import was recent enough, sudden enough and sharp enough.

### Unforeseen Development

203. The Appellate Body in Argentina – Footwear (EC case) has held that the phrase Unforeseen Developments means the developments which were unexpected. ‘Unforeseen developments’ requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been ‘unexpected’. The Body in the same case noted a GATT panel report which held that the development must have been unforeseen at the time of tariff negotiation. The Appellate Body in Korea-Dairy case<sup>6</sup> held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation.
204. The Appellate Body, in Argentina — Footwear (EC), then held that the requirement of “unforeseen developments” did not establish a separate “condition” for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of “circumstances”:

<sup>6</sup> Para 86 of Korea Dairy case Appellate Body Report Of WTO

205. The panel on US- Steel Safeguards concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development:

“The United States argues that the robustness of the US dollar was a development which combined with the other developments, namely, the currency crises in Asia and the former USSR and the continued growth in steel demand in the United States’ market as other markets declined, lead to increased imports.”

206. The petitioner has pointed out two events which constitutes unforeseen development namely a) Special relationship between KKPC and Sinorgchem and (b) recession in the global market leading to significant drop in demand for the product in developed countries and China. The petitioner has submitted evidences for the same (refer para 22 to 27 of this findings).

207. It is noted that there is mention of special relationship with M/s Sinorgchem in the Annual Report of Korea Kumho for the year 2009 :

*—Our specialty chemicals business — the industry leader in 6PPD production capacity —saw sales decline and price fall as Chinese competitors pursued a low price strategy. Shortages in the 4-ADPA feedstock market and restrictions on our ability to enter the Chinese market due to our special relationship with feedstock supplier Sinorgchem resulted in a lower operation rate that further hurt profitability.□*

208. The ADD duty @ Rs. 42.70/kg and @Rs. 10.35/kg was imposed on the goods imported from China and Korea respectively in f.y 2008-2009<sup>7</sup>. The import data of Korea in the table below shows substantial increase in import of the 4ADPA, the penultimate stage intermediate for 6PPD from the same F.Y. i.e. 2008-09 onwards.

209. The unit price of import of 4ADPA from China to Korea came down from US\$3.54/kg in 2008-09 to US\$2.68/kg. in 2009-10 which is also the year of levy of ADD duty at higher rate on China . The table below contains import data of 4ADPA from China to Korea.

**TABLE-4**

Sl. No.	Financial Year	Quantity in MT	Rate in US\$/Kg
1	2005-06	10815	3.20
2	2006-07	11492	2.57
3	2007-08	15465	2.67
4	2008-09	23631	3.54
5	2009-10	23118	2.68
6.	2010-11(Upto Sep.)	13036	2.69

Source: Applicant from Korea Customs Data(KITA site)

210. The unit import price of 4ADPA in India from EU and China is given in the Table below. It is seen that the import price of 4ADPA into Korea from China is

<sup>7</sup> Notf.No. 133/2008 Cus. dt.12.12.2008 of Government of India

much less than import price of the same goods into India from China and EU. Further the increase in 4ADPA import from China into Korea was in the year of levy of ADD duty at higher rate on Chinese import into India i.e. in the year 2008-09.

**TABLE-5**

Sl. No.	Financial Year	Rate /Kg in US\$ from EU	Rate /Kg in US\$ from China
1	2006-07	3.09	2.85
2	2007-08	3.13	3.02
3	2008-09	3.83	3.88
4	2009-10	-	2.91
5	2010-11(Upto Sep.)	3.10	2.94

Source:IBIS data submitted by applicant.

211. It is seen that the capacity available with the KKPC is more than the demand in Korea. Despite of excess capacity, the said company has gone for expansion up to \*\*\* MT despite of the fact that the existing capacity was much higher than the total demand of Korea. The capacity was expanded for exports market and additional market opportunities will be the requirement of the said company to justify the investment made.
212. The table-2 in paragraph 198 of this finding contains import data of PUI from Korea and China into India. It is seen that after levy of ADD at higher rate on PUI imported from China, the imports from Korea increased by 3050MT (102%) and that from China decreased.
213. During the worldwide recession there was decrease in demand of tyre and tubes in rest of the world (mainly USA, EU and China) due to crash of Automobile Industry. However, from the data of Tyre and Tube Production in India<sup>8</sup> it is seen that even during the world wide recession, the production of tyre and tube were on increase in India. The data below shows continuous increase in production since 2005-06 to 2009-10. The increase in production compare to 2005-06 is by 62% in tyre and 52% in Tube. Consequently the demand of PX-13 increased tremendously in India as compared to the rest of the world leading to its increased imports into India.

**TABLE-6**

F. Y.	Tyre Production in 000 Nos.	Tube Production in 000 Nos.
2005-06	66032	53421
2006-07	73545	62376
2007-08	81103	70810
2008-09	82107	69733
2009-10	97137	81448

<sup>8</sup> Source : All India Tyre Manufacture Association website

214. The above developments are unexpected and changed the demand supply ratio and caused price difference between domestic and import goods leading to increase in imports.

### **Serious Injury and Threat of Serious Injury**

215. **Statutory framework:** "Serious injury" means an injury causing overall impairment in the position of a domestic industry;<sup>9</sup> and "threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.<sup>10</sup>

216. The panel in United States – Fresh Chilled or Frozen lamb Meat from Australia and New Zealand ruled that<sup>11</sup>:

*We note that in our view SG Article 4.1(b) and 4.2(a) do not require the competent national authority to show that each listed injury factor is declining, i.e., point in the direction of serious injury or threat thereof. The competent national Authority is required to make its determination in the light of the developments of injury factors on the whole in order to determine whether the relevant industry's condition is facing 'significant overall impairment' in the industry's condition is imminent. We agree with the Appellate Body's statement in Argentina-Footwear that :*

*" It is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in the light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is 'a significant overall impairment' in the position of the industry--- An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is 'declining'. In one case, for example, there may be significant decline in sale, employment and productivity that will show 'significant overall impairment' in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case the certain factor may not be declining but the overall picture nevertheless demonstrate 'significant overall impairment' of domestic industry.*

217. It is seen that -

The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular

<sup>9</sup> Section 8B(6)(c) of the Customs Tariff Act, 1975.

<sup>10</sup> Section 8B(6)(d) of the Customs Tariff Act, 1975.

<sup>11</sup> WT/DS177-178/R dt 21.12.2000 Para 7.203 of panel report in US- SG Measure on Fresh Chilled or Frozen Lamb Meat from New Zealand and Australia.

case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.<sup>12</sup>

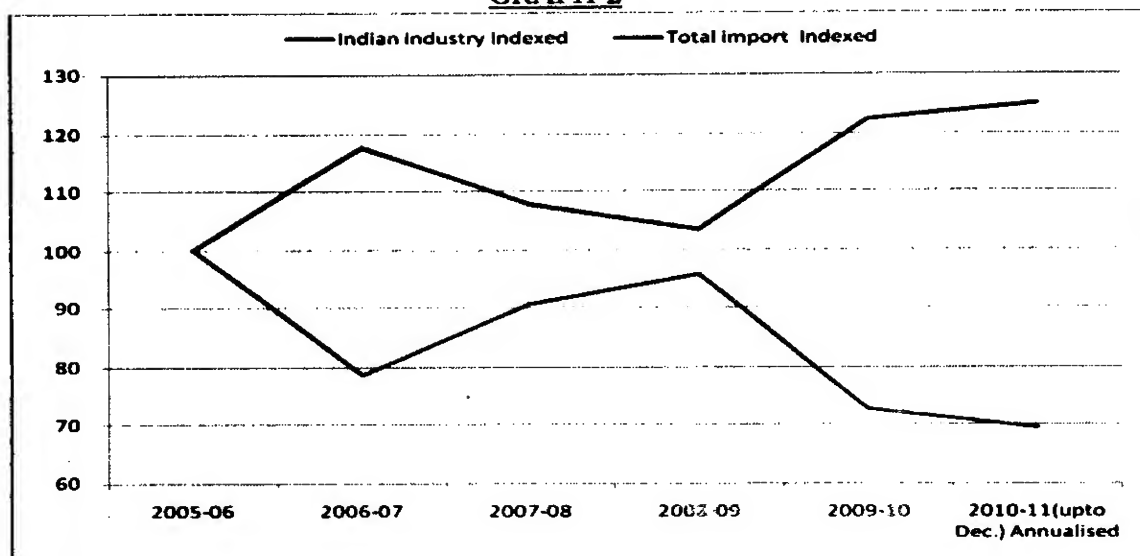
218. Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury, all factors which are mentioned in the rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition which are relevant to the affected industry have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the domestic industry, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

219. Market Share of Domestic industry taken by increased imports: The table contains the share of Indian industries and Imports in the Indian market:

**TABLE-7**

Financial Year	Share of Indian industry in total market size % (Indexed)	Share of import in total market size %	Share of DI in total market size in % (Indexed)
2005-06	100	54.92	100
2006-07	79	64.57	60
2007-08	91	59.19	62
2008-09	96	56.83	70
2009-10	73	67.21	69
2010-11(upto Dec.) Annualised	69	68.92	66

<sup>12</sup> Based on Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report Of WTO

**GRAPH-2**

220. The table above shows that the share of Indian Industry is decreasing and that of import is increasing except in F.Y. 2008-09 when ADD was imposed on imports from Korea and China. The share of Indian Industry has come down by \*\*% compare to base year and \*\*% compare to 2008-09. The Indian industry lost major share in 2009-10 and 2010-11 when there was steep increase in import. The applicant domestic industry has lost \*\*% share compare to base year of \*\*% and has come down to \*\*% in 2010-11.

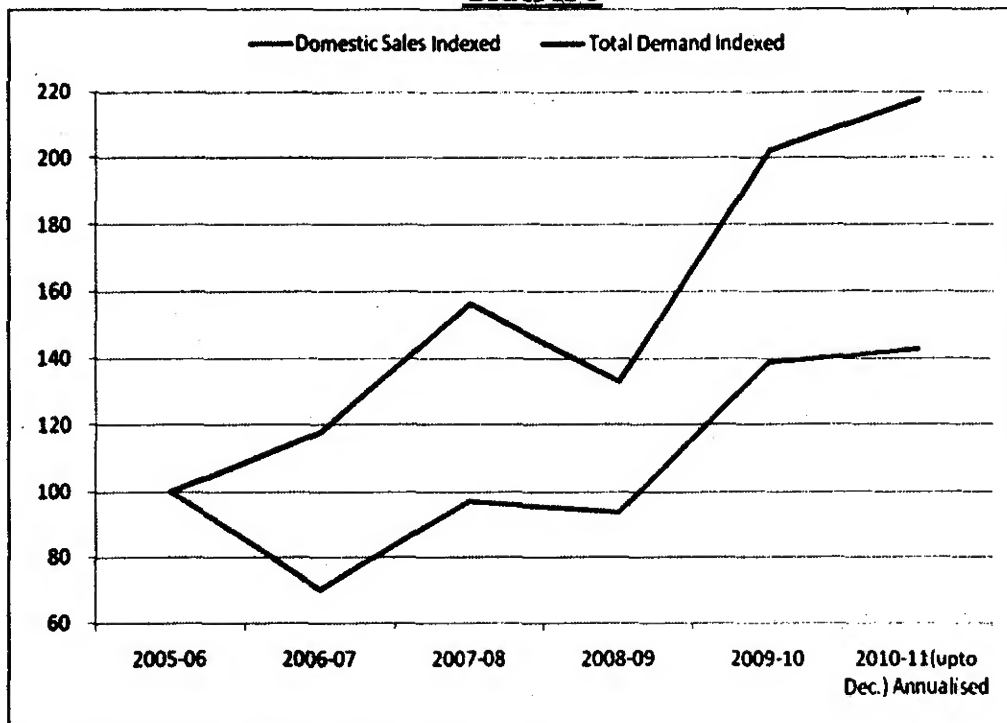
221. The loss of market share is attributed to increased imports.

222. The table below contains sales by domestic industry, total demand and Sales as a percentage of demand.

**TABLE-8**

Financial Year	Sales by DI	Total Demand	Indexed
			Sales as % of demand
2005-06	100	100	100
2006-07	70	118	60
2007-08	97	156	62
2008-09	93	133	70
2009-10	139	202	69
2010-11 (upto Dec.) Annualised	143	217	66



**GRAPH-3**

223. The demand of PUI has increased since 2005-06 but the sales of DI decreased. However with the imposition of ADD in 2008-09 the sales of DI started increasing in 2009-10 and 2010-11. The increase in sale is not in proportion to increase in domestic demand which was taken by increased imports after 2008-09.

224. The table below shows the landed price of import with ADD, the DI selling price and the DI export price.

**TABLE-9**

Financial Year	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11 (Upto Dec.)
Landed price of imports with ADD (Rs./Kg.)	229.73	192.66	147.02	247.29	192.59	189.84
DI Domestic Selling price (Indexed)	100	90	82	113	103	103
DI export price(Indexed)	100	90	79	110	93	89

225. The data in the table above shows that the imports after 2008-09 were taking place much below the DI domestic sale price and even below the DI export price. It is concluded that the low price increased imports has affected the sale of domestic industry despite of high domestic demand.

226. Production:- The table below shows the production of the PUI on yearly basis.

**TABLE-10**

Sl. No.	Financial Year	Indexed	
		Production Capacity(MT)	Production in MT
1	2005-06	100	100
2	2006-07	104	91
3	2007-08	140	136
4	2008-09	140	138
5	2009-10	149	158
6	2010-11(upto Dec.) Annualised	149	131

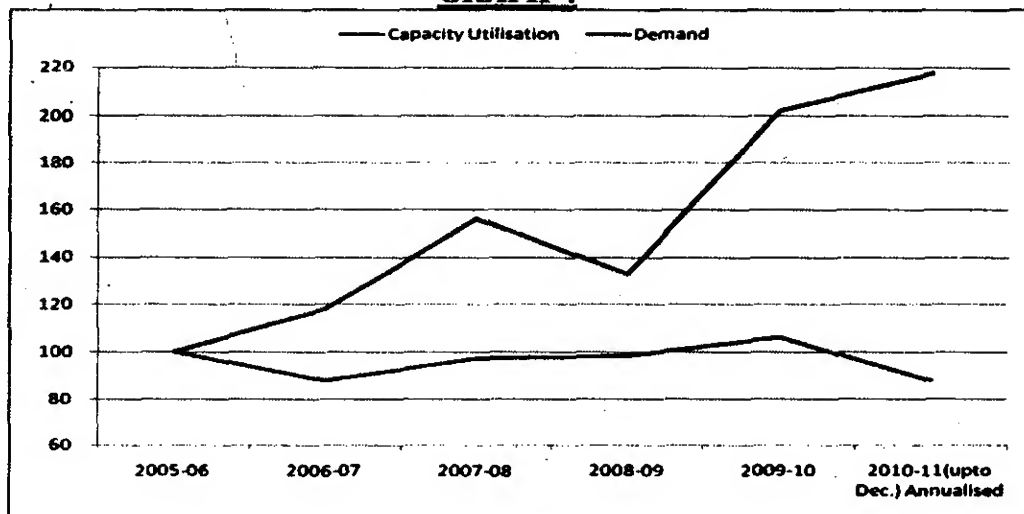
227. The production of DI decreased in 2006-07 with respect to previous year. Thereafter the DI increased its capacity with increase in demand of PUI in domestic market from \*\*\*MT to \*\*\*MT in 2009-10. However, the production of DI was not up to its capacity despite of high increase in demand. With continuous increase in import the production decreased by \*\*% in 2010-11 compared to 2009-10.

228. The table below shows the capacity utilisation of PUI with reference to demand in the domestic market.

**TABLE-11**

Financial Year	Capacity Utilisation in % (Indexed)	Demand in MT
2005-06	100	7,424
2006-07	88	8,753
2007-08	97	11,590
2008-09	98	9,864
2009-10	106	15,011
2010-11(upto Dec.) Annualised	88	16,117

229. The capacity utilisation of DI has decreased by \*\*% from base year and by \*\*% from 2009-10 in the 2010-11 despite of increase in demand by \*\*%. The capacity utilisation of DI is showing downward trend. The decrease in capacity utilization despite of increase in demand is due to increased imports.

**GRAPH-4**

230. The table below contains data of the production hour lost by the Domestic Industry. It is seen that the DI is not able to utilise its production capacity and the loss of production is maximum in 2010-11.

**TABLE-12**

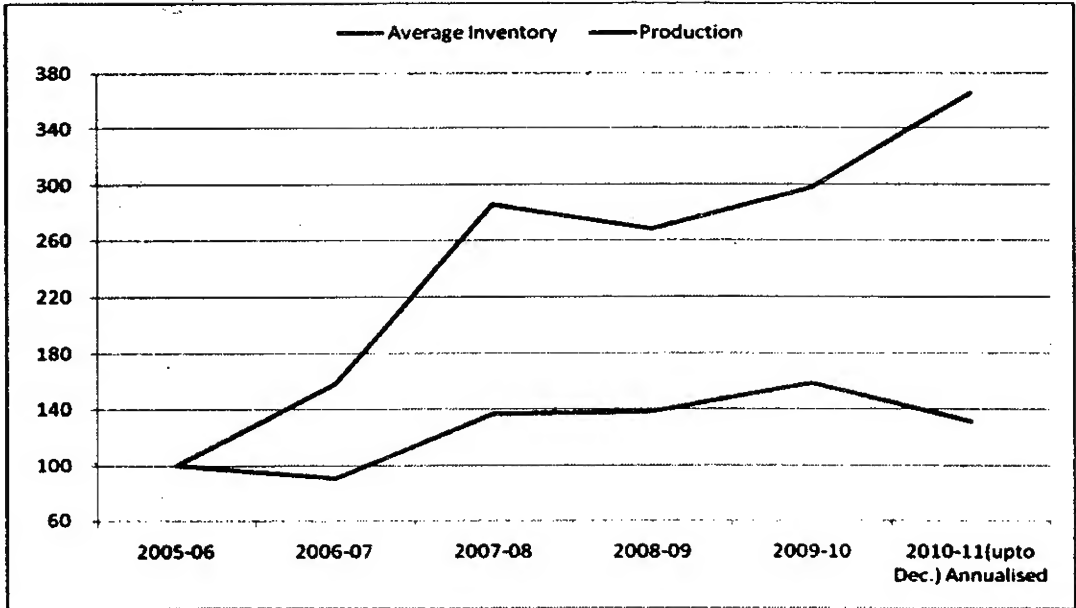
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Production Hour lost	100	780	297	947
Production lost in MT	100	780	297	948

231. Inventory: The table below contains the average inventory on yearly basis. Further the graph below is plotted taking the yearly average inventory and yearly production data in Indexed form.

**TABLE-13**

Sl. No.	Financial Year	Indexed	
		Average Inventory	Production
1	2005-06	100	100
2	2006-07	157	91
3	2007-08	286	136
4	2008-09	268	138
5	2009-10	298	158
6	2010-11 (upto Dec.) Annualised	365	131

GRAPH-5



232. The table above shows that the inventory of Domestic Industry is increasing since 2005-06. The inventory continued to increase in 2009-10 and 2010-11. The inventory increased by \*\*% in 2010-11 compared to 2009-10 when there was decrease in production by \*\*% in the same period.

233. The increase in inventory is attributed to increased imports at low price.

234. **Effect of Price:** The argument has been raised that price is not a relevant factor for consideration in safeguard investigation. At what price the imports are entering is not the relevant factor because it is not the unfair competition which is the subject matter of safeguard action but it is the competition per se offered by the increased imports to the domestic producers, even if it is at fair price. Only in this context the import price is not relevant. However when it comes to determination of serious injury or market disruption or threat thereof, the law requires an examination of change in level of sales, profitability etc. of the domestic producers. These factors undoubtedly depend on the prices of competing products and in that context import price do become relevant and require examination particularly to assess their affect on domestic situation and also the reason for increase in import.

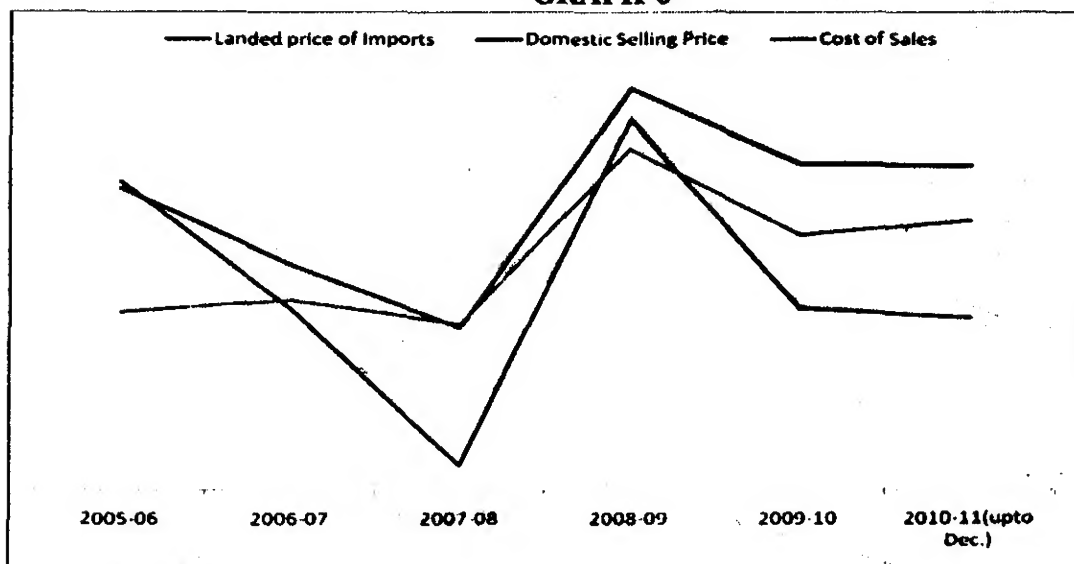
235. The table below contains landed price of import with ADD duty, selling price of Domestic Industry and the cost of sale of Domestic Industry.

TABLE-14

Sl. No.	Financial Year	CIF Price of Import	Landed price of imports with ADD	Selling Price of DI (Indexed)	Cost of Sales of DI (Indexed)

1.	2005-06	198.98	229.73	100	100
2.	2006-07	167.28	192.66	90	102
3.	2007-08	135.55	147.02	82	98
4.	2008-09	205.66	247.29	113	125
5.	2009-10	162.14	192.59	103	112
6.	2010-11(upto Dec.)	161.98	189.84	103	114

GRAPH-6



236. The annual average landing price of import with ADD (on imports from EU and Taiwan only) showed declining trend since 2005-06. There was correction of landed price of import with ADD after levy of Anti-dumping duty on imports from Korea and China. However, the price further deteriorated and came down below the 2005-06 and 2006-07 level in 2009-10 and 2010-11. This led to reduction in price of the domestic producers from 2009-10 onwards.

237. The continuous depression in domestic sale price is indicator of injury being suffered by domestic industry as it result in loss of market share to imports. Imports are causing significant price undercutting despite current Anti-dumping duties.

238. The cost of sale increased by Rs.\*\*\*/Kg from 2005-06 to 2009-10 and the selling price of DI increased by only Rs. \*\*\*/Kg but the CIF import price dropped by Rs. 36.85/Kg and landed price of import with ADD by Rs. 37.14/Kg. Further in the current year 2010-11 the cost rose by Rs. \*\*\*/kg compare to 2005-06 but the selling price increased by only Rs.\*\*\*/kg and the CIF import price declined by Rs. 37/kg and landed price of import with ADD by Rs. 39.89/kg. Due to increased import at low price the DI is not able to increase its domestic selling price in proportion to increase in cost.

239. The difference between import price and domestic selling price is too high making the imports lucrative and posing continued threat of increased import.

240. Profit / Loss: The table below contains the profit/ loss and ROCE.

**TABLE-15**

Financial Year	Profit/loss in Rs.Kg	ROCE in %
2005-06	100	100
2006-07	29	20
2007-08	(3)	(1)
2008-09	49	47
2009-10	57	53
2010-11 (upto Dec.)	45	39

241. The profitability of domestic industry dropped steadily till 2007-08. It improved thereafter with imposition of Anti-dumping duty in 2008-09 when imports came down. However the same started deteriorating after that and the profit in F.Y. 2010-11 has declined further compared to 2009-10 and has reached below 2008-09 level. The domestic industry is not able to regain their profit margin of 2005-06.

242. The ROCE has declined upto 2007-08 and increased thereafter. However the same further declined by \*\*\*% in 2010-11 compared to 2009-10.

243. The increasing price difference between the import and domestic selling price is reducing the profitability of the domestic industry.

244. Significant Global Surplus Capacity : The domestic industry submitted following figures for the capacity in excess of demand, available with the foreign suppliers which is causing increased imports at low price into India causing serious injury/threat to serious injury to the domestic manufacturers.

All figures are in MT

TABLE-16

SN	Country	Producer	Capacity in MT	Domestic Demand	Surplus
1	Korea	Korea Kumho (KKPC)	70,000	8,000	62,000
2	China	Sinorgchem	120,000	-	-
		Nanjing Chemicals	30,000	-	-
		Tongling Xenda	10,000	-	-
		Northeast Aux	10,000	-	-
		Shangyu Lixing	2,000	-	-
		Jiangsu Donglong	8,000	-	-
		China Sunsine	15,000	-	-
	Total China		195,000	90,000	105,000
3	EU Region	Flexsys	65,000	-	-
		Lanxess	38,000	-	-
		Dussio	18,000	-	-
	Total EU		123,000	32,000	91,000
4	Japan	Sumitomo	10,000	17,000	-7,000
5	India		11,500	14,500	-3,000
6	Rest of World		NIL	87,000	-
7	Total world		407,500	248,500	159,000
8	Indian demand				14,500
9	World surplus as a % of Indian demand				1097%

245. The examination of the data submitted by the interested parties shows that there is significant capacity in excess of demand with the Korean and Chinese supplier. Further the Korean supplier increased its capacity from \*\*\*MT to \*\*\*MT in 2009-10 despite of the fact that it was operating at less than its capacity and the total demand in Korea is much less than the existing capacity. The excess unutilized capacity with foreign supplier is the reason for tapping or creating additional market for their product at price lower than the prevailing price of that additional market. This poses threat to the Domestic Industry in India.

246. The clause 6(d) of section 8(B) of the Custom Tariff Act, 1975 defines 'threat of Serious Injury' to mean a clear and imminent danger of serious injury. The examination of various parameters above also shows that the DI is affected by adverse condition since 2009-10 compared to preceding year and the same further deteriorated in 2010-11. The applicant industry has lost on account of production, capacity utilization, Increase inventory, Sales realization, Profit, ROCE in 2010-

11 compared to 2009-10. The marginal growth in sale is much less compare to increase in domestic demand. Further the exportes have huge unutilized capacities of the PUI. It is therefore observed that DI is also suffering from threat to serious injury.

### **Other Factor**

247. **Export:** Some of the interested parties have contended that the DI Exports more than 50% of production and the fall of export volume in export in 2010-11 could be the possible cause of injury to the domestic industry. The table below contains the landed price of import with ADD, Export Price and the domestic selling price.

**TABLE-17**

Financial Year	Landed price of import with ADD (Rs. Kg)	Export Price (Indexed)	Domestic Selling price (Indexed)
2005-06	229.73	100	100
2006-07	192.66	90	90
2007-08	147.02	79	82
2008-09	247.29	110	113
2009-10	192.59	93	103
2010-11 (upto Dec.)	189.84	89	103

248. The data in table above shows that the export price of DI is always less than the Domestic selling price. The domestic industry has to export the goods despite of sound domestic demand at the price much higher than the export price. In view of this the export is not profitable option for the DI. The DI has to export to minimize losses. Hence it can not be said that the export is priority for DI. Further no evidence has been brought on record to show that DI has refused domestic supply for export by the User industry in India.

249. However, in the injury analysis, impact of export activities have been excluded. The factors such as domestic sales volumes, market share, domestic selling prices, profits, etc do not have anything to do with export performance. Further it has been seen that production net of exports shows decline in 2010-11 and further increase in production upto 2009-10 was much less than the increase in demand. Therefore, while conducting the injury analysis, adequate care has been taken to exclude the impact of export activities and hence, it is held that export performance was not a cause of injury to the domestic producers.



250. Demand of PX-13 and capacity of Indian producers to meet domestic demand: Some of the interested parties have claimed that the cause of injury to the DI was not increased import as the imports were necessitated to meet the gap between domestic supply and the domestic demand. The domestic industry has claimed that they have enough capacity to meet the domestic demand after excluding the duty free imports of PUI under Advance Licence scheme. They have contended that the major share of increase in demand is taken by increased imports and they have to export the PUI at a price lower than the domestic selling price to minimize losses. The DI has submitted following data in support of their claim.

Capacity, Quantity in MT **TABLE-18**

Items	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
NOCIL Capacity	***	***	***	***	***	***	***	***	***
NOCIL New Capacities	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Inventory/opening stock	***	***	***	***	***	***	***	***	***
MERCHEM Capacity	***	***	***	***	***	***	***	***	***
PMC Capacity	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Lanxes Capacity	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Duty Free Import	1734	1916	1867	1761	3069	2373	2741	3289	3947
Total availability	11568	11689	14236	14158	15867	15848	19228	28419	38831
Demand	7424	8753	11095	10053	14572	15691	18123	22110	26974
Surplus/Shortfall	4144	2936	3141	4105	1295	157	1105	6309	11857

Source:- Submission of applicants.

251. The DI has submitted the figures in above table on the basis of their expansion plan at Dahej which has been submitted with the adjustment plan; maximum inventory as on date supported by Cost accountant certificate; capacity of other Indian producer as per market source and Tyre export data for calculating duty free import of PUI under Advance License scheme. The applicant submitted supporting documents/certificates including transaction wise data of Tyre export, sourced from Export-Import databank of Department of Commerce, for calculation of import of PX-13 under ALS. Further the applicant submitted that they have no sale for Deemed Export as is evident from their ER-1 of production.
252. The above submission of applicant in support of their demand supply gap was placed in public file as per Rule 6(7) of Safeguard Rules 1997 for comments if any by other interested parties. The User/ Importers contended that if the import under ALS is excluded for assessing demand supply gap than the same should also be excluded from the assessment of increased imports. The user industry did not question the correctness of duty free import quantity of PUI submitted by applicant. The User industry requested to ascertain actual capacity of Lanxes and whether they are manufacturing PUI and not to make finding on import data of

intermediate i.e. 4 ADPA. The same has been ascertained from the Central Excise.

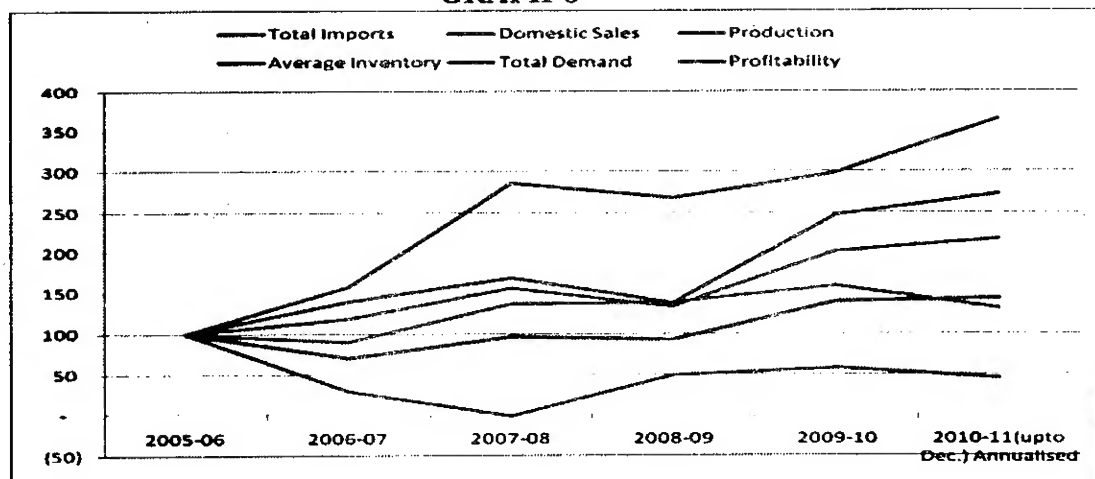
253. It is seen from the submission above that there is no demand-supply gap if imports under ALS is deducted from domestic demand. Further, if as per the claim of User Industry, the given figure of Import under ALS is deducted from total imports, the year wise import will be 2005-06=2343MT; 2006-07=3736MT; 2007-08=4993MT, 2008-09=3845MT; 2009-10=7021MT and 2010-11= 8736MT. It shows increase in import even after deduction of duty free import under ALS.
254. Though the DI claims that the Export of Tyres are under Advance Licence Scheme, transaction wise export data of Tyre submitted by them does not contain the export promotion scheme under which the export has taken place. Further the ALS holder has the choice to import raw material duty free or procure the same from domestic market under Advance Release Order. It may not be correct to exclude the submitted data of import under ALS to determine overall demand. However, once the Safeguard duty is imposed the duty free import under ALS shall have no competition with the domestic sale.
255. The Capacity with all Indian producers was \*\*\*MT, \*\*\*MT, \*\*\*MT, and \*\*\*MT against the domestic demand of 7424 MT, 8753 MT, 11590 MT and 9864MT in 2005-06, 06-07, 07-08 and 2008-09 respectively. The applicant domestic Industry have achieved capacity more than \*\*\*% and other Indian Industry have achieved even \*\*\*% and above utilization. From the above it is clear that the available capacity with Indian Industry was more than domestic demand between 2005-06 to 2008-09. However the import increased in this period and the DI has to export the goods at price below the domestic sale price.
256. The capacity with Indian industries in F.Y. 2009-10 and 2010-11 (upto Dec. annualized) was \*\*\*MT and \*\*\*MT. The domestic demand in above mentioned years were 15011 MT and 16117 MT. The available capacity with Indian industry was less than domestic demand in the above mentioned two years. However the domestic demand suddenly rose by 45% in 2009-10 whereas the average yearly rise in demand is 22% per year only. The DI and other producers have achieved more than \*\*% of utilization and are capable to produce almost equal to the capacity. But the DI failed to achieve capacity due to import at low advantageous price which has taken major share of the domestic demand. In the same period, due to increased imports the average inventory of the applicant rose to \*\*\*MT and \*\*\*MT. Further in 2009-10 the share of import in domestic demand has increased from 55.77% to 69.02% compared to preceding year 2008-09. The DI was not able to sell in domestic market and forced to export the PUI at a price less than the domestic selling price.
257. In a situation where there is alleged demand supply gap in country the domestic industry would not have resorted to significant export that too at a price lower than the domestic sale price. The domestic industry is unable to sell its product in domestic market due to increased import. No evidence/allegation has been brought on record that consumer demanded material from DI and supplies were not made.

258. The domestic industry has significant unutilized capacities and the utilization has gone down to \*\*% in 2010-11 despite of high demand. The DI is facing increased average inventory from \*\*\*MT in 2008-09, \*\*\*MT in 2009-10 and \*\*\*MT in 2010-11. In the event of demand supply gap the DI would not have faced such situation. The fact that domestic industry has to export at price less than domestic sale price shows that the increase in import is not due to demand supply gap.
259. The Indian industry has sufficient capacity to meet the present domestic demand and the expansion plan which are under advance stage of implementation is sufficient to meet the future domestic demand. The increase in import is not due to domestic demand-supply gap.
260. Imposition of Safeguard duty when anti-dumping duty is already in operation: The issue whether Safeguard Duty can be imposed when Anti dumping duty is already in place was examined. Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Anti dumping Duty not exceeding the margin of dumping. Section 8B deals with imposition of Safeguard duty in certain circumstances. This circumstances under which the two duties can be imposed are different. Further, the sub section (3) of Section 8B envisages imposition of a number of duties at the same time under the Customs Tariff Act, 1975 or under any other law for the time being in force. The sub section 3 reads as
- “the duty chargeable under this section shall be in addition to any other duty imposed under this Act or under any other law for the time being in force.”***
261. Accordingly, there is no bar imposed by law on imposition of Safeguard Duty when Anti dumping duty is already in place.
262. However there have been various submissions from interested parties, who have submitted against imposition of both antidumping and safeguard duty together. They have also submitted that imposition of ADD and Safeguard duties at the same time is not in public interest. The issue has been analysed. The antidumping duty is a trade remedy measure to counter and neutralise the ill effects of dumped imports through raising tariff barrier. Safeguard duty is a measure to protect the domestic industry from injurious effects of increased imports by raising tariff barrier. Both the duties have one function in common i.e. neutralising injurious effect of imports, besides other functions. Therefore it is imperative that the safeguard duty may be imposed and continued only when the existing trade remedies measures, in whatever form, are not able to protect the domestic industry. It is also implied that the multiple protection is available only to the extent it is necessary.
263. In the instant case it is a fact that imports increased with faster rate even after imposition of ADD in F.Y. 2008-09 . The increase in import at low price caused and threatened to cause serious injury.
264. The analysis done in earlier paragraphs show that the special relationship between Korean and Chinese exporter coupled with high demand of PUI in India

at time when the demand went down in larger markets of USA, EU and China was responsible for increased imports. The existing tariff barrier, which included anti-dumping duty, was not sufficient enough to prevent permeation of imports in large quantity. Therefore, multiple trade remedy measures are justified to neutralize the injurious effects of imports. However, the prudence in use of multiple trade remedy measures requires that it is limited to the period and extent which is necessary, so that the placing of burden of safeguard duty on end users is justified.

### Causal Link

**GRAPH-8**



265. The performance of domestic industry shows that despite of increase in demand of the PUI the market share of DI has decreased and that of import has increased.

266. The difference between the landed price of import and the domestic selling price is significant and is increasing over the year since 2005-06.

**TABLE-19**

F.Y.	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11 (upto Dec) Annualised
Price difference between import and Domestic sales (Indexed)	100	648	2020	456	2114	2228
Volume of Import in MT	4077	5652	6860	5606	10090	11109

267. It is noted that the price difference and volume of import declined in 2008-09 (when ADD was imposed). The price difference increased thereafter and imports surged further. The increase in import is in tandem with price difference between import price and domestic selling price.

268. The significant price difference caused price undercutting despite of ADD. Consequently even when sales of DI increased, it was far less than increase in

demand. This caused decline in the market share of domestic industry. The decline in the market share of DI is therefore because of increase in imports.

269. Less than market increase in the sales volume of domestic industry resulted in production of domestic industry suffering adversely. The production started declining in 2010-11 which is further evidenced by production hour lost and increase in inventory. The adverse performance on account of production is due to increased imports.
270. The market share of DI decreased and imports increased. Consequently, inventories with domestic industry increased. Despite of increase in production the increase in inventory is because of increased imports.
271. The imports are significantly undercutting the prices of domestic industry. The DI is unable to regulate its prices in accordance with the changes in cost of production. The profitability of DI is not returning back to the earlier level despite of ADD which is due to increased imports.
272. The fall in capacity utilization, production, profit, profitability coincide with the increase in imports. It is the increased import at lower price which caused depression in prices in India leading to loss of profitability and profit. The increased import alone caused loss of market share. The increase in import is the cause of increase in inventory of the DI. The growth of demand in Indian market has been taken by the increased imports.
273. The increase in import is the cause of serious injury and threat to serious injury to the Domestic Industry.
274. Adjustment Plan: It has been argued that the domestic industry has not submitted viable adjustment plan to meet the international competition. The petitioner submitted adjustment plan with the application and subsequent written submissions (para 33 to 38 of the findings).
275. It is seen that Panel in Korea- Dairy case has rejected the view that Art. 5.1 imposes obligation to consider the adjustment plan (reference to be given).

*—We wish to make it clear that we do not interpret Article 5.1 as requiring the consideration of an adjustment plan by the authorities ... The Panel finds no specific requirement that an adjustment plan as such must be requested and considered in the text of the Agreement on Safeguards. Although there are references to industry adjustment in two of its provisions, **nothing in the text of the Agreement on Safeguards suggests that consideration of a specific adjustment plan is required before a measure can be adopted.** Rather, we believe that the question of adjustment, along with the question of preventing or remedying serious injury, must be a part of the authorities' reasoned explanation of the measure it has chosen to apply.*

*Nonetheless, we note that examination of an adjustment plan, within the context of the application of a safeguard measure, would be strong evidence that the authorities considered whether the measure was commensurate with the objective of preventing or remedying serious injury and facilitating adjustment.*□

276. The Rule 5(2) of Safeguard Rules 1997 requires submission of a statement on *"efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition"*. The WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.
277. The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. In this regard attention is invited towards Section 8 B (4) of CTA 75 and Rule 16(2) of Safeguard Rules 1997 which prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.
278. The restructuring plan submitted by the DI focuses on capacity expansion to cater the growing demand and cost reduction.
279. The petitioner has submitted that they are expanding the capacity of production to face fair competition from imports. The expanded capacity of DI along with the capacity of other Indian producers will be enough to meet the growing demand of the product along with imports. The applicant DI is expanding capacity by \*\*\*MT at a cost of Rs. \*\*\*Crores. An amount of Rs. \*\*\*Crore has been committed as on 30.04.2011. Out of the said amount Rs. \*\*\*Crore has already been spent. The expansion work is likely to be submitted in March 2012 and production is likely to be started from April 2012.
280. The applicant has claimed that the expansion would result in minimum cost saving of Rs. \*\*\*/Kg. Further the DI is hopeful of cost reduction on account of overhead cost once it is able to sell more in the market.
281. The details of the restructuring plan were called. It is seen that the claim of DI is well supported by Chartered Engineer Certificate on expansion and expenditure for new plant and practicing Cost Accountant Certificate on the cost incurred and the claim of cost reduction. It is noted that the Adjustment plan of company is reasonable and feasible.
282. The adjustment plan has been taken into account for gradual liberalisation of duties.

#### **Public interest**

283. It has been contended by the interested parties that the safeguard measure on PUI is not in public interest. However evidence to substantiate the same was not submitted by any of the interested parties.

284. The Applicants have submitted that the share of PX-13 in the tyre industry ranges between 0.71% to 1.11% and on non tyre segment is 0.5%. The fact has not been disputed by the ATMA, representing Tyre manufacturer in the current investigation and All India Rubber Manufacturer Association (name to be checked).
285. Considering the above share and the insignificant cost of PX-13 it is noted that there will be no or very minimal impact of Safeguard duty on price of tyre and on the non tyre segment.
286. The applicant and one other domestic industry have undertaken expansion of their capacities and substantial progress has already been made as discussed in para 279 of this finding. The applicant alone will have an employment of more than \*\*\* persons. Further significant part of investment has come from financial institution. The employment and public finance are at risk if the Indian manufacturers are not given adequate protection from increased imports.
287. Further besides the applicant domestic industry, all other Indian producers are dependent on foreign producers for the penultimate intermediate 4ADPA for production of PUI. In the event of closing down of the applicant industry, there is no guarantee of timely getting 4ADPA at competitive price by other Indian producers. Hence the survival of applicant domestic producers is in the interest of the consumers. Further, the employment of more than \*\*\* persons presently working with the applicant is also at risk.
288. The safeguard duty which would enable domestic industry to survive in the face of competition offered by increased imports is also in long term public interest of buyers of PUI as well as buyers of products manufactured therefrom. It is therefore considered that imposition of safeguard duty on PUI will be in Public interest.

### **Developing Nation**

289. The percentage of imports from developing nations has also been examined. Except China who constitute 18.14% in 2009-10 and 15.09% in 2010-11 of total imports into India in F.Y. 09-10 and 2010-11 respectively, other developing nations individually have less than 3% of total imports in India. Therefore, the import of product under consideration originating from developing nations except China may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.
290. In view of the findings above, the final determination is that the increased imports of N 1,3-dimethyl butyl-N'Phenylenediamine (PX-13 or 6PPD) into India have caused serious injury and also threatened to cause serious injury to the domestic producers of N 1,3-dimethyl butyl-N'Phenylenediamine (PX-13 or 6PPD). In arriving at the amount of safeguard duty which would be adequate to prevent serious injury and threat of serious injury to the domestic industry and to facilitate positive adjustment, weighted average cost of sales at reasonable return on employed capital and average landed cost of import (taking basic customs

duty, cess) have been considered. The Antidumping duty on the PUI has also been considered while arriving at the amount of Safeguard duty. Further, the calculated safeguard duty has been moderated downward to allow imports to maintain competition in domestic market in the interest of end users and consumers. The public interest has also been considered in detail.

291. Considering the need to progressively liberalise the safeguard duty in order to facilitate positive adjustment by the domestic industry, it is recommended that safeguard duty be imposed on imports of N 1,3-dimethyl butyl-N'Phenylenediamine (PX-13 or 6PPD also known as 6C, Pilflex 13, Sirantox 4020, Anti-oxidant 4020, Kumhonax 13, Vulconax 4020) falling under subheading 3810, 3812, as well as under 2921, 2925, 2934 and 2942 (at six digit levels) of the Customs Tariff Act 1975 at the rates specified below on ad-valorem basis for a period of two years being the minimum requirement to protect the domestic industry from serious injury and threat to serious injury

Sl. No.	Period	Safeguard Duty
1	First Year	30%% minus Antidumping Duty Payable
2	Second Year	25% % minus Antidumping Duty Payable

292. As the imports from developing nations except China do not exceed 3% individually, the import of product under consideration originating from developing nations except China may not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

[F.No.D-22011/32/2010]

I. D. MAJUMDER, Director General (Safeguards)